15 अप्रैल, 2020 40 रुपए

इंडिया टुडे

MAGAZINE KING

महामारी से मुकाबला

कोरोना से जिंदगी भी खतरे में है और अर्थव्यवस्था भी.
इस दोहरी जंग में भारत को क्या करना चाहिए

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
RNI NO. 45823/86 REGISTERED NO. FARIDABAD/46/2020-22; DL(ND)-11/6042/2018-20; U(C)-31/2018-20
www.indiatodayhindi.in
OC

प्रधान संपादक की कलम से

दुनिया का हर देश नॉवेल कोरोना वायरस से अपने तरीके से लड़ रहा है. महामारी विशेषज्ञ कंप्यूटर मॉडल तैयार कर रहे हैं कि यह संक्रमण कैसे फैलेगा और कितने लोग मरेंगे. वैज्ञानिक इस वायरस की प्रकृति को समझने में जुटे हुए हैं. देश एक-दूसरे की ओर देख रहे हैं कि कौन कितनी कामयाबी हासिल कर पाया और मृत्यु तथा आर्थिक तबाही की रोकथाम के लिए कौन-सा मॉडल अपनाया जाए. जैसा कि बेहद समझदार सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालकृष्णन ने कहा, ''दरअसल, यह हर देश की स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता, सुशासन के स्तर और सामाजिक पूंजी की अग्निपरीक्षा है. अगर इस तिकड़ी में एक भी कमजोर है तो उसकी कलई बेरहमी से खुल जाएगी.'' जाहिर है, भारत की बराबरी सिंगापुर से नहीं की जा सकती लेकिन उनकी बातों में दम है. भारत कई वजहों से एकदम अलग है.1.3 अरब आबादी के साथ यह दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश है और प्रति वर्ग किलोमीटर में 420 लोगों की रिहाइश के साथ सबसे सघन आबादी वाला 31वां देश है. हम गरीब देश हैं और क्रय-शक्ति के मामले में चीन के 19,503 डॉलर के मुकाबले हमारी प्रति व्यक्ति आय 8,378 डॉलर है. अक्तूबर 2019 की आइएमएफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 191 देशों की सूची में 124वें स्थान पर है. यह हमारे आम इन्फ्रास्ट्रक्चर और खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं की खस्ताहाली से भी जाहिर होता है. हर भारतीय अपनी निठल्ली अफसरशाही और क्षुद्र स्वार्थों में लिपटे नेताओं से बखूबी वाकिफ है. हालांकि हाल के वर्षों में काफी सुधार आया है, हमें अब भी जवाबदेह और कारगर सरकार के लिए लंबा सफर तय करना है. देश की सामाजिक पूंजी का मतलब होता है उसके समाज का सरकार पर कितना भरोसा है. इसका खौफनाक नजारा तब दिखा जब लाखों गरीब शहरी प्रवासियों ने लॉकडाउन के आदेशों को धता बताकर अपने गांवों की ओर कूच कर दिया. ग्रामीण भारत भी भारी परेशानी में है. वह भी जैसे ठप है क्योंकि कृषि से जुड़े 20.5 करोड़ लोग अपनी फसल की कटाई की बाट जोह रहे हैं और कुछ मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं.

बेशक, आजाद प्रेस के साथ लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत इस संकट से निबटने में अधिनायकवादी चीन की तरह बहुत कुछ नहीं कर सकता. इसके अलावा, चीन में संक्रमित लोगों और मरने वालों की वास्तविक संख्या के बारे में कोई भरोसे से नहीं कह सकता. हम आंख मूंदकर विकसित देशों के नक्शेकदम पर भी नहीं चल सकते क्योंकि उनके यहां बेरोजगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लाभ और संतोषजनक स्वास्थ्य सुविधाओं का तंत्र है. भारत में ढेरों लोग हाशिए पर जीवन-यापन करते हैं. यहां 26 करोड़ मजदूर सेवा क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य कारोबार जैसे गैर-कृषि कार्यों में लगे हैं. इनमें से अनुमानित 13.6 करोड़ लोगों को लॉकडाउन ने जोखिम में डाल दिया क्योंकि ये अपना छोटा-मोटा धंधा करते हैं या फिर गैर-पंजीकृत छोटे व्यवसायों या पंजीकृत छोटी-मोटी कंपनियों में बगैर किसी लिखित करार के अस्थायी मजदूर के तौर पर काम करते हैं.

भारत में 2 अप्रैल तक संक्रमण के 2,015 मामले और 53 मौतों का आंकड़ा दुनिया भर में करीब 10 लाख संक्रमण के मामले और 50,000 मौतों के मुकाबले बेहद थोड़ा ही है. लेकिन ये आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं. महामारी के प्रकोप के चार हफ्ते बाद भी हमारी जांच की दर दुनिया में सबसे कम है—प्रति दस लाख आबादी पर 32 जांच जबकि चीन में यह आंकड़ा 2,820 है. दरअसल, इस आपदा के प्रति हमारा रवैया ढीलाढाला है. इसका खुलासा इस तथ्य से भी हुआ कि हाल ही में नई दिल्ली में तबलीगी जमात के जमावड़े में एक ही जगह पर कोविड-19 संक्रमण के मामले पूरे दक्षिण एशिया में सबसे अधिक मिले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी की रोकथाम के लिए सरकारी कोशिशों में तेजी लाने के लिए 11 अधिकारसंपन्न समूहों का गठन किया है. जाहिर है, गहन चिकित्सा के उपकरणों से लेकर सुरक्षात्मक पहनावे समेत स्वास्थ्य क्षेत्र की सीमित क्षमता के मद्देनजर सरकार अपने संसाधन बड़ी आपातस्थिति के लिए सुरक्षित रखना चाहती है. प्रवासी मजदूरों के पलायन और तबलीगी जमात के जमावड़े जैसे झटकों के बावजूद लॉकडाउन से संक्रमण की शृंखला को तोड़ने का कुछ वक्त मिल गया है. अगले कुछ दिनों में लोगों को जागरूक करने, लॉकडाउन पर अमल करने और सामुदायिक संक्रमण की रोकथाम के लिए कदम उठाने की जरूरत है.

इसी के साथ लॉकडाउन को बनाए रखते हुए, देशव्यापी ब्रेकडाउन के वास्तविक खतरे से भी बचने की जरूरत है. अर्थव्यवस्था के चक्कों को चलाए रखना होगा, जिससे स्वास्थ्य संकट कहीं आर्थिक संकट न बन जाए. आर्थिक गतिविधि तो पूरी तरह ठप हो गई है, मार्च और अप्रैल के महीने तो एक मायने में आर्थिक कैलेंडर से गायब ही हो गए. लॉजिस्टिक क्षेत्र के पहिए बैठ गए. लिहाजा, जरूरी आपूर्ति की मुक्त आवाजाही भी थम गई. सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित है क्योंकि खेत-खलिहान का काम ठप है.

हमारी आवरण कथा 'महामारी से मुकाबला' आगे आने वाली चुनौतियों की पड़ताल करती है और बताती है कि संकट से पार पाने के लिए क्या करने की जरूरत है. सीनियर एडिटर सोनाली आचार्जी ने सघन चिकित्सा के मामले में हमारी क्षमता की कमियों का आकलन किया है. एग्जीक्यूटिव एडिटर एम.जी. अरुण, डिप्टी एडिटर श्वेता पुंज और सीनियर एडिटर अनिलेश एस. महाजन ने सड़क परिवहन की पंगु हालत का जायजा लिया है. सीनियर एडिटर कौशिक डेका ने शहरी गरीबों की दशा देखी तो कंसल्टिंग एडिटर अजीत कुमार झा ने जाना कि कृषि क्षेत्र की हालत क्या है. एसोसिएट एडिटर शौगत दासगुप्ता ने दर्ज किया कि कैसे प्रवासी मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया गया.

एक बात तो तय है कि कोरोना संकट से पार पा जाते हैं तब भी हमें लंबा सफर तय करना होगा. हमें उसके लिए तैयार रहना है, घबराना नहीं है. यह वाकई मुश्किल दौर है. सरकार के लिए इस महामारी से जूझना हिमालय लांघने जैसा है. वह उतना ही कर सकती है, जो उसके काबू में है. बाकी, वाकई हमारे हाथ में है.

(अरुण पुरी)

पुनश्च: संकट की इस घड़ी में सही सूचना आपका सबसे बड़िया हथियार है. हम इंडिया टुडे में स्पष्ट और सटीक सूचना आप तक लाने को प्रतिबद्ध हैं. इस अंक का पीडीएफ संस्करण www.indiatoday.in/emaghindi और www.indiatoday.in/magzterhindi पर मुफ्त उपलब्ध है. हम इस संकट के बारे में अपनी वेबसाइट https://aajtak.intoday.in/indiatoday-hindi/ पर भी अपडेट देते रहते हैं.

इलस्ट्रेशनः तन्मय चक्रवर्ती

इंडिया टुडे
www.indiatodayhindi.in

प्रधान संपादकः अरुण पुरी
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टरः राज चेंगप्पा
एडिटरः अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटरः मोहम्मद वकास
एसोसिएट एडिटरः शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर
असिस्टेंट एडिटरः मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
विशेष संवाददाताः मंजीत ठाकुर, संध्या द्विवेदी
राज्य ब्यूरोः आशीष मिश्र (लखनऊ), अमिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटरः नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टरः चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टरः रश्मि सक्सेना
चीफ डिजाइनरः असित रॉय
सीनियर डिजाइनरः वाल्तन सिंह रौतेला
डिजाइनरः अमर प्रकाश बिंजोला
ग्रुप फोटो एडिटरः बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंटः विक्रम शर्मा, सुबीर हलदर, चंद्रदीप कुमार, शैलेश रावल (अहमदाबाद), मंदार देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चरः प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चरः सलोनी वैद
सीनियर फोटो रिसर्चरः शुभोजीत ब्रह्मा
प्रोडक्शन चीफः अभिनव पुजला
पब्लिशिंग डायरेक्टरः मनोज शर्मा
एसोसिएट पब्लिशरः अनिल फर्नांडीस
इंपैक्ट टीमः सीनियर जनरल मैनेजरः जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजरः मयूर रस्तोगी (नॉर्थ),
उपेंद्र सिंह (बेंगलूरू), कौशिकी गांगुली (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसरः विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
चीफ जनरल मैनेजरः डी.वी.एस. रामाराव
सीनियर जनरल मैनेजरः दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजरः विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजरः राजीव गांधी (नॉर्थ)
रीजनल सेल्स मैनेजरः सैयद आसिफ सलीम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजरः एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजरः पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

वर्षः 34; अंकः 23; 9-15 अप्रैल, 2020; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालयः** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोनः 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवाः** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोनः दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्सः (0120) 4078080. ई-मेलः wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालयः** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालयः** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोनः 022-66063355 फैक्सः 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालयः** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोनः 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरू-560 025 फोनः 2212448, 226233, टेलेक्सः 0845-2217 INTO IN. फैक्सः 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालयः के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.

- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110 001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादकः राज चेंगप्पा**

भीतर

फुरसत साहित्यः करो न दिल की बात पेज 63

10 आवरण कथा / महामारी से मुकाबला

कैसे बचाएं जान-माल

कोरोना महामारी से यह दोतरफा जंग है, बदहाल भारतीय नागरिक भी हैं और अर्थव्यवस्था भी. आखिर ऐसे मुश्किल वक्त में क्या हैं भारत के पास विकल्प.

6 तबलीगी जमात

महाफैलाव की अंतर्कथा

दिल्ली में हुए जमात के मरकज ने देश भर में बना दिए कोविड वायरस के बड़े क्लस्टर. अब क्या होगा?

59 उत्तर प्रदेश

चौबीसो घंटे चौकन्ने

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन कोरोना के खिलाफ जंग में भरोसेमंद हथियार बनकर उभरा.

अर्थात्

जीवन बनाम जीविका

अंशुमान तिवारी

जिन्हें लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद बेहद मजबूत है, कोरोना बंदी के बाद देश के हर प्रमुख शहर से पलायन को देखकर, उन्हें खुद को चिकोटी काटनी चाहिए. यह श्रमिक कोरोना से डर कर नहीं, रोजगार गंवाकर रोते हुए घरों को लौटे हैं.

जो यह मानते हैं कि लोग सरकारों में गहरा भरोसा रखते हैं, उन्हें भी खुद को झिंझोड़ना चाहिए. भारत के ताजा इतिहास का यह सबसे बड़ा पलायन ठीक उस दिन शुरू हुआ, जिस दिन लोग ताली-थाली पीट रहे थे, और जब सरकार कोरोना राहत पैकेजों के बीच हजारों लोग अपने घरों की तरफ पैदल चल पड़े थे.

महामारी रोकने की बंदी के पहले तीन दिन के भीतर ही भारतीय अर्थव्यवस्था की 'मजबूत' बुनियाद दरक गई और सिर पर गठरियां रखे, रोता-कलपता विराट अदृश्य भारत, दुनिया के सामने आ गया.

भारत की आर्थिक बुनियाद दरअसल है क्या और क्यों वह एक आपदा भी नहीं झेल सकी?

छठी आर्थिक गणना (2016) बताती है कि—

- भारत में कुल 5.85 करोड़ प्रतिष्ठान हैं जिनमें करीब 78 फीसद गैर कृषि गतिविधियों (प्रशासन, प्रतिरक्षा, घरेलू सहायक आदि शामिल नहीं) में लगे हैं. इनमें 58 फीसद सेवा क्षेत्र में हैं
- करीब 60 फीसद प्रतिष्ठान या तो घर से चलते हैं या उनके पास कोई स्थायी कारोबारी ढांचा नहीं है. इनमें करीब 54 फीसद प्रतिष्ठान के पास कर्मचारी नहीं हैं यानी कि वे स्वरोजगार हैं
- इस अदृश्य अर्थव्यवस्था में प्रति प्रतिष्ठान कर्मचारी संख्या केवल 2.18 है. 1998 से प्रतिष्ठान छोटे होते जा रहे हैं यानी हर कारोबार में कर्मचारियों की संख्या घट रही है और स्वरोजगार बढ़ रहे हैं
- असंगठित क्षेत्र पर श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट (2013-14) बताती है कि गैर कृषि गतिविधियों में लगे 67 फीसद प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या छह से कम है, जबकि 82 फीसद के पास कोई रोजगार अनुबंध नहीं है

इस अर्थव्यवस्था को पिछले पांच साल में चौथी बड़ी चोट लगी है. नोटबंदी ने बिजनेस मॉडल तोड़ दिए, जीएसटी ने घुटनों के बल कर दिया, कर्ज और कानूनी पेच (रेरा) ने भवन निर्माण (जीडीपी का 8 फीसद) खत्म कर दिया और अब कोरोना बंदी के बाद इनके पास न पूंजी बची है न दोबारा खड़े होने की ताकत.

पिछले 40 वर्षों में भारत को जिस विराट आंतरिक प्रवास की अदृश्य ताकत ने गढ़ा है वह इन्हीं लाखों छोटे उद्योगों पर केंद्रित है. आर्थिक सर्वेक्षण (2017) के अनुसार, 2011 से 2016 के बीच करीब 90 लाख लोगों ने प्रति वर्ष आंतरिक प्रवास किया है. भारत में करीब 10 करोड़ आंतरिक प्रवासी शहरों में काम कर रहे हैं. अगर ये 10,000 रुपए प्रति माह (न्यूनतम मजदूरी) भी कमाते हैं तो भी यह कमाई करीब 170 अरब डॉलर है. अगर इसमें एक-तिहाई पैसा भी गांवों में जाता है तो यह धन हस्तांतरण जीडीपी का दो फीसद है. इसलिए यह पलायन शहरों के साथ गांवों को भी गरीब करेगा.

यह अदृश्य बुनियादी अर्थव्यवस्था उद्योग मेलों या प्रधानमंत्री की बैठकों का हिस्सा नहीं होती. मंदी से निबटने की राहत भी सरकारों की दोस्त कंपनियां खा गईं. उलटे नीति निर्माताओं की सोच में इन बुनियादी छोटों को लेकर वितृष्णा दिखती है. असंगठित क्षेत्र को वे काले धन की खान मानते हैं, सरकार इन्हें पीटकर बदलना चाहती है. यह पिटाई इन्हें खत्म कर रही है जिसका फायदा बड़ी कंपनियों को है.

भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद पहले से कमजोर है. कोरोना की विदाई के बाद यह सपाट मैदान हो जाएगी. सीमित साधनों वाले गांव इन प्रवासियों का पेट भी नहीं भर पाएंगे. कोरोना के जाने के बाद अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना होगा. अगर आंखें खुल चुकी हों तो यह नया निर्माण नीचे से शुरू होना चाहिए.

- भारतीय अर्थव्यवस्था 49 क्लस्टर (उद्योग, नगर, बाजार) में फैली है जो जीडीपी में 70 फीसद का योगदान करते हैं. सियासी चंदे देने वालों की जगह यहां रोजगार देने वालों के लिए नीति बनानी होगी
- छोटे उद्योगों के लिए उत्पाद आरक्षण की वापसी जरूरी है. वह खुदरा सामान तो बना सकते हैं जो हम आयात करते हैं
- बैंकों को छोटे उद्योगों को पूंजी और कर्ज देने के नए उत्पाद विकसित करने होंगे

सरकारों के भव्य वादों के बावजूद वे लाखों लोग कौन थे जो अपने वर्षों पुराने रोजगार छोड़कर अचानक गांवों की ओर चल दिए? ताजा अध्ययनों (सेंटर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर ऐंड लेबर स्टडीज, जेएनयू) के मुताबिक, रोजगार प्राप्त करीब 46.5 करोड़ लोगों में से करीब 13.6 करोड़ लोगों के पास कोई रोजगार अनुबंध नहीं है. यानी कि इतने तो रोजगारों पर सीधा खतरा है.

ये ही लोग कोरोना बंदी के अपने घरों को चल पड़े हैं. उन्हें कोरोना से मरने का डर भी नहीं था क्योंकि जीवन से जीविका प्यारी होती है. यह पलायन दरअसल सरकारों और व्यवस्था से मोहभंग का सबसे संगठित प्रमाण है. लोग उस गरीबी में वापस लौट रहे हैं जहां से उनका निकलना इस सदी में भारत की सबसे बड़ी सफलता रही थी.

@anshuman1tiwari

अगर आंखें खुल गई हों तो अर्थव्यवस्था का नया निर्माण बुनियाद से शुरू होना चाहिए

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

खास रपट
तबलीगी जमात

कोरोना को यहां लगे पंख

MAGAZINE KING

भारत में और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में धार्मिक संगठन का एक जलसा कोविड-19 को फैलाने में कैसे जिममेदार रहा है

सोनाली आचार्जी और उदय माहूरकर, साथ में गुलाम जीलानी

भारत में नए कोरोनोवायरस संक्रमित लोगों की संख्या 2,000 को पार करने के बाद, दक्षिणी दिल्ली की निज़ामुद्दीन बस्ती देश के महामारी के हॉटस्पॉट के रूप में उभरी है. मार्च की शुरुआत में यहां तब्लीगी जमात के सदस्यों और प्रचारकों के करीब 3400 लोगों के जमावड़े ने कश्मीर से तमिलनाडु और यहां तक कि अंडमान द्वीप समूह में भी संक्रमण पहुंचाया है और कई लोगों की जान गई है. निजामुद्दीन स्थिति संगठन के मरकज़ या वैश्विक मुख्यालय, बंगलेवाली मस्जिद के छह मंजिला छात्रावास में सैकड़ों लोग नजदीकी संपर्कों में रहते थे. जमात एक वैश्विक इस्लामिक धार्मिक अभियान है, जिसकी शुरुआत 1927 में भारत में हुई थी.

2 अप्रैल तक देश में कोविड-19 के कारण हुई 15 मौतों की कड़ी 10 से 13 मार्च को हुए मरकज़ के सम्मेलन से जुड़ रही है. वायरस के कारण तेलंगाना में नौ, दिल्ली में दो और जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और तमिलनाडु में

कोविड का खौफ
जमातियों का एक जत्था निजामुद्दीन में क्वारंटीन में जाने का इंतजार करते हुए. यहां तबलीगी जमात का मुख्यालय है

जंगल में आग की तरह

27 फरवरी
कुआलालंपुर की श्री पेटलिंग मस्जिद में मरकज में 16,000 लोग जुटे. 600 से ज्यादा कोविड-19 पॉजिटिव

10-13 मार्च
दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीग के मरकज में 3,400 शामिल. इनमें मलेशिया के मरकज में शामिल लोग भी

11 मार्च
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया

13 मार्च
दिल्ली सरकार ने 50 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगाई

17 मार्च
मरकज में शामिल लोगों में कोविड-19 के मामले सामने आने शुरू. 10 तो अकेले तेलंगाना से ही निकले

26 मार्च
जमात के कश्मीर के एक सदस्य की कोविड-19 के संक्रमण से मौत

1 अप्रैल
जमात का निजामुद्दीन स्थित मुख्यालय सील. परिसर से 2,361 लोगों को निकाला गया

MAGAZINE KING

एक-एक मौतों का संबंध मरकज़ कायक्रम से पाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में एक फिलिपीनी नागरिक भी शामिल है. कार्यक्रम में शामिल लगभग 400 लोगों में अब तक नए कोरोनावायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. जमात के सदस्य और उनके प्रत्यक्ष संपर्क में आए देशभर में लगभग 9,000 लोगों को क्वारंटीन किया गया है. इनमें से करीब 1,800 लोग दिल्ली के 9 अस्पतालों और क्वारंटीन केंद्रों में निगरानी में हैं. 1 अप्रैल को मीडिया ब्रीफिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, ''भारत में कोविड-19 मामलों में हालिया वृद्धि को पूरे देश में संक्रमण का ट्रेंड नहीं माना जा सकता. संक्रमण के मामलों में आई अचानक तेजी तब्लीगी जमात के लोगों की आवाजाही के कारण है.''

जमात से बंगलेवाली मस्जिद को खाली करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को हस्तक्षेप करना पड़ा. 2015 से जमात के प्रमुख और संगठन के संस्थापक मौलाना मुहम्मद इलियास कांधलवी के पोते मौलाना साद से मिलने डोवाल को आना पड़ा. डोवाल की ओर से कथित तौर पर मस्जिद को खाली करने के लिए पुलिस और यहां तक की कमांडो कार्रवाई की धमकी के बाद ही मौलाना साद झुका. 1 अप्रैल को परिसर खाली करा लिया गया और निवासियों को क्वारंटीन केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय अब उस हरेक व्यक्ति

महामारी का मरकज

जमात के सम्मेलन ने कोविड-19 से निबटने की भारत की कोशिशों को पलीता लगाया

9,000
तबलीगी जमात के सदस्य और उनके संपर्क में आए लोग अब तक क्वारंटीन किए गए

400
कोविड-19 के संक्रमण के शिकार लोगों का ताल्लुक दिल्ली में जमात के आयोजन से निकला

15
कोविड 19 मौतें जमात से जुड़े लोगों की हुईं. इनमें एक फिलीपींस का नागरिक भी शामिल है

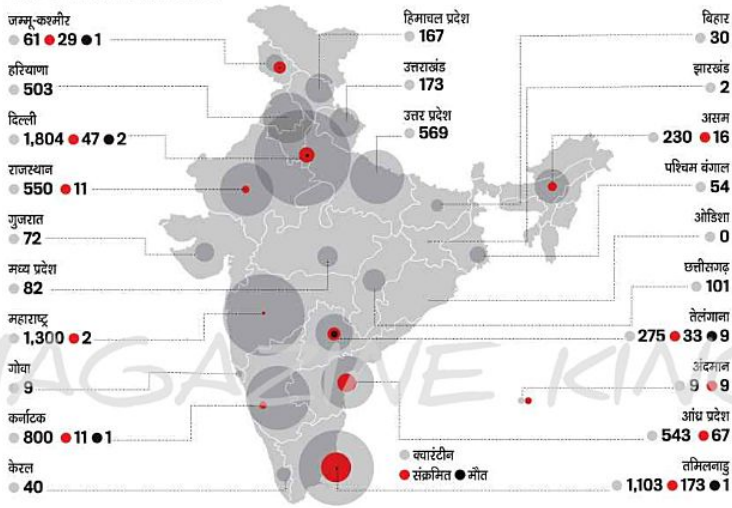

कुछ राज्यों से डाटा अभी हासिल नहीं हुआ है. जमात के आयोजन से जुड़े कुछ संपर्कों को अब भी क्वारंटीन के लिए तलाशा जा रहा है.

स्रोत: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारें

MAGAZINE KING

पर डोजियर तैयार कर रहा है जो मरकज में मौजूद था. उनकी यात्रा इतिहास का पता लगाया जा रहा है, मोबाइल डेटा को खंगाला जा रहा है और तकनीक के उपयोग से यह जानने के लिए किया जा रहा है कि वे सभी किस-किसके संपर्क में आए.

मरकज ही जमात का भारत-आधारित धर्म प्रचारकों का प्रस्थान बिंदु है. यहां से ही वे समूहों में दूसरे राज्यों में जाते हैं, जहां परंपरा के अनुसार, वे स्थानीय मस्जिदों में रहते हैं. जमात के एक सदस्य जो मुख्यालय के साथ नियमित रूप से कार्यरत हैं, बताते हैं, ''प्रचारक और अनुयायी मरकज में इकट्ठा होते हैं. यहां से, वे गांवों और कस्बों में जाते हैं.'' प्रचारकों का मुख्य कार्य उन मुसलमानों को फिर से धर्म में लौटाने का है जो धर्म की राह से भटक गए हैं.

तब्लीगी लोग कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक हैं. सरकार उन्हें संदेह से देखाती है, लेकिन अब तक वे कानूनी प्रक्रियाओं में बने हुए हैं. हालांकि, अनजाने ही कोरोना संक्रमण के प्रसार के केंद्र के रूप में उनकी भूमिका के बाद चीजें थोड़ी जटिल हो सकती हैं और उनकी गतिविधियों पर सरकार का पहरा बढ़ सकता है.

तो पहली बार जमाती कैसे संक्रमित हुए होंगे? माना जा रहा है कि फरवरी में मलेशिया में आयोजित एक तब्लीगी जमात की मजलिस में निजामुद्दीन मरकज से भारतीय सदस्यों ने भाग लिया था और संक्रमण वहीं से आया होगा. 27 फरवरी को, कुआलालंपुर की श्री पेटलिंग मस्जिद में अनुमानित 16,000 लोग जमा हुए थे. अगले सप्ताह हुई जांच में इस चार दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले 620 से अधिक लोगों को कोविड-19 संक्रमित पाया गया. वहां उपस्थित लोग संक्रमण को अपने-अपने देशों में लेकर गए- ब्रूनेई में 73, थाईलैंड में 10 और पाकिस्तान में 35 संक्रमित पाए गए लोग मलेशिया की उस मजलिस से लौटे थे. मलेशिया से आए कुछ लोग निजामुद्दीन मरकज में रुके थे. जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च को कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया तो उसके दो दिन बाद, दिल्ली सरकार ने 14 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी.

इस आदेश का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली सरकार ने कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश तो की, लेकिन 28 मार्च को मरकज से छह कोविड-19 मामले सामने आने के बाद ही. आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता अक्षय मराठे ने कहा, ''यह आपराधिक लापरवाही थी और 13 मार्च को जारी उन आदेशों का

उल्लंघन जिसमें आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.'' दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने मरकज प्रबंधन को नोटिस जारी किए हैं. नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी बताते हैं, ''हमने आयोजकों को मरकज़ खाली करने के लिए राजी करने के लगातार प्रयास किए. हमने 23 मार्च को भी एक बैठक की. लेकिन वे हमारी कोई बात सुनने को राजी न थे.'' अंतत: प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के लिए 31 मार्च को मौलाना साद और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

निजामुद्दीन में जुटी जमात से वायरस किस तरह और कितना फैला होगा, इसके पीछे तीन सिद्धांत दिए जा रहे हैं. पहला कि कितने संप मित लोगों ने शिरकत की थी. मलेशिया से लगभग 62 लोग उपस्थित थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ये सभी या इनमें से कोई भी कुआलालंपुर कार्यक्रम में शामिल हुए था या नहीं और भारत आने से पहले से ही इनमें से कितने लोग संक्रमित थे. इसके अलावा, निज़ामुद्दीन में मौजूद लोगों ने बाद में यात्राएं भी कीं और समूहों में वापस अपने घर गए. इसलिए अगर यह मान भी लिया जाए कि दिल्ली की सभा से कुछ ही लोग संक्रमित हुए थे, तो भी उन लोगों ने उसके बाद न जाने कितने लोगों तक संक्रमण पहुंचाया होगा.

दूसरा सिद्धांत यह है कि धार्मिक सभाओं में लोग सामान्य रूप से एक दूसरे से बहुत करीब रहते हैं. दिल्ली में कोविड-19 के कुल मामलों में से 100 से अधिक ऐसे समारोहों से जुड़े हुए हैं. दक्षिण कोरिया में, एक 61 वर्षीय महिला, जिसे स्वास्थ्यकर्मियों के बीच 'रोगी 31' के रूप में में पहचाना जाता है, ने एक ईसाई पंथ की दो बैठकों में भाग लिया था और वह एक हजार से अधिक संक्रमणों का स्रोत बन गई थी. भारत में, पंजाब के एक उपदेशक बलदेव सिंह ने यूरोप का दौरा किया था और भारत लौटने के बाद क्वारंटीन के आदेशों की अवहेलना की थी. राज्य में 32 कोविड-19 संक्रमण के मामलों को बलदेव से जोड़ा गया है. जसलोक अस्पताल, मुंबई के संक्रामक रोगों, एचआईवी मेडिसिन और इम्युनोलॉजी विभाग के निदेशक, डॉ. ओम श्रीवास्तव, एचआईवी कहते हैं, ''हमें तेजी से सबूत मिल रहे हैं कि वायरस वायुवाहित (एयरबोर्न) हो सकता है- यह नमी, तापमान, हवा की स्थिति और ऐसी कई चीजों पर निर्भर करेगा. जब आप एक बड़े समूह के निकट संपर्क में होते हैं, तो संक्रमित व्यक्ति से महीन बूंद के रूप में, वायरस हवा में हो सकता है और किसी भी सतह पर पहुंच सकता है. अगर वे संक्रमित व्यक्ति के बेहद करीब हैं तो ये सांस से शरीर के अंदर जा सकता है.''

निगरानी: नई दिल्ली में तबलीगी जमात के लोग क्वारंटीन के लिए ले जाए गए

गेट्टी इमेजेज

दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने मरकज के आयोजकों को नोटिस दिया और उनसे मुलाकात कर कार्यक्रम खत्म करने के लिए भी कहा गया लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा

तीसरी व्याख्या 'वायरल लोड' की हो सकती है यानी कितना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है. एक उच्च वायरल लोड को कोविड-19 के अधिक गंभीर लक्षणों से जोड़ा गया है, और यही कारण है कि निज़ामुद्दीन जमात के साथ संपर्क में आए अधिकांश मामलों में बहुत स्पष्ट लक्षण दिखाई दिए हैं, और उनमें से कई संक्रमण के कारण दम तोड़ चुके हैं. हालांकि, जमात मुख्यालय में पूरे वर्ष आगंतुकों की आवाजाही होती है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मार्च के पहले सप्ताह में भारत और विदेश दोनों के आगंतुकों की संख्या में वृद्धि देखी गई. हरियाणा के मेवात के एक जमाती का कहना है कि 10 मार्च तक विभिन्न देशों के 2,500 लोग मरकज़ में इकट्ठे हुए थे.

मरकज़ में संभावित संक्रमण का पहला सबूत 17 मार्च को आया जब कश्मीर के एक जमात सदस्य की घर लौटने पर जांच हुई तो वह संक्रमित पाया गया. श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके के व्यापारी की 26 मार्च को मृत्यु हो गई. 7 मार्च को मरकज़ से निकलकर 9 मार्च को श्रीनगर पहुंचने से पहले वह उत्तर प्रदेश के देवबंद भी गया था. यह अनुमान है कि 1 जनवरी से, 2,000 से अधिक विदेशियों ने उपदेश से जुड़ी गतिविधियों के लिए भारत का दौरा किया है. 21 मार्च को गृह मंत्रालय ने उन 824 विदेशी नागरिकों के बारे में राज्य सरकारों को सूचित किया, जिन्होंने जमात मुख्यालय का दौरा किया था और उसके बाद अन्य राज्यों की यात्रा की.

25 मार्च को, तीन सप्ताह के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के लागू होने के बाद, स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के अधिकारियों और एक मेडिकल टीम ने मरकज़ का निरीक्षण किया और आगंतुकों की एक सूची तैयार की. मेडिकल जांच शुरू हुई.

हालांकि, जमात के सदस्यों का दावा है कि 23 मार्च को मरकज ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को परिसर के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में सूचित किया था, लेकिन प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया. 1 अप्रैल को, दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की कि 36 घंटे के लंबे ऑपरेशन में 2,361 लोगों को मरकज़ से निकाला गया. इस क्षेत्र को पूरी तरह बंद कर दिया गया और सफाई के बाद इमारत को सील कर दिया गया है. जमात में शिरकत करने वाले लोगों के जरिए वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिश में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों के साथ जिस तरह की हाथापाई की जा रही है, उसे देखते हुए यह आशंका है कि पहले ही काफी क्षति हो चुकी है. एक सवाल यह भी है-क्या इसे रोका जा सकता था? ■

जान-माल बचाने

भारत फिलहाल नोवेल कोरोनावायरस का फैलाव रोक पाने में कामयाब रहा है लेकिन इसकी उसे बड़ी भारी सामाजिक-आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी है. अब जरूरत है स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की, अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति आसान बनाने की और इससे बाहर निकलने की रणनीति तैयार करने की, जिसमें अर्थव्यवस्था और लोगों को फिर अपनी पुरानी लय में वापस लाने के लिए वित्तीय पैकेज भी शामिल हो

राज चेंगप्पा

सख्त मिसाल नई दिल्ली में 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में कैबिनेट की वैठक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ

का सवाल

नरेंद्र मोदी ने **24 मार्च** को देश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का जो फैसला लिया, वह आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री की सबसे अहम कार्रवाई के तौर पर दर्ज किया जाएगा. मानव इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक अरब से ज्यादा लोगों को घरों में बंद कर दिया गया हो. यहां तक कि चीन, जहां कोविड-19 नाम की बीमारी पैदा करने वाला नोवेल कोरोनावायरस पहली बार प्रकट हुआ, वहां के नेतृत्व ने भी देशव्यापी कामबंदी सरीखा भीषण कदम नहीं उठाया.

आजादी के बाद भारत ने जो चार जंग लड़ीं, उनमें भी रातों में ब्लैकआउट के अलावा लोग बेधड़क यहां-वहां घूमते थे और वस्तुओं तथा सेवाओं की आवाजाही भी होती थी. उद्योग का पहिया कभी नहीं रुका. 1975-1977 के आपातकाल के दौरान बुनियादी अधिकारों और खुलेआम इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदियां लगीं पर यातायात और दूसरी तमाम गतिविधियां जारी थीं, बल्कि डर के मारे ज्यादा ही अनुशासित थीं. लिहाजा देश के लॉकडाउन में जाने के बाद मोदी और उनकी टीम को रास्ता दिखाने के लिए उनके अपने देश का, या इस लिहाज से किसी भी दूसरे देश का, महामारी से निबटने का ऐसा कोई अनुभव नहीं था, जिसकी रौशनी में फैसले लेते और कदम उठा पाते.

जानकार अफसर बताते हैं कि उन्हें एक ऐसा कानून तक खोजने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी, जिसका इस्तेमाल

जानकार अफसर बताते हैं कि उन्हें एक ऐसा कानून तक खोजने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी, जिसका इस्तेमाल वे राष्ट्रीय आपातकाल से कमतर एक फैसला लागू करने के लिए कर सकें. आपातकाल के साथ जुड़ी बदनामी और ऐसा आदेश थोपने की वैधानिकता के अलावा यह बात भी ध्यान में रखी गई कि इस प्रावधान का इस्तेमाल करने से राज्य अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं, वह भी ऐसे वक्त जब वायरस के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने के लिए उनके पूरे सहयोग की जरूरत है. फिर उन्होंने महामारी रोग अधिनियम का अध्ययन किया, जो मुंबई में ब्यूबनिक प्लेग से निबटने के लिए 1897 में लाया गया था.

आखिर में, अफसरों ने मोदी को आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होने के नाते उन्हें दिए गए अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने की सलाह दी. इसके तहत राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू किया जा सकता था और राज्य इसके तहत उठाए गए कदमों का पालन करने को बाध्य थे. इसके फौरन बाद प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ पी.के. मिश्र और कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा नेराज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक करके यह पक्का किया कि लॉकडाउन सख्ती से लागू किया जाए और केवल अनिवार्य वस्तुओं तथा सेवाओं की आवाजाही की इजाजत दी जाए.

बड़े अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और प्रमुख मंत्रालयों के भीतर काफी माथापच्ची और विचार-विमर्श के बाद लिया गया. इस वायरस से लड़ने के कदम 7 जनवरी से ही उठाने शुरू कर दिए गए थे, जब चीन ने आखिरकार माना कि उसके वुहान और हुबेइ प्रांतों में फैले संक्रामक बुखार की वजह के तौर पर कोरोनावायरस की पहचान की गई है. आखिरी गिनती तक चीन में इससे 81,589 लोग संक्रमित और 3,318 लोग मर चुके थे. इसके फौरन बाद भारतीय नागरिक विमानन और स्वास्थ्य विभागों ने प्रमुख हवाई अड्डों पर तमाम अंतरराष्ट्रीय और खासकर चीन से आने वाले यात्रियों की जांच-पड़ताल करना शुरू कर दिया.

पीएमओ ने 25 जनवरी को अहम विभागों के साथ तैयार को लेकर समीक्षा बैठक की और उसके बाद इन कदमों को और बढ़ा दिया गया. सभी हवाई अड्डों पर जांच-पड़ताल को उत्तरोत्तर और बढ़ाने के आदेश दे दिए गए, सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालयों को अलर्ट करते हुए उन्हें लगातार जानकारी रखने के कदम उठाए गए. देश भर में फैली राष्ट्रीय वाइरोलॉजी संस्थान की प्रयोगशालाओं को इस वायरस की जांच करने के लिए सुसज्जित किया गया. देश की तैयारी बढ़ाने के लिए मोदी ने 3 फरवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक अधिकार प्राप्त समूह गठित किया और उसमें विदेश, गृह, नागरिक उड्डयन तथा जहाजरानी मंत्रालयों के मंत्रियों को सदस्य रखा गया. उस वक्त तक भारत में कोविड-19 के महज तीन मामले सामने आए थे.

एक वरिष्ठ अफसर कहते हैं, चीजें मार्च के पहले हफ्ते से 'वाकई भयावह होना' शुरू हुईं. 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया, जब दुनिया भर में 114 देशों में यह महामारी फैल गई, 1,18,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो गए और 4,291 लोगों की इससे मौत हो गई. उस वक्त भारत में इसके मामलों की संख्या 57 और मौत महज एक थी—जो यूरोप, पूर्व एशिया और खासकर दक्षिण कोरिया तथा अंततः अमेरिका के इसके तेज फैलाव के मुकाबले बहुत कम थी. अलबत्ता भारत जब दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित था, तब भी विशेषज्ञों ने मोदी को आगाह किया कि खुशफहमी से बचना होगा. देश दूसरे चरण की तरफ बढ़ चुका था, जिसमें देश लौटकर आए बिल्कुल शुरुआती यात्रियों के संक्रमित पाए जाने के बाद स्थानीय संक्रमण होना शुरू हो गया था. हालांकि असल चिंता की बात महामारी का तीसरा चरण था, जिसमें वायरस सामुदायिक संचरण के जरिए फैलता और मौतों की संख्या में हर रोज कई गुना बढ़ोतरी होती. इसके बाद यह भयावह चौथे चरम में जा सकता था, जहां

बंदीप सिंह

इंतजार में आंखें बेटे को कंधे पर बिठाए दिल्ली में झांसी के लिए बस की बाट जोहता एक श्रमिक

MAGAZINE KING

केंद्र के 11 अधिकारप्राप्त समूह संकट से निकलने और लॉकडाउन की चुनौतियों से निबटने की युक्तियां निकालने में जुटे हुए हैं

आबादी के झुंड के झुंड संक्रमित होते.

प्रधानमंत्री को बखूबी पता था कि भारत में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा और सुविधाएं सामुदायिक संक्रमण और खासकर यदि संक्रमित लोगों की तादाद कुछ ही दिनों के भीतर कुछ हजार से सैकड़ों हजार तक बढ़ जाती है तो ऐसे हमले का मुकाबला करने के लिए अच्छी तरह तैयार नहीं है. दूसरे देशों में इस महामारी के फैलने के तरीके को लेकर किए गए अध्ययनों से पता चला कि 80 फीसदी संक्रमित लोगों को इसमें हल्का बुखार होता है जिसका इलाज घर पर किया जा सकता है, जबकि बाकी 20 फीसदी को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है. इनमें से 8 फीसदी के इलाज के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट (आइसीयू) की जरूरत होगी. फिलहाल भारत में महज करीब 29,000 मरीजों के इलाज के लिए आइसीयू की सुविधाएं मौजूद है, लेकिन ये देश भर में फैली हुई हैं. मसलन, महाराष्ट्र, जहां अब तक सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, केवल 2,500 आइसीयू बिस्तर हैं. अगर महामारी एक ही राज्य तक सीमित रहती है, जैसा कि चीन में हुआ, तो उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा. अगले छह महीने तक जब वैक्सीन या टीके की कोई संभावना नजर नहीं आती, ऐसे में कोविड-19 को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे सामाजिक दूरी के जरिए रोका जाए और संक्रमित व्यक्तियों को क्वारंटीन रखने का पक्का इंतजाम किया जाए ताकि वे दूसरों को संक्रमित न करें.

फिर मोदी और उनकी टीम ने क्लस्टर तरीके पर चर्चा की, यानी केवल संक्रमित जगहों को लॉकडाउन किया जाए, जैसा कि चीन ने अपने दो प्रांतों के साथ किया था. 19 मार्च को जब मोदी ने 'जनता कर्फ्यू' का ऐलान किया, तब 75 जिलों में कोरोनावायरस के मामले सामने आए थे जिन्हें लॉकडाउन किया जाना था. शुरुआत में योजना संपूर्ण लॉकडाउन करने के बजाय थोड़े-थोड़े वक्त बाद बार-बार जनता कर्फ्यू लगाने की थी. लेकिन लॉकडाउन किए गए जिलों की संख्या जल्दी ही बढ़कर 548 या देश के कुल 720 जिलों के तीन-चौथाई पर पहुंच गई. ज्यादातर राज्यों में अपने जिलों में किसी न किसी शक्ल में कर्फ्यू लगा दिया था. लिहाजा फिर टुकड़ा-टुकड़ा उपाय का तरीका खारिज करना पड़ा. यही वह बिंदु था जब मोदी ने तय किया कि अब जरा भी और वक्त न गंवाया जाए और 25 मार्च से देश भर में 21 दिनों का राष्ट्रीय लॉकडाउन करने का फैसला लिया जाए. एक बड़े अफसर बताते हैं, ''यह मुश्किल फैसला था, पर इसे टालना देश के लिए विनाशकारी

होता. जिंदगी और रोजी-रोटी के बीच किसी एक को चुनना था और हमने जिंदगी को चुना. यही नहीं, अगर हमने तीन दिनों की मोहलत दी होती, तो रेलों, बसों और उड़ानों में लोगों की इस कदर भीड़ टूट पड़ती कि लॉकडाउन का मकसद ही नाकाम हो जाता.''

तो भी, अधिकारी जहां यह दावा करते हैं कि उन्हें ''लॉकडाउन से पैदा सकने वाली 95 फीसदी परेशानियों'' का पहले से अंदाजा था, लेकिन वे स्वीकार करते हैं कि वे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के इतनी बड़े पैमाने पर वापस ग्रामीण इलाकों में लौटने के लिए तैयार नहीं थे. इसके लिए वे उन अफवाहों को दोषी ठहराते हैं जिनमें कहा गया कि लॉकडाउन तीन महीने चलेगा और कामगारों को मालिक तनख्वाह भी नहीं देंगे. पांच लाख से ज्यादा कामगार दूर-दराज के अपने घरों के लिए शहरों से निकल पड़े, इसने संक्रमण के ग्रामीण भारत तक फैलने का असल खतरा पैदा कर दिया.

लॉकडाउन के एक दिन बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, किसानों के अलावा, गरीबों और खासकर लॉकडाउन से सर्वाधिक प्रभावित प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए कुल 1.7 लाख करोड़ रुपए के उपायों की घोषणा की. इनमें अगले तीन महीनों तक हर महीने अनाजों की मौजूदा पात्रता को दोगुना बढ़ाते हुए अतिरिक्त 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दालें देना शामिल था. जन धन खातों से लैस 20.4 करोड़ महिलाओं को अगले तीन महीने तक हर महीने 500 रुपए देने का वादा किया गया. वहीं किसानों के लिए ऐलान किया गया कि उन्हें पीएम-किसान योजना के तहत सालाना दिए जाने वाले 6,000 रुपए के हिस्से के तौर पर 2,000 रुपए का अग्रिम भुगतान अप्रैल में कर दिया जाएगा. इन उपायों को लेकर विशेषज्ञों की राय बंटी हुई थी. कुछ ने कहा कि अलग-अलग योजनाओं में बंटी हुई रकम देने के बजाय इस संकट से उबरने के लिए उन्हें सार्वभौम बुनियादी आमदनी देना कहीं बेहतर होता. भारतीय रिजर्व बैंक भी आगे आया और उसने ब्याज दरों में कटौती की और बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात की बाध्यता को आसान बना दिया ताकि संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ सके.

इस बीच अर्थव्यवस्था में एक और बड़ा संकट भीतर ही भीतर खदबदाने लगा. हालांकि अनिवार्य वस्तुओं की आवाजाही को बनाए रखने के आदेश दिए गए थे, इसके बावजूद लॉकडाउन को लागू करने दबाव में राज्य पुलिस बलों ने स्थिति से बेतुके ढंग से निबटना शुरू कर दिया. फल, सब्जियां और दूसरी अनिवार्य वस्तुएं ले जा रहे 13 लाख से ज्यादा ट्रकों को तमाम राजमार्गों के जांचस्थलों पर फंसा छोड़ दिया गया. तमाम यात्री उड़ाने रद्द कर दी गई हैं और रोज केवल 10 कार्गो उड़ानें चल रही हैं, ऐसे में वस्तुओं का लाना-ले जाना मुश्किल हो गया. बताते हैं सरकार को एक आयातित हजमत सूट को ले जाने के लिए पूरा विमान चार्टर करना पड़ा, क्योंकि तमिलनाडु की फैक्टरी में उसकी नकल पर बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उसकी जरूरत थी. दूसरी मिसाल वह थी जब 40,000 से ज्यादा हाथ में पकड़े जाने वाले थर्मल थर्मामीटर हांगकांग से पश्चिम बंगाल पहुंचाने के लिए चार्टर विमान किराये पर लेना पड़ा.

यह अहसास होने के बाद कि हालात संकट

आइसीयू की चौखट पर खड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा आर्थिक पैकेज रूपी वित्तीय वेंटिलेटर मुहैया कराने को भारतीय उद्योग जगत मोदी सरकार का मुंह निहार रहा.

के प्रबंधन की असाधारण रणनीतियों की मांग करते हैं, मोदी ने शीर्ष केंद्रीय सचिवों और विशेषज्ञों की 11 अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया ताकि लॉकडाउन को असरदार बनाने, उथल-पुथल को कम से कम करने और किसी भी संभावित आकस्मिक परिस्थिति के लिए पहले से पर्याप्त कदम उठाना पक्का करने के लिए जरूरी कार्रवाइयों और फैसलों को तेजी से अंजाम दिया जा सके. इनमें से चार समूहों को खास तौर पर बेहद अहम स्वास्थ्य क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी सबंपी गई है. इनमें मेडिकल इमरजेंसी सुविधाओं का तेजी से विस्तार, मरीजों की जांच, सुरक्षा और इलाज के लिए पर्याप्त उपकरण का मिलना पक्का करना शामिल है. एक समूह अनिवार्य वस्तुओं की आवजाही पक्की करने के लिए सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन में सुगमता का काम देख रहा है. एक तीसरे समूह को इस बात की पड़ताल करने का काम सौंपा गया है कि इस वायरस और उसके शिकारों के फैलाव की निगरानी में टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है. इतना ही अहम यह कि एक अन्य समूह लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति पर काम कर रहा है.

पूर्णबंद लागू होने के पांच दिन बाद 29 मार्च को गठित, इन समूहों ने संकट को संभालने के तरीके बदलते शुरू कर दिए, जिससे बंद से पैदा हुई चुनौतियों से निबटने के लिए उद्देश्य और विश्वास की एक नई भावना पैदा हुई है. इनमें से एक समूह के एक अधिकारी कहते हैं, ''हम दिन-रात काम कर रहे हैं, जिसमें जूम के माध्यम से कॉन्फ्रेंस आयोजित कराना भी शामिल है. हम पर्दे के पीछे से काम करने वाले लोगों जैसी भूमिकाएं निभा रहे हैं, और मंत्रालयों को कुछ ऐसी जरूरी सिफारिशें देते हैं जिसे लागू किए जाने की जरूरत है. कई बार, हम फोन-अ-फ्रेंड की तरह काम करते हैं.'' मसलन लॉजिस्टिक्स ग्रुप ने जो शुरुआती काम किए, उनमें से एक रहा उस नियम को हटाना जो सिर्फ जरूरी वस्तुओं के परिवहन की ही अनुमति देता था और इस नियम के कारण चेक-पोस्ट पर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई थी. समूह के सदस्य चोक पॉइंट को साफ कराने में एक बड़े मददगार के रूप में भी कार्य करते हैं. जब देश के प्याज केंद्र नासिक में मंडी बंद रही, तो ट्रक ड्राइवरों को सीधे किसानों के पास जाने और फसल लेने के लिए कहा गया, जबकि राज्य के अधिकारियों से उपज को थोक विक्रेताओं को बेचने की अनुमति दिलाई गई. हालांकि, सशक्त समूहों की नई प्रणाली की असल परीक्षा अप्रैल के मध्य में होगी जब रबी की कटाई अपने चरम पर पहुंच जाती है. अनाज को मंडियों में ले जाने और इसे खरीदे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए—अन्यथा किसानों और अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे.

मोदी सरकार की स्थिति पर पकड़ बनती तो दिख रही है, फिर भी लंबा रास्ता तय करना है. कोविड-19 मामलों और मौतों की संख्या अभी भी अपेक्षाकृत कम है. 2 अप्रैल तक 2,015 संक्रमण और 53 मौतों का आंकड़ा दुनियाभर में 10 लाख संक्रमण और 50,000 से अधिक मौतों की तुलना में बहुत कम है. भारत में कम संख्या इसलिए भी हो सकती है क्योंकि यहां मुख्य रूप से केवल उन लोगों की जांच की गई है जिनमें बीमारी के स्पष्ट लक्षण दिखे हैं. सरकार ने अब प्रसार की बेहतर स्थिति समझने

के लिए विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षणों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है. इसकी वजह किसी भी आगामी चुनौती से निपटने के लिए स्वास्थ्य इंतजामों को बढ़ाना है. जैसा कि एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, ''हम सबसे विकट स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं—यहां तक कि क्वारंटीन और आइसीयू सुविधाओं सहित 2 लाख से अधिक मामलों से निबटने की योजना बना रहे हैं. ''इस बीच, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों को जुटाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने वाले डॉक्टर भी शामिल हैं. उन्हें कोरोना के मामलों को संभालने का प्रशिक्षण दिया जाएगा. विदेशों से वेंटिलेटर के अलावा, विशेष रूप से चिकित्सा कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) खरीदने के रास्ते की सभी अड़चनों को दूर किया जा रहा है और जरूरी खर्च में कोई कमी नहीं की जा रही है. 45,790 वेंटिलेटर के लिए ऑर्डर दिए गए हैं जो देश में 15,000 की उपलब्धता का तीन गुना है. यहां तक कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को ही भारत में कुछ वेंटिलेटर्स बनाने के लिए कहा गया है. सरकारी आयुध कारखानों को 3,00,000 पीपीई का निर्माण करना है, जबकि 80 लाख का आयात किया जा रहा है. कुल मिलाकर, विभिन्न राज्यों में 3,50,000 पीपीई ही फिलहाल उपलब्ध हैं और इसे 1.1 करोड़ तक पहुंचाने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं.

मोदी सरकार फिलहाल हर चीज को प्राथमिकता दे रही है लेकिन अब इसे अर्थव्यवस्था को फिर जीवित करने के लिए एक आर्थिक पुनरुद्धार पैकेज पर काम करना होगा ताकि लुढ़कती अर्थव्यवस्था को थामा जा सके. क्रिसिल जैसी रेटिंग एजेंसियों ने पहले ही वित्त वर्ष 2021 के लिए देश की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 5.2 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत कर दिया है. वित्त मंत्रालय की तरह रिजर्व बैंक ने भी कई उपायों की घोषणा की है लेकिन उद्योग जगत चाहता है कि सरकार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि दे और उन्हें परेशानी से बाहर निकाले. वे ध्यान दिलाते हैं कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 2 ट्रिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं. यह सबसे बड़ा अमेरिकी वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज है जिसमें महामारी से प्रभावित व्यक्तियों और कंपनियों को प्रत्यक्ष भुगतान शामिल है, बेरोजगारी भत्तों के लिए राज्य सरकारों को मदद और आर्थिक गतिविधियों के बंद होने के कारण दिवालिया होने की कगार पर खड़ी कंपनियों को ऋण और कर राहत शामिल है. भारतीय उद्योग ने मोदी से एक बड़े आर्थिक पैकेज पर काम करने की आस लगा रखी है जो व्यवसायों को अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में मदद करे और आइसीयू में पड़ी अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय वेंटिलेटर बनकर उसे बचा ले.

प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से स्थिति की दैनिक निगरानी कर रहे हैं. 2 अप्रैल को, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरे दौर की बातचीत की, जिसमें उन्होंने यह भी पूछा कि संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए देश चरणों में लॉकडाउन को कैसे हटा सकता है. अब तक सरकार का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बहुत विश्वास से यह नहीं कह रहा कि अप्रैल मध्य तक लॉकडाउन अपने तय समय अनुसार ही समाप्त होगा. लेकिन उनमें से एक ने आश्वासन दिया: ''जब हम सबसे खराब स्थिति से निबटने के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं, तो हमें प्रलय के दिन के परिदृश्य की कल्पना नहीं करनी चाहिए, कोई विनाश नहीं होगा.'' ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनकी बात सच साबित हो और घर में रहते हुए खुद को सुरक्षित रखें. ■

अनुपम नाथ/एपी

बुरे वक्त की तैयारी

राज्य सरकारें और देशभर के अस्पताल कोरोना वायरस संक्रमण की चुनौतियों से निपटने की तैयारी में जुटे. आखिर इस महामारी के खिलाफ जंग में हमारी कितनी तैयारी है?

सोनाली आचार्जी

MAGAZINE KING

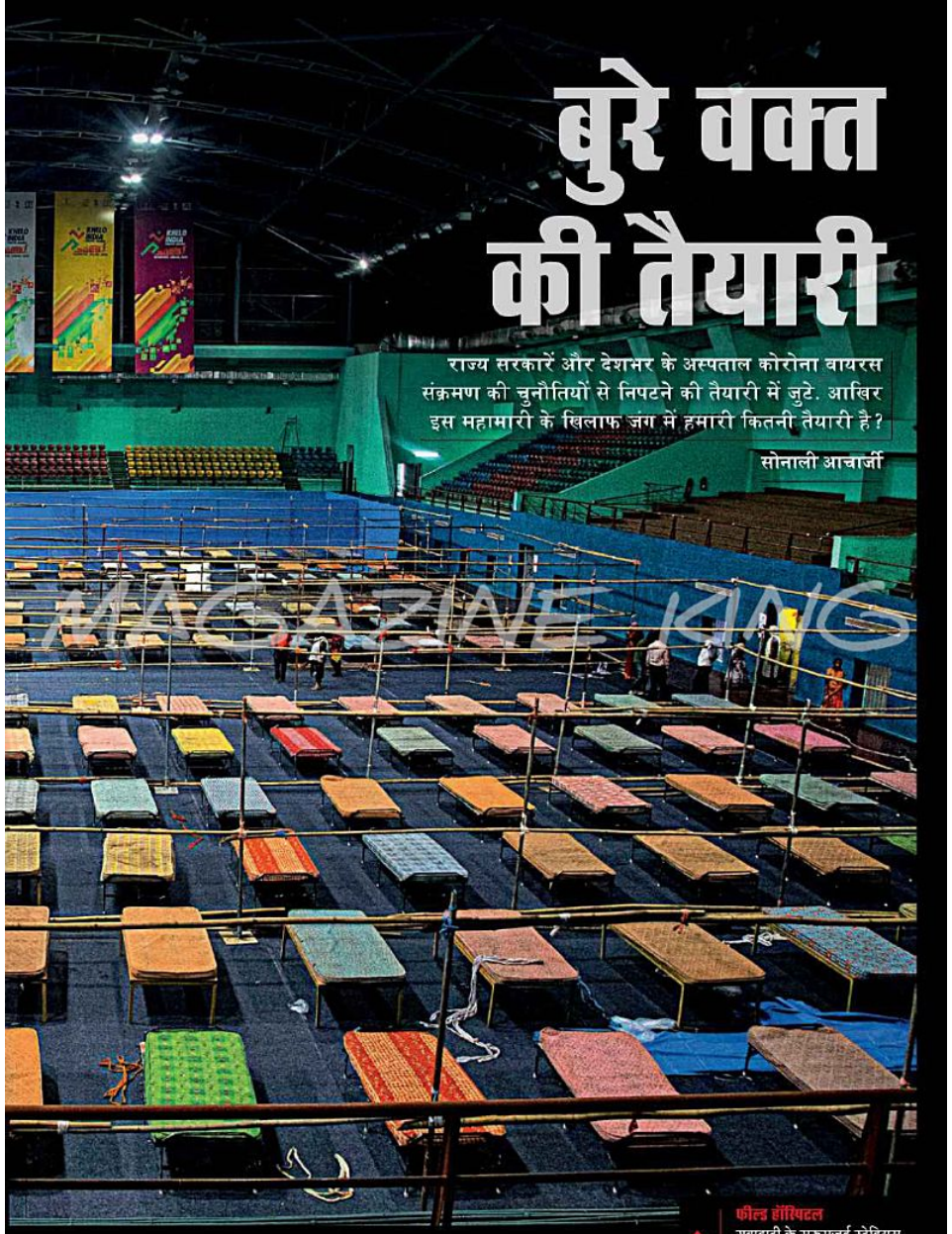

फील्ड हॉस्पिटल
गुवाहाटी के सरुसजई स्टेडियम में कोविड-19 से निपटने के लिए तैयार अस्पताल

कितने तैयार हैं हम?

भारत को जांच और संवेदनशील मरीजों की देखभाल के लिए क्षमताएं बढ़ाने और यह आश्वस्त करने की जरूरत है कि अत्यधिक बोझ से दबे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के पास व्यक्तिगत सुरक्षा के पर्याप्त उपकरण हों. सर्वाधिक आवश्यक प्राथमिकताओं पर एक नजर

जस्थान के जैसलमेर जिले के बांदरी गांव की एक सहायक नर्स (एएनएम) 37 वर्षीया लक्ष्मी मीणा ने इससे पहले कभी संक्रामक रोगों से जुड़ा काम नहीं किया है. उनका सारा प्रशिक्षण टीकाकरण और जच्चा-बच्चा देखभाल का ही रहा है. फिलहाल उनकी देखरेख में 20 परिवार या करीब 300 लोग हैं. लेकिन जब से 600 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा के बीजीएम अस्पताल में कोविड-19 के प्रकोप की खबर आई है, वे सबसे ज्यादा जोखिम श्रेणी की वयोवृद्ध मरीज 73 वर्षीया दादी के साथ अधिक समय बिता रही हैं. भीलवाड़ा में छह चिकित्सा कर्मचारियों सहित 25 लोग कोरोनो वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. क्या वे कोविड-19 की चुनौती के लिए तैयार हैं? मीणा बड़े शांत भाव से जवाब देती हैं, ''समय आने पर मैं अपना पूरा योगदान देने को तैयार हूं.''

वह समय शायद बहुत दूर नहीं है. दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में 2 अप्रैल तक कोरोना संक्रमण के 2015 मामलों और 53 मौतों की सूचना थी, जो दुनियाभर में संक्रमण के 10 लाख से अधिक मामलों और 51,335 मौतों की तुलना में बहुत कम लग सकती है. लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अब तक दुनिया में इस संक्रमण की सबसे कम जांच कराने वाले देश भी हैं. महामारी के इस संकट के भारत में दस्तक देने के चार सप्ताह बाद भी संक्रमण की जांच दर अभी भी प्रति 10 लाख की आबादी पर मात्र 32 (1 अरब की आबादी है और कुल मिलाकर 38,442 टेस्ट हुए हैं) है, जबकि अन्य देश प्रति 10 लाख की आबादी पर 1,000 से ऊपर जांच कर रहे हैं.

27 फरवरी को ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसका शीर्षक था 'भारत में कोरोनो वायरस रोग 2019 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कुशल स्वास्थ्य हस्तक्षेप रणनीति: एक गणितीय मॉडल-आधारित दृष्टिकोण.' रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि इससे दिल्ली में 15 लाख और मुंबई, कोलकाता तथा बेंगलूरू में लगभग 5,00,000 लोगों में रोगसूचक लक्षण उभर सकते हैं. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी की शुरुआत से 200 दिनों के दौरान स्थिति चरम पर पहुंच जाएगी. सबसे विकट स्थिति की भविष्यवाणियां अधिक गंभीर थीं. इसे मुताबिक, दिल्ली में 1 करोड़ और मुंबई में 40 लाख मामले सामने आ सकते हैं और संक्रमण 50 दिनों के भीतर ही सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकता है. व्हाइट हाउस ने अंदेशा जताया है कि यह वायरस अमेरिका में 2,40,000 लोगों का जीवन छीन सकता है.

अगर भारत में संक्रमित लोगों की संख्या अचानक तेजी से बढ़ने लगे तो हम उसके लिए कितने तैयार हैं? न्यूयॉर्क जहां दुनिया के कुछ सबसे बेहतर अस्पताल हैं और जहां आबादी के लिहाज से डॉक्टरों और अस्पताल में बिस्तरों की उपलब्धता सबसे अच्छी है, वहां अब तक 75,000 मामले सामने आ चुके हैं और करीब एक हजार जानें पहले ही जा चुकी हैं. 31 मार्च को तो महज 24 घंटे में ही वहां 300 लोग मरे, जिनमें 18 साल से भी कम आयु का एक मरीज भी शामिल है. यूरोप में, फ्रांस में एक दिन में सबसे अधिक मृत्यु की सूचना मिली है. वहां 31 मार्च को 418 लोग मरे जबकि ब्रिटेन में 28 मार्च से 1 अप्रैल के बीच, मात्र चार दिनों में मरने वालों की संख्या दोगुनी हो गई.

बेशक, मौसम, जनसांख्यिकी और जीन्स

टेस्ट किट

ज्यादातर चिकित्सा पेशेवरों को लगता है कि भारत को और अधिक जांच करने की जरूरत है. मोटे तौर पर देखें तो भारत ने प्रति दस लाख पर 32 टेस्ट किए हैं जबकि ब्रिटेन ने 1,921 और अमेरिका ने 2,600 टेस्ट किए हैं. आइसीएमआर के अंतिम आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार के पास 17 मार्च को 1,50,000 टेस्ट किट थे और 26 मार्च को अमेरिका से 5,00,000 और किट प्राप्त हुए

क्या कदम

- आइसीएमआर ने 7,00,000 परीक्षण किट के लिए निविदा आमंत्रित किए हैं, लेकिन अब तक कोई आदेश नहीं दिया गया है; 16 कंपनियों को भारत में वाणिज्यिक परीक्षण किट बेचने के लिए मंजूरी दे दी गई है

क्या जरूरी

- आइसीएमआर का अनुमान है कि भारत में 7,00,000 परीक्षण किटों की आवश्यकता होगी
- दक्षिण कोरिया में 5.1 करोड़ लोग हैं और वह 2,00,000 से अधिक परीक्षण कर चुका है; भारत में 1.3 अरब लोग हैं लेकिन 1 अप्रैल तक 38,442 परीक्षण ही हुए हैं
- अधिकांश विशेषज्ञ सहमत हैं कि कोविड-19 के प्रसार और संचरण का पता लगाने के लिए, विशेष रूप से वायरल हॉटस्पॉट्स में बड़े पैमाने पर परीक्षण आवश्यक हैं

पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण)

पीपीई सामग्री, जिसमें मास्क, आई शील्ड, गाउन, दस्ताने और जूते के कवर शामिल हैं, कोविड-19 रोगियों के साथ संपर्क करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जरूरी हैं. अब तक, हमारे पास विभिन्न अस्पतालों में 3,34,000 उपलब्ध हैं

वाक चौबंद चेन्नै में नए-नवेले अस्पताल के आइसीयू वार्ड में तैनात स्वास्थ्यकर्मी

अरुण शंकर/गेट्टी इमेजेज

टेस्ट का हाल

टेस्ट किट की अनुपलब्धता और इसके महंगे होने के कारण भारत में बड़ी संख्या में लोगों की जांच करने का लक्ष्य बाधित हुआ

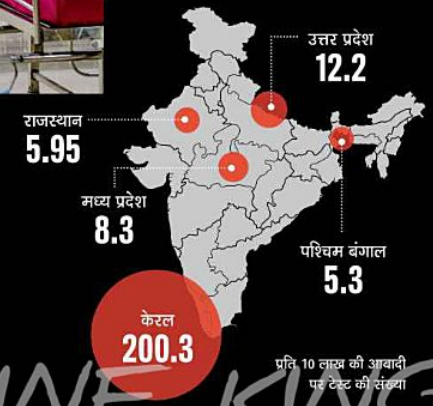

प्रति 10 लाख की आबादी पर टेस्ट की संख्या

MAGAZINE KING

- आइसीएमआर का कहना है कि अब तक 30 फीसद परीक्षण दर्शना का उपयोग किया गया है
- राज्यों के परीक्षण आंकड़ों में भारी अंतर है: केरल ने 7,000 परीक्षण किए हैं, जबकि अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने केवल 2,824 परीक्षण किए हैं.

क्या कदम

- विदेश मंत्रालय के माध्यम से सरकार ने 20 लाख पीपीई किट का आदेश दिया है
- रेड क्रॉस ने 3,00,000 पीपीई किट दान की है
- 15 घरेलू कंपनियों को भारत में पीपीई किट बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया है

क्या जरूरी

- इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को कोविड-19 का सामना करने के लिए 62 लाख पीपीई किट चाहिए
- पीपीई किट का अकेले उपयोग होता है और इस महामारी ने उसका भंडार तेजी से खत्म हो रहा है. भारत के सामुदायिक संक्रमण में प्रवेश करने से पहले पीपीई का एक राष्ट्रीय भंडार आवश्यक है

वेंटिलेटर

कोविड से संबंधित संवेदनशील मरीजों की देखभाल की स्थिति में, जब सांस लेने में तकलीफ को दूर करना होता है, यह संभवतः सबसे जरूरी उपकरण माना जाता है. भारत में लगभग 40,000 वेंटिलेटर हैं, अमेरिका में 1,60,000 हैं और वहां भी कमी महसूस की जा रही है

क्या कदम

- सरकार ने 50,000 वेंटिलेटरों की खरीद के आदेश दिए हैं
- मई तक वेंटिलेटर निर्माताओं से और 50,000 उपलब्ध हो सकते हैं तथा उत्पादन में शामिल होने वाली ऑटो कंपनियों ने भी उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की है

क्या जरूरी

- डॉक्टर भंडार में 1,00,000 वेंटिलेटर तैयार रखने का सुझाव देते हैं. करीब दस फीसद कोविड-19 मरीजों को वेंटिलेटर की आवश्यकता हो सकती है; भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के 10 करोड़ लोग हैं जो सर्वाधिक जोखिम वाली श्रेणी है

आइसीयू

- हमारे पास करीब 1,00,000 आइसीयू बिस्तर हैं. हर राज्य में इसकी संख्या अलग-अलग है. उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में प्रति दस लाख की आबादी पर 2.5 वेंटिलेटर हैं. इतनी ही जनसंख्या वाले इटली में प्रति दस लाख आबादी पर 26 वेंटिलेटर हैं, फिर भी कम पड़ रहे हैं

क्या कदम

- राज्य जिला अस्पतालों को आइसीयू में परिवर्तित कर रहे हैं. कितने बिस्तर तैयार किए गए हैं, इस पर कोई राष्ट्रीय आंकड़ा नहीं है.

क्या जरूरी

- यहां तक कि अगर दस में से एक रोगी को आइसीयू बिस्तर की आवश्यकता होती है, तो हमारे देश में उसकी कमी पड़ जाएगी. शीर्ष डॉक्टरों का कहना है कि मृत्यु दर का अनुपात आइसीयू बिस्तर से जुड़ा हुआ है. जर्मनी में मृत्यु दर 0.3 प्रतिशत है और प्रति लाख लोगों पर 29 आइसीयू बिस्तर हैं. भारत में प्रति लाख लोगों पर 2.3 आइसीयू बिस्तर हैं

डॉक्टर

- अमेरिका स्थित सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स ऐंड पॉलिसी की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 6 लाख डॉक्टरों और 20 लाख नर्सों की कमी है

क्या कदम

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड-19 अस्पतालों में अंतिम वर्ष के मेडिकल छात्रों और सेवानिवृत्त मेडिकल स्टाफ को काम करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है

क्या जरूरी

- कई पश्चिमी देश कोविड-19 मरीजों का इलाज करने की अनुमति विदेशी डॉक्टरों को दे रहे हैं. भारत को डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने और उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता है: स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को तैनाती से पहले सुरक्षा के कदम उठाने की जरूरत है

एएनआइ

की विभिन्नता के कारण अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बीमारी का असर अलग हो सकता है, और हमारे यहां रोग के प्रसार की गति पश्चिम की तुलना में अलग हो सकती है. तीन सप्ताह के राष्ट्रीय लॉकडाउन या पूर्णबंदी ने भी संक्रमित लोगों की संख्या को कम रखने में मदद की है. फिर भी बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि संक्रमण के मामलों की संख्या और मौतें कम बताई जा रही हैं. हालांकि लॉकडाउन स्थायी समाधान नहीं है पर लगता नहीं कि भारत के पास 14 अप्रैल को पूर्णबंद से बाहर आने की कोई रणनीति तैयार है. हालांकि, सामुदायिक फैलाव की आधिकारिक रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन जब समुदाय के स्तर पर वायरस संक्रमण चरम पर होगा तो उससे युद्धस्तर पर लड़ने की जरूरत होगी और उपकरण, विशेषज्ञता में किसी भी प्रकार की कमी मौतों की संख्या बढ़ा सकती है. बात चाहे डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों की संख्या या फिर अस्पताल के बिस्तर और गहन देखभाल के उपकरणों की हो, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का बुनियादी ढांचा पहले से ही चरमराया दिखता है और कोविड-19 की नई चुनौतियों—चाहे वह परीक्षण किट हों या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण—के बाद देश को हर मोर्चे पर एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी. अगले कुछ दिनों में, हमें आवश्यक और विश्वसनीय-गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों के एक बड़े राष्ट्रीय भंडार का निर्माण करना होगा, परीक्षण बढ़ाना होगा और बीमारी के चरण 3 के लिए तैयार रहना होगा. सौभाग्य से, हमारे पास सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए दो सप्ताह का वक्त है. अंतिम-वर्ष के मेडिकल छात्रों और सेवानिवृत्त डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ जिन्होंने स्वेच्छा से मदद की पेशकश की है, वाहन बनाने वाली कंपनियों ने वेंटिलेटर बनाने की पेशकश करके—यानी हर कोई इसे रोकने के लिए जी-जान से जुट गया है. राज्यों में स्टेडियमों, होटलों, स्कूलों और यहां तक कि रेल के डिब्बों को भी अस्थायी अस्पतालों के रूप में बदला जा रहा है. क्या यह पर्याप्त होगा?

“अगर कोरोना का कहर बरपा तो मुझे वेंटिलेटर का ऑर्डर देने में 15 दिन लगेंगे लेकिन इसके लिए देश में इनका उपलब्ध होना भी जरूरी है.”

-डॉ. अयाज तंबोली
जिला कलेक्टर, बस्तर छत्तीसगढ़

पीपीई: तैयारी नहीं है पूरी

पीपीई या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) किट जिसमें एक मास्क, आंखों के लिए सुरक्षा कवच, जूते का कवर, एक गाउन और दस्ताने शामिल हैं, न केवल डॉक्टरों के लिए बल्कि उन सभी चिकित्सा कर्मचारियों के लिए भी आवश्यक हैं जो न केवल कोविड-19 रोगियों के साथ बल्कि अन्य रोगियों के संपर्क में भी हैं. ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर आशा वर्कर्स की राष्ट्रीय संयोजक रंजना निरुला आशा (एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट) कार्यकर्ताओं को भी पीपीई देने की हिमायती हैं. देश के विभिन्न राज्यों में 9,00,000 आशा वर्कर्स हैं जो समाज तक पहुंचने का माध्यम हैं. रंजना कहती हैं, “आशा औपचारिक तंत्र का हिस्सा नहीं हैं लेकिन संभावित संक्रमित व्यक्ति की तलाश में घर-घर जाने से उन पर भी खतरा है.” हालांकि, महाराष्ट्र में जब वार्ड बॉय, नर्स और हेल्थ वर्कर्स के बीच ड्यूटी पर जाने के लिए पीपीई किट्स मांगने लगे तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने उनसे कहा, “पीपीई सिर्फ उन डॉक्टरों, नर्सों और वार्ड बॉयज के लिए हैं जो आइसोलेशन वार्ड में मरीज देखते हैं.” डॉक्टर और एक नर्स के कोविड-19 पॉजिटिव निकलने पर 1 अप्रैल को पीजीआइएमईआर (पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऐंड रिसर्च) और जीएमसीएच (गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐंड हॉस्पिटल) के डॉक्टर,

MAGAZINE KING

कैसी जांच दिल्ली से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे लोगों की 27 मार्च को लाइन लगाकर थर्मल स्क्रीनिंग की गई

45 नर्सें और अन्य चिकित्सा स्टाफ को क्वारंटीन किया गया था. मुंबई के वोकहार्ट अस्पताल में एंजियोप्लास्टी के लिए आए 70 साल के बुजुर्ग के संपर्क में आने से दो नर्सें कोविड-19 पॉजिटिव निकलीं. इटली में अस्पताल स्थानीय संक्रमण के प्रमुख अड्डे बने हुए हैं, जहां ऐसे 1,00,000 मामले आए. निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी, इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को कोविड-19 का मुकाबले करने के लिए 3.8 करोड़ मास्क और 62 लाख पीपीई किट की आवश्यकता होगी. हमारे पास वास्तव में विभिन्न अस्पतालों में लगभग 3,34,000 किट ही उपलब्ध हैं.

मार्च की शुरुआत में देश के सबसे प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान, दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में पीपीई की कमी हो गई थी और डॉक्टरों के अपने स्तर पर हाथों पर लगाने के लिए सैनिटाइजर और प्लास्टिक शीट से फेस मास्क बनाने की सूचना मिली थी. 24 मार्च को, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने विभिन्न विक्रेताओं से संपर्क साधा. तब से भारत डायनेमिक्स ने 50 लाख रुपए, पॉस्को इंडिया ने 10 लाख रुपए और अस्पताल सीएसआर फंड ने एम्स में पीपीई किट के लिए 60 लाख रुपए का योगदान दिया है. हालांकि, अगर भारत, स्टेज-3 तक पहुंचता है, तो इसकी प्रतिक्रिया का समय महत्वपूर्ण होगा. जैसा कि राजस्थान के बाड़मेर मेडिकल कॉलेज ऐंड हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर एन.एन. सोनी अपने राज्य के बारे में कहते हैं, ''राजस्थान में अभी मामले कम हैं, लेकिन इस मौके का उपयोग पीपीई का स्टॉक बनाने के लिए करना चाहिए. आप संकट की इस घड़ी में सुरक्षा उपकरणों की कमी से डॉक्टरों को गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं.''

❝ भारत को पीपीई का उत्पादन युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता है.''

-डॉ. एन.एन. माथुर

डायरेक्टर, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली

सरकार ने पहले ही 15 घरेलू कंपनियों को पीपीई बनाने के लिए मंजूरी दे दी है और 26 लाख किट का ऑर्डर दिया है. दक्षिण कोरिया की एक कंपनी को 20 लाख किट के ऑर्डर दिए गए हैं. दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ऐंड हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. एन.एन. माथुर कहते हैं, ''अभी हमारे पास इसकी बड़ी कमी है. हमें अगले छह महीनों के लिए निरंतर और निर्बाध आपूर्ति की आवश्यकता है. राज्य सरकारों को कमी का साप्ताहिक हिसाब लेना चाहिए और इसे पूरा करने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास करना चाहिए.'' कुछ राज्यों ने उपाय करने शुरू कर दिए हैं. पिछले पांच दिनों में, बिहार में चिकित्सा पेशेवरों को 6,165 पीपीई किट जारी किए गए हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, संजय कुमार कहते हैं, ''कोई कमी नहीं है.''

गहन चिकित्साः जीवनरक्षक साधनों की जरूरत

कई सार्वजनिक स्वास्थ्य विश्लेषकों ने देशों में मृत्यु दर को आइसीयू बेड की संख्या से जोड़ा है. जर्मनी में प्रति 1,00,000 नागरिकों पर 29 आइसीयू बेड उपलब्ध हैं और मृत्यु दर 0.3 प्रतिशत है. इसके विपरीत इटली में प्रति 1,00,000 पर 13 बेड हैं और मृत्यु दर 9.26 प्रतिशत है. भारत में, प्रति 1,00,000 नागरिकों पर केवल 2.3 आइसीयू बेड हैं. यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि देश में 10 करोड़ से अधिक 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं, जिन्हें कोविड-19 से सबसे अधिक खतरा हो सकता है.

इस पर ध्यान देते हुए सरकार ने जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में आइसीयू सुविधाएं बढ़ाने के लिए कहा है. महाराष्ट्र में सांगली जिले के सिविल सर्जन डॉ. संजय सालुंखे का कहना है कि उन्होंने कोविड-19 रोगियों के लिए मिरज में 315-बेड वाला अस्पताल आरक्षित कर दिया है. वे बताते हैं, ''हम अन्य सभी रोगियों का इलाज सांगली शहर के सामान्य अस्पताल

कर रहे हैं. मिरज अस्पताल विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों के लिए होगा.''

लेकिन बिना वेंटिलेटर वाले आइसीयू पर्याप्त नहीं होंगे. यह अनुमान है कि सभी कोविड-19 रोगियों में से करीब 10 प्रतिशत को गहन चिकित्सा की आवश्यकता होगी जिसमें वेंटिलेटर पर रखना शामिल है. डॉक्टरों का कहना है कि 1,00,000 का एक राष्ट्रीय भंडार तैयार किया जाना चाहिए क्योंकि महामारी की स्थिति में वेंटिलेटर का पर्याप्त संख्या में निर्माण, शिपिंग और उनको लगाना संभव नहीं होगा. अमेरिका में लगभग 1,60,000 वेंटिलेटर हैं और कई जगहों पर इनकी कमी हो गई है. छत्तीसगढ़ में बस्तर के जिला कलेक्टर डॉ. अयाज तंबोली कहते हैं, ''हमारे पास एक अलग प्रवेश द्वार के साथ कोविड-19 के लिए 200 बेड का अस्पताल है, लेकिन केवल छह वेंटिलेटर उपलब्ध हैं. हम राज्य में पीपीई का निर्माण कर रहे हैं, हमें वेंटिलेटर का निर्माण करने की भी आवश्यकता है.''

सरकार पहले ही चीन से 10,000 वेंटिलेटर मंगाने का ऑर्डर दे चुकी है. भारत में नोएडा की कंपनी एग्वा हेल्थकेयर को 10,000 ऑर्डर मिले हैं और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी 30,000 वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर दिया गया है. घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की भी योजना है. देश की अग्रणी वेंटिलेटर निर्माता कंपनी स्कैनरे टेक्नोलॉजीज ने प्रति माह 2,000 वेंटिलेटर निर्माण की अपनी सामान्य क्षमता को मई तक बढ़ाकर 30,000 यूनिट प्रति माह करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा समूह के साथ साझेदारी की है. उम्मीद है, इससे स्थिति कुछ सुधरेगी.

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉ. माथुर की सलाह है, ''अस्पतालों का बोझ घटाने और संक्रमण रोकने का एक तरीका है मरीजों के दाखिले की नीति बदल दी जाए. हमें हर कोविड-19 रोगी के लिए सक्रिय रूप से उपचार देने की आवश्यकता नहीं है—हल्के लक्षणों वाले लोगों को घर पर या कोविड-19 उपचार केंद्र में आइसोलेट करके रखा जाना चाहिए. इससे गंभीर रूप से बीमार रोगियों की देखभाल के लिए अस्पताल के पास संसाधन उपलब्ध रहेंगे.''

जांचः कछुए की चाल

डॉ. माथुर का कहना है, ''डेटा के बिना, आप युद्धस्तर की कोई योजना नहीं बना सकते हैं.'' दक्षिण कोरिया की जनसंख्या 5.1 करोड़ है और उसने अपने कोविड-19 प्रकोप से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर जांच शुरू कर दी. वहां 2,70,000 लोगों की जांच की गई—और इसकी सबसे तेज प्रयोगशाला एसडी बायोसेंसर में प्रति सेकंड 2.5 टेस्ट किट का निर्माण हो रहा है. दूसरी ओर, टेस्ट की कम दरों के लिए भारत की आलोचना हो रही है. यहां तक कि देश के भीतर भी, काफी अंतर देखा जा सकता है. जहां केरल ने अब तक 7,000 टेस्ट किए हैं, उससे काफी अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में केवल 2,800 परीक्षण हुए हैं. कम परीक्षण दर शायद टेस्ट किट की कमी के कारण है. यह महसूस करते हुए सरकार ने दो कंपनियों—मायलैब्स और एल्टन डायग्नोस्टिक्स को टेस्ट किट का उत्पादन करने की अनुमति दी है. देश में बेची जाने वाली किसी भी दवा या डायग्नोस्टिक किट को अंतिम मंजूरी देने वाले संस्थान सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने किट बेचने की प्रक्रिया को भी तेज किया है. भारत

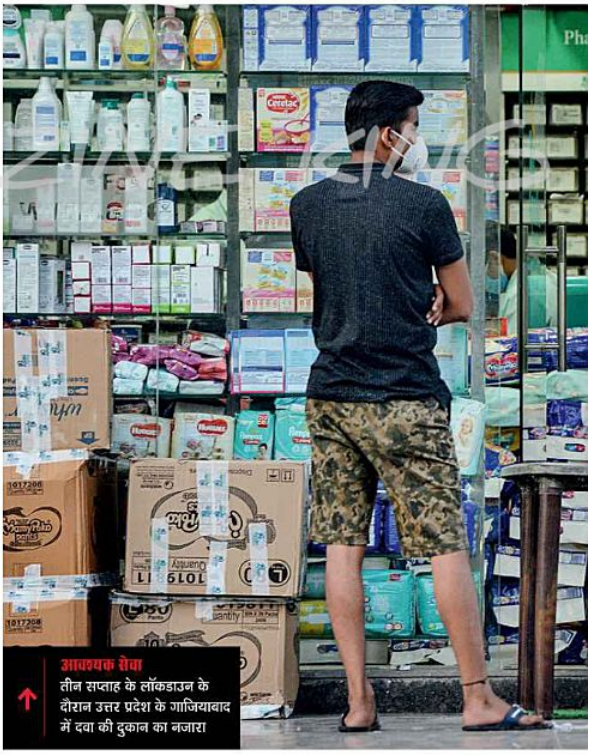

आवश्यक सेवा
तीन सप्ताह के लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दवा की दुकान का नजारा

ने घरेलू स्तर पर 16 टेस्ट किट की बिक्री की मंजूरी दी है.

हालांकि, दो सप्ताह पहले वाणिज्यिक किट के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन डिलिवरी को लेकर अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है. डॉ. डैंग्स लैब्स के सीईओ और पैथोलॉजिस्ट डॉ. अर्जुन डैंग कहते हैं, ''हमने कुछ सौ परीक्षण किए हैं और हम नियमित रूप से सभी परिणामों को आइसीएमआर के इंटर्नल पोर्टल पर अपलोड करते हैं.'' आइसीएमआर ने भारत में 16 निजी प्रयोगशालाओं के लिए एफडीए—और यूरोपीय सीई पर खरे परीक्षण किट के उपयोग को मंजूरी दे दी है. यह केवल स्टैंडर्ड आरटी पीसीआर (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज चेन रिएक्शन) टेस्ट के लिए है जो गले के स्वैब में आरएनए (वायरस का आनुवंशिक मटीरियल) का पता लगाता है. नए कोरोना वायरस का आनुवांशिक क्रम अन्य कोरोना वायरसों जैसे कि सामान्य जुकाम या गंभीर सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (सार्स) से अलग है. आरएनए परीक्षण महंगा और श्रमसाध्य है क्योंकि इसमें प्रयोगशाला सुविधाओं, प्रशिक्षित

“कोविड-19 की दवा सिर्फ डॉक्टर के पर्चे के आधार पर ही बेची जाए”

-टी. नारायण

प्रेसिडेंट, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन

चंद्रदीप कुमार

कर्मियों और परीक्षण किट की आवश्यकता होती है. अभी, इन परीक्षण किटों की वैश्विक स्तर पर कमी भी है.

डॉ. डैंग कहते हैं, ''जांच से दो चीजों में मदद मिलती है- हर्ड इम्यूनिटी (समूह की प्रतिरक्षा) और स्पर्शोन्मुख तथा रोगसूचक वाहक के माध्यम से संक्रमण के प्रसार को मापने में. आरएनए जांच संक्रमण की पुष्टि करने वाली जांच है. सीरोलॉजी जांच या तीव्र जांच भी की जाती है जो रक्त के नमूने में ऐंटीबॉडी की तलाश करते हैं.'' सीरोलॉजी जांच में कम समय लगता है और भारत के पास इस जांच की ज्यादा सुविधाएं हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआइवी), पुणे ने आइसीएमआर को रैपिड टेस्ट किट प्रदान करने के लिए दो कंपनियों—सिंगापुर स्थित सेंसिंग सेल्फ लिमिटेड और चीन की वोंड्फो को मंजूरी दे दी है, जिसने घोषणा की है कि यह समूह प्रतिरक्षा के लिए सेरोलॉजी जांच शुरू करेगी. रोगसूचक लोगों को ऐंटीबॉडी के लिए जांच की जा सकती है और जांच में जो लोग संक्रमित पाए जाते हैं उनकी पुष्टि एक और पीसीआर परीक्षण से की जा सकती है.

कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के रक्त में ऐंटीबॉडी होंगे, पीसीआर पता लगाता है कि यह नया कोरोना वायरस है या नहीं. न केवल भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा जांच की आवश्यकता है कि स्पर्शोन्मुख वाहक संक्रमण नहीं फैलाते हैं बल्कि इसे भारत में वायरस की प्रकृति और इसकी पहुंच को भी समझने के लिए भी जांच की संख्या बढ़ाने की जरूरत है.

जन औषधि केंद्र

ऐन मौके पर मास्क गायब

महामारी के समय जन औषधि केंद्रों से नदारद मास्क, अधिकारी कह रहे निर्माता कंपनियों ने दिया धोखा

खाली हाथः एक जन औषधि केंद्र से बिना मास्क लौटता शख्स

राजेश कुमार

मार्च के आखिरी हफ्ते में कोरोना वायरस से जंग के लिए लॉकडाउन शुरू होते ही लोग दवा दुकानों में मास्क और सैनिटाइजर खरीदने के लिए टूट पड़े. 14-15 रु. में बिकने वाले सामान्य मास्क की कीमत 50-60 रु. तक पहुंच गई. एन-95 मास्क की कीमत 60-65 रु. से बढ़कर 200-300 हो गई. प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत चलने वाले जन औषधि केंद्रों की तरफ भी लोगों ने रुख किया लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा.

गाजियाबाद के वैशाली में रहने वाली 45 वर्षीया इंजीनियर प्रभा श्रीवास्तव ने घर के सभी पांच सदस्यों के लिए एन-95 मास्क खरीदे. उन्हें पांच मास्क की कीमत 1,500 रु. चुकानी पड़ी. प्रभा को अचानक जन औषधि केंद्रों की याद आई. उन्होंने अपने ड्राइवर और घर में काम करने वाली सविता के साथ उनके घरवालों के लिए भी मास्क खरीदने का मन बनाया. लक्ष्मीनगर, इंद्रापुरम, वैशाली से लेकर दिलशाद गार्डन और अंत में दिल्ली के शास्त्री भवन में मौजूद जन औषधि केंद्र में उन्होंने मास्क के लिए चक्कर लगाए लेकिन किसी भी केंद्र में मास्क नहीं मिला. सभी केंद्र मालिकों का जवाब था कि पिछले करीब दो-ढाई महीनों से मास्क की आपूर्ति बंद है. सैनिटाइजर जन औषधि केंद्र में उपलब्ध दवाइयों की सूची में है ही नहीं.

शालीमार बाग में स्थित जन औषधि केंद्र के मालिक राजू सिंह कहते हैं, ''हमारे यहां 1.50 रु. में मास्क मिलता है. लेकिन पिछले ढाई महीने से मास्क की सप्लाई नहीं हुई. हम नोडल ऑफिसर से कह-कहकर थक गए. तीन बार ई-मेल भी कर चुके हैं.'' दिल्ली के अशोक नगर में मौजूद जन औषधि केंद्र के मालिक जय राम कहते हैं, ''चीन में बढ़ते संकट को देख हमने विभाग को मास्क के साथ सैनिटाइजर मुहैया करवाने के लिए जनवरी के पहले ही हफ्ते में लिखा था. लेकिन जवाब मिला कि सैनिटाइजर हमारी दवाओं की सूची में नहीं, मास्क की आपूर्ति जल्द होगी.''

जय राम कहते हैं, ''जब जन औषधि केंद्र मालिकों को यह बात समझ आ रही थी की सैनिटाइजर और मास्क की मांग आगे बढ़ेगी तो फिर विभाग इससे अनजान कैसे था?'' जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के एस.पी शर्मा भी लगभग यही हालात बयान करते हैं.

कर्नाटक के मांड्या जिले में केंद्र मालिक सिद्धाराजू ने भी पिछले तीन महीने से मास्क की आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं. जन औषधि केंद्र के एक मार्केटिंग अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, ''हमारे पास खबर थी कि निजी दवा कंपनियां उन मास्क कंपनियों के संपर्क में हैं जो हमें भी मास्क आपूर्ति करती हैं. निजी कंपनियों ने उन्हें दिसंबर के आखिर में ही ज्यादा मात्रा में मास्क बनाने के ऑर्डर दे दिए थे. लेकिन सरकारी विभाग सोता रहा.''

''रोजाना 1.5 करोड़ मास्क बनाए जा रहे हैं. पूरे देश में मास्क आपूर्ति करने पर हमारा ध्यान है, इसमें जन औषधि केंद्र भी शामिल हैं''

-मनसुख मांडविया
केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री

उधर, जन औषधि विभाग में ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूएस ऑफ इंडिया (बीपीपीआइ) के सीईओ सविन कुमार सिंह का कहना है, ''अचानक मांग में आई तेजी की वजह से यह दिक्कत आ रही है. जहां 10,000 मास्क महीने में जरूरत पड़ती थी, वहीं अब यह मांग बढ़कर डेढ़ करोड़ हो गई. हमें तीन कंपनियां मास्क सप्लाई करती हैं. लेकिन अचानक कंपनियों ने सप्लाई बंद कर दी. हमने इन्हें नोटिस भेजे हैं. अगर सप्लाई शुरू नहीं होती तो नियम के मुताबिक 45 दिन में उन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.''

पूछने पर कि निर्माता कंपनियां मास्क ब्लैक में सप्लाई कर रही हैं? वे कहते हैं, संभव है कि निर्माता कंपनियां ज्यादा मुनाफे के चक्कर में ऐसा कर रही हों. सैनेटाइजर के जन औषधि केंद्रों की दवाई की सूची में जोड़ने के सवाल पर वे कहते हैं, इतनी जल्दी कोई सरकारी फैसला नहीं होता.

उत्तर प्रदेश में जन औषधि विभाग के एक अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं, ''यह हाल केवल महामारी के समय में नहीं है बल्कि डेंगू, स्वाइन फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों के समय भी रहता है. हर बार मांग के मुकाबले सप्लाई कम होती है.''

देश में मौजूदा समय में 6,200 जन औषधि केंद्र हैं. लेकिन सवाल उठता है कि हेल्थ इमरजेंसी के समय अगर ये केंद्र अपाहिज हो जाएंगे तो फिर गरीबों तक सस्ती दवा पहुंचाने के वादे का क्या होगा?

– संध्या द्विवेदी

उपचार: बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं

30 मार्च को गुवाहाटी में एक वरिष्ठ एनेस्थेटिस्ट, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) ले रहे थे, की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. इससे पहले व्हाट्सऐप मैसेज पर बातचीत में उन्होंने अपने सहयोगियों को बताया था कि दवा लेने के बाद से उन्हें तकलीफ हो रही थी. स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए आइसीएमआर ने मलेरिया-रोधी दवाएं लेने का परामर्श दिया है लेकिन इसकी ओवरडोज या अत्यधिक रिऐक्शन विशेष चिंता का विषय है. आइसीएमआर की घोषणा के बाद दवा बाजार से गायब हो गई है लेकिन दवा के मुख्य उत्पादक सिप्ला ने 30 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में लगभग 50 लाख टैबलेट बाजार में भेज दी हैं.

डॉ. नारायण कहते हैं, ''कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है, इसलिए कोई यह ठीक-ठीक नहीं कह सकता है कि कौन सी दवाएं काम करती हैं. लेकिन अब तक डॉक्टर वायरस की शृंखला को तोड़ने के लिए एचआइवी की दवाएं लोपिनेवीर और रिटोनेवीर का, तेज बुखार के लिए पेरासिटामोल, निमोनिया के मामले में शरीर की प्रतिरक्षा सुधारने के लिए एचसीक्यू और निमोनिया में कुछ अन्य दवाओं का उपयोग कर रहे हैं.'' यह आमतौर पर पांच दिन का कोर्स होता है, जिसे लक्षणों के आधार पर बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, कोविड-19 के लिए सभी दवाओं को केवल डॉक्टरों के पर्चे पर ही बेचे जाने की जरूरत है, ताकि दुरुपयोग, खुद से इलाज की प्रवृत्ति को रोका जा सके और अस्पतालों के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सके.

''आने वाले सप्ताहों में हाई रिस्क क्षेत्रों को आइसोलेट करने की जरूरत होगी. क्लस्टर वाले नजरिये से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर संक्रमण रोका जा सकता है''

-डॉ. नागेश्वर रेड्डी

चेयरमैन, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी

लॉकडाउन के बाद की रणनीति की जरूरत

भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में, जहां लगभग 20 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, आपदा नियोजन और प्रबंधन उपलब्ध संसाधनों के रूप में बड़ी भूमिका निभाते हैं. करीब 2,00,000 प्रवासियों के भारत भर से अपने गांवों और गृहनगर के लिए कूच करने के साथ तीन सप्ताह के राष्ट्रीय स्तर की पूर्णबंदी के बावजूद ग्रामीण भारत के लिए जोखिम बहुत वास्तविक है. कई अर्थशास्त्री और डॉक्टर अब सलाह दे रहे हैं कि पूरे देश के लॉकडाउन की जगह केवल उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन किया जाए. 1.3 अरब लोगों को नियंत्रित करने से ज्यादा व्यवहार्य होगा संक्रमण प्रसार वाले क्षेत्र के कुछ हजार लोगों के बीच स्थिति को नियंत्रण में रखना. हैदराबाद स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के चेयरमैन डॉ. नागेश्वर रेड्डी कहते हैं, ''कोविड-19 आम जुकाम की तुलना में 10 गुना अधिक संक्रामक है और इससे मृत्यु दर 10 गुना अधिक है, इसलिए लॉकडाउन की आवश्यकता तो है लेकिन पूरे देश के लिए नहीं. एक क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण संसाधनों को प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने में काफी मददगार होगा.''

राष्ट्रीय राजधानी का निजामुद्दीन इलाका सरकार के पूर्णबंदी के बाद एक उच्च जोखिम वाले क्षेत्र का पहला उदाहरण बन गया है. इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि तबलीगी जमात का मुख्यालय कोरोना वायरस संक्रमण का एक स्रोत था, जिसके परिणामस्वरूप संक्रमण के 35 पॉजिटिव मामले सामने आए और देश में नौ मौतें हुईं. 30 मार्च की सुबह लगभग 300 खाली प्लास्टिक की बोतलें, जिसमें से प्रत्येक में 20 लीटर सैनिटाइजर आता है, दिल्ली में निजामुद्दीन बस्ती के एक छोर पर खाली पड़ी थीं. उसके बाद दो दिनों में क्षेत्र में 30,000 लीटर कीटाणुनाशक का छिड़काव किया गया और 1,500 लोगों को वहां से बाहर निकाला गया. मार्च के पहले सप्ताह में जमात की एक सभा में 2,000 लोग शामिल हुए थे जिनमें कुछ अन्य देशों से आए लोग भी थे.

''हर्ड इम्यूनिटी जांचने के लिए सेरोलॉजी टेस्ट कारगर है. इससे पीसीआर टेस्ट का दबाव घटेगा.''

-डॉ. अर्जुन डेंग

सीईओ और पैथोलॉजिस्ट डॉ. डेंग्स लैब्स

1 अप्रैल को केंद्र ने 10 हॉटस्पॉट की एक सूची जारी की जहां वायरस का संक्रमण अधिक है. इसमें दिल्ली में दिलशाद गार्डन और निजामुद्दीन, उत्तर प्रदेश में नोएडा और मेरठ, राजस्थान में भीलवाड़ा, अहमदाबाद, केरल में कासरगोड और पत्तनमथिट्टा, मुंबई और पुणे शामिल हैं. ये हॉटस्पॉट जांच और अन्य चिकित्सा संसाधनों के लिए लक्षित करने और संक्रमण को अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोकने में उपयोगी होंगे.

बहरहाल, भारत में अभी तक कोविड-19 का वैसा संक्रमण नहीं हुआ है जैसा पश्चिमी देशों इटली, स्पेन आदि में देखा जा रहा है. लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थिति बदल सकती है. इस बीच, हमें अपने स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने की जरूरत है अन्यथा एक ऐसी स्थिति पैदा होने का खतरा है जहां हमारे पास डॉक्टरों, आइसीयू, लैब और आइसोलेशन वार्ड की तुलना में कोविड-19 के कहीं अधिक मरीज होंगे. यह एक लंबी लड़ाई है और लड़ाई एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ है जो अज्ञात और अपराजेय दोनों है. दवा खोजे जाने तक ठोस, बहुस्तरीय रणनीति के बिना हालात से निपटना मुश्किल काम लगता है. लेकिन हम अपनी तैयारी चुस्त करने में कोताही नहीं बरत सकते.

—साथ में, **अमिताभ श्रीवास्तव** और **किरण डी. तारे**

पलायन का दर्द

शौगत दासगुप्ता

अपने भरोसे अपने गांव-घर की ओर कूच करते मजदूर दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के पास

रोजगार, घर या भोजन से महरूम शहरों में फंसे, समूचे देश से प्रवासी मजदूर अपना थोड़ा-बहुत सामान लादे, भूख से बेहाल, थके-मांदे बच्चों के साथ पैदल या बसों में पशुओं की तरह ठूंसकर अपने गांव की ओर लौटने को मजबूर, जहां 'सोशल डिस्टेंसिंग' की कोई गुंजाइश नहीं, उनके बुझे हुए चेहरे गवाह हैं कि कोविड-19 ने कितनी भारी उथल-पुथल मचा दी

MAGAZINE KING

कमर सिब्तैन / मेल टुडे

MAGAZINE KING

असहाय उत्तर प्रदेश में आगरा जाने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करके 28 मार्च को बस पकड़ने ग्रेटर नोएडा में परी चौक पहुंचे कुछ परिवार, लेकिन कोई बस नहीं आई

बंदीप सिंह

प्रवासी मजदूर

शा

हरों की तंग गलियों के अपने अंधेरे कमरों से निकलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव के घरों की ओर पैदल ही निकल पड़े लोगों में से कितनों ने सफर के बीच ही अपना दम तोड़ दिया, इसकी कोई आधिकारिक संख्या तो उपलब्ध नहीं है, पर विभिन्न रिपोर्ट कम से कम 20 मौतों की आशंका जताती हैं. यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है. डरे, भूखे और हताश ये प्रवासी श्रमिक खुद को अपनी सरकारों की ओर से पूरी तरह बदहाल छोड़ दिए महसूस कर रहे हैं. अपने बच्चों और थोड़े-बहुत सामान के साथ चप्पल पहने सड़कों पर पैदल चलते लोगों के हुजूम का दृश्य दुनिया भर में देखा गया. उनके पास कई दिनों की अपनी यात्रा के लिए खाने का पर्याप्त सामान भी नहीं है. अधिकतर को बीच में ही रोक लिया जा रहा है और शिविरों में रखा जा रहा है, अब केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे अपनी सीमाओं को सील कर दें.

देश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन, शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोविड-19 के विरुद्ध कथित युद्ध में मोर्चा संभाल रहे लोगों के सम्मान में दिखावटी-उत्सव में बर्तन पीटकर कृतज्ञता जताई थी. उसके बाद कुछ ही दिनों में देखा गया कि अचानक घर, आमदनी, भोजन से वंचित हो गए मजदूर हताशा में पुलिस की बाधाओं को पार करते हुए अपने परिवार के साथ रात के अंधेरे में और दोपहर की गर्मी में भी लंबी यात्रा पर निकल पड़े. इनकी तस्वीरें मन को झकझोर रही थीं. यह दृश्य बताता है कि कोविड-19 ने लोगों की जिंदगी में कितना तूफान ला दिया है.

38 साल के मुन्ना महतो बेंगलूरू में स्थायी नौकरी कर रहे थे और वे 18,000 रुपए प्रति माह कमाते थे. लेकिन इस महामारी के कारण उनकी नौकरी चली गई. आय का कोई साधन नहीं होने के कारण, वे और वहां से 2,000 किलोमीटर दूर बिहार के अपने गांव के तीन अन्य लोगों के साथ, जनता कर्फ्यू से एक दिन पहले रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से रांची जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए. उनकी योजना रांची पहुंचने के बाद भागलपुर के लिए दूसरी ट्रेन लेने की थी. लेकिन अगले ही दिन, प्रधानमंत्री ने 21 दिन की पूर्णबंदी की घोषणा कर दी. इन तीनों को आगे के लिए साधन नहीं मिला तो उन्होंने रांची से आगे का रास्ता पैदल ही तय करने की कोशिश की. पर पुलिस ने उन्हें बीच में पकड़ लिया और सरकारी आश्रय केंद्र में पहुंचा दिया. यह कहते हुए मुन्ना रो पड़ते हैं कि उनके बच्चे उनके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें बच्चों के पास जाना है. वे अब बेंगलूरू में नहीं रहना चाहते और परिवार के लिए बचाए पैसे को उन्हें खर्च करना पड़ रहा है. उन्हें मालूम है कि वे फिर से ये पैसे नहीं कमा पाएंगे, कम से कम निकट भविष्य में तो नहीं.

> **“गरीबों के लिए यह लॉकडाउन तो दोहरी मार साबित हुआ है. वे तंग कमरों में रहते हैं. आखिर, उनकी कमाई भी बंद हो गई तो वे जिंदा कैसे रहेंगे?”**
>
> –रीतिका खेड़ा
> *विकास अर्थशास्त्री, आइआइएम अहमदाबाद*

इसी तरह 45 वर्षीया विधवा कमला देवी कानपुर में एक पान मसाला कारखाने में काम करती थीं. कंपनी ने 22 मार्च को अपने इस ठेका मजदूर को काम से हटा दिया. अपने पास बचे ‘बहुत कम पैसे’ से उन्हें 10 साल से कम उम्र के तीन बेटों की देखभाल करनी थी. इसलिए उन्होंने बहराइच के अपने गांव जाने की कोशिश की. चार दिन तक पैदल यात्रा करके 28 मार्च की सुबह कमला और उनके बेटे लखनऊ के चारबाग बस अड्डे तक पहुंचे तो वहां उन्हें उनकी ही तरह, हजारों अन्य लोग अपने घर तक पहुंचने के लिए बसों की प्रतीक्षा करते दिखे. उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 1,000 बसों की व्यवस्था की थी; दिल्ली सरकार ने भी बसों की व्यवस्था की थी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवासी श्रमिकों को उनके घर लौटने से रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम न करने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों ने आलोचना की. रात 8 बजे नाटकीय रूप से देशव्यापी बंद की अपनी घोषणा से पहले इसकी कोई पूर्व तैयारी न करने वाली केंद्र सरकार ने भी पल्ला झाड़कर सारा दोष दिल्ली सरकार पर डालने की कोशिश की. पर श्रमिकों की ऐसी कहानियां सिर्फ दिल्ली के आसपास ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, देशभर में बिखरी पड़ी हैं.

अपनी सीमाओं में लोगों को भोजन, घर

और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और इसमें चूक के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है. पर देश के श्रमिकों, चाहे वे प्रवासी मजदूर हों या सड़कों पर रोज कमाने और रोज खाने वाले लाखों लोग, उनके लिए अचानक चिंता की घंटी बजाने में केंद्र की भूमिका को लेकर भी वाजिब सवाल पूछे जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साक्षात्कारों में कहा है कि पूरी तरह से बंदी को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्यों की है इसलिए केंद्र को पहले राज्यों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए था. उन्होंने तंज के लहजे में पूछा, ''प्रधानमंत्री ने एकतरफा घोषणा करने से पहले किसी भी राज्य सरकार से बात की थी?'' अपने क्रूर आदेशों के गरीबों पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने में विफल रहने और घोर लापरवाही के लिए प्रथम दृष्ट्या केंद्र को दोषमुक्त नहीं ठहराया जा सकता है.

श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कल्याण योजनाओं के तहत उपकर के रूप में प्राप्त 52,000 करोड़ रुपए की राशि को निकालकर निर्माण क्षेत्र के करीब 3.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों के खाते में डालने का निर्देश दिया है. पर लाखों श्रमिक अपंजीकृत हैं और ऐसे में वे इस राहत राशि के पात्र नहीं हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1.7 लाख करोड़ रु. के प्रोत्साहन पैकेज को तत्काल राहत देने में अपर्याप्त बताते हुए कई विश्लेषकों ने आलोचना की. अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने एक साक्षात्कार में कहा, ''अधिकतर उपाय लॉकडाउन के बाद प्रभावी होंगे और लोगों तक आपातकालीन राहत नहीं पहुंचाई जाती तो लाखों लोग भूख से मर जाएंगे.''

वहीं किसी तरह अपने गृह राज्य पहुंचे श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण पर भी ध्यान नहीं दिया जिससे ग्रामीण इलाकों में भी बीमारी के फैलने का खतरा है. मध्य प्रदेश और यूपी में फैले बुंदेलखंड इलाके में ही अब तक करीब छह लाख श्रमिकों के वापस आने का अनुमान है. विकास अर्थशास्त्री रीतिका खेड़ा ने ग्रामीण भारत में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिहाड़ी मजदूरों को अपनी-अपनी जगह पर बने रहने को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करने के कारण केंद्र की आलोचना की है. 2015-16 के रोजगार सर्वेक्षण के हवाले से उन्होंने कहा, ''भारत के 80 फीसद से अधिक कार्यबल अनौपचारिक

करण कुमार, 22 वर्ष
मनोज कुमार, 35 वर्ष
ठेका मजदूर, उत्तर प्रदेश

''किराया तक नहीं''

अन्य लोगों के साथ ही मनोज कुमार और करण कुमार भी उत्तर प्रदेश में अपने गृह नगर अयोध्या लौटने के लिए बस पकड़ने की उम्मीद में दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल की तरफ पैदल जाते नजर आए. लॉकडाउन के कारण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के तहस-नहस हो जाने के बाद ये लोग दक्षिण दिल्ली की रजोकरी पहाड़ी में स्थित अपने किराये के ठिकाने से पैदल ही निकल पड़े थे. यह इलाका शहरी प्रवासियों का बसेरा है और वसंत कुंज में भव्य फार्म हाउसों के इलाके के बिल्कुल नजदीक है. मनोज प्लंबर हैं और करण भी छोटे-मोटे काम कर लेते हैं. ये लोग दिल्ली में किसी ठेकेदार के साथ काम करते थे और हर महीने क्रमशः 13,000 रु. और 9,000 रु. कमा लेते थे. लेकिन अब, उन दोनों का न केवल काम छूट गया बल्कि उन्हें पिछले महीने की तनख्वाह भी ठेकेदार ने नहीं दी. बचत का पैसा तेजी से खत्म हो रहा है. लिहाजा, दोनों अपने घर-परिवारों के पास जाना चाहते हैं. मनोज कहते हैं, ''हमारे पास थोड़ा पैसा है जिससे हम 15-20 दिन का गुजारा तो कर लेंगे लेकिन काम नहीं है तो फिर हम 2,200 रु. का कमरे का किराया तो नहीं दे पाएंगे. फिर हम परिवारों को पैसा कैसे भेजेंगे? मोबाइल रिचार्ज की दुकानें बंद हैं, ऐसे में हमारे प्लान खत्म हो जाएंगे तो फिर हम अपने परिवारों से बात भी कैसे करेंगे? गांव में खाने की तो कोई कमी नहीं है और फिर वहां कम-से-कम अपने लोगों के बीच तो रहेंगे.'' अब ये दोनों लॉकडाउन की अवधि में फसल की कटाई में परिवार की मदद करेंगे. जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी में अनौपचारिक क्षेत्र एवं श्रम अध्ययन केंद्र में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर संतोष कुमार मेहरोत्रा कहते हैं कि यह रबी की फसल की कटाई का मौसम है और ज्यादातर प्रवासी श्रमिक इस समय खेतों में मदद करने के लिए अपने घर चले जाते हैं. वह इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि इनमें से कई लोगों को गांवों में मनरेगा कार्यक्रमों में रोजगार मिलने की भी उम्मीद होती है.

—कौशिक डेका

MAGAZINE KING

राजवंत रावत

> **"एकतरफा घोषणा से पहले क्या प्रधानमंत्री ने किसी भी राज्य सरकार के साथ इस राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लेकर कोई चर्चा तक की थी?"**
>
> —भूपेश बघेल
> *मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़*

क्षेत्र में कार्यरत है जिसमें से एक-तिहाई दिहाड़ी मजदूर हैं. गरीबों के लिए यह दोहरी मार है. वे तंग जगहों पर रहते हैं और अगर उनकी कमाई घटती है, तो वे कैसे बचेंगे?" उन्होंने कहा कि स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों को आश्रय और रसोई के रूप में बदला जा सकता है. सरकार के कुछ आलोचक मानते हैं कि लॉकडाउन जरूरी नहीं था—पुलिस की लाठी के जोर पर कराया गया देश का लॉकडाउन अन्य देशों की तुलना में अधिक कठोर है—क्योंकि इससे गरीबों की जिंदगी में जो दुश्वारियां पैदा हुईं हैं उसके बारे में कल्पना तक नहीं की गई थी.

जवाब में सरकार ने एक रक्षात्मक बयान दिया कि "कोविड-19 को लेकर भारत की प्रतिक्रिया समय रहते, आगे बढ़कर किया गया और क्रमबद्ध प्रयास है." सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि समाचार रिपोर्टों और सोशल मीडिया में इसे देश के विभाजन के बाद प्रवासियों का सबसे बड़ा पलायन बताया जाना 'झूठ और भ्रामक' है. 31 मार्च को, देश के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की बेंच ने मीडिया को महामारी को लेकर 'आधिकारिक' विवरण को प्रकाशित करने के लिए कहा.

यह सरकार के उस नजरिए के अनुसार है जिसमें वह मीडिया को लोगों और खुद के बीच एक कड़ी मानती है. यह सरकार की ओर से लोगों को यह आश्वासन देने के लिए मीडिया को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने जैसा है कि सरकार कोरोना वायरस की चुनौतियों से मजबूती से लड़ रही है. इस खबर को लिखे जाने तक, देश में कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार को लेकर आधिकारिक हलकों में अभी भी असहमति है. यह देखते हुए कि भारत में अभी संक्रमण के प्रसार की गति की जांच ही चल रही थी और क्या यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने कठोर पूर्णबंदी का फैसला जल्दबाजी में लिया? और इसकी कोई पूर्व तैयारी नहीं की. मिसाल के तौर पर, गरीबों पर इसके प्रभाव को देखकर मेक्सिको ने राष्ट्रव्यापी बंद को वापस ले लिया है. बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों ने आंशिक रूप से बंद लागू किया है या दिहाड़ी मजदूरों को अपने घरों में लौटने का

राहत प्राथमिकता होनी चाहिए

क्या गलत हुआ और सड़कों पर चल रहे गरीबों की मदद के लिए अब क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में तीन विशेषज्ञों की राय

राजीव खंडेलवाल,
सह-संस्थापक और कार्यकारी निदेशक, आजीविका ब्यूरो

केंद्र को स्थानीय स्तर पर पीडीएस से सबको तत्काल भोजन और पैसा मुहैया करना चाहिए. दस्तावेज हों या न हों, सभी को राशन मुहैया करवाए. आश्वस्त करे कि श्रमिकों को उनकी उचित पगार मिले. मनरेगा के बकाए के भुगतान के साथ-साथ सार्वभौमिक बुनियादी आय दे और अग्रिम पैसे का भुगतान करे. प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर बंदिशें अस्वीकार्य हैं. हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों के नियमों को दुरुस्त करके राज्यों की सीमा के आर-पार उनकी आवाजाही बेरोकटोक की जानी चाहिए.

अविनाश कुमार,
कार्यकारी निदेशक, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की केंद्र और राज्यों से अपील है कि सामाजिक सुरक्षा व्यापक बनाएं.

रीतिका खेड़ा,
विकास अर्थशास्त्री, आइआइएम अहमदाबाद

अभी भी बहुत देर नहीं हुई है और प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई निति किए जाने चाहिए या उन्हें भोजन के पैकेट मुहैया किए जाने चाहिए. जो बाहर निकल चुके हैं, उन्हें या तो उनके घर पहुंचाया जाना चाहिए या उन्हें अस्थायी आश्रय मुहैया कराया जाना चाहिए.

मौका दिया है. स्वीडन ने अभी भी अपने पार्क, रेस्तरां और स्कूल खुले रखे हैं, और लोगों को केवल सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी है, घर से काम करने को कहा गया है और 50 से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध है.

महामारी विज्ञानी, डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इससे सहमति जताते हैं कि भारत ने उपयुक्त और निर्णायक कदम उठाए हैं. लेकिन किस कीमत पर? पहले से पस्त भारतीय अर्थव्यवस्था को निस्संदेह एक बड़ा झटका लगा है. सरकार के कदमों से नाराजगी वृहद आर्थिक चिंताओं की वजह से नहीं है, बल्कि भूख और गरीबी के कारण लोगों की जान जाने के असल जोखिम के कारण है. कई प्रवासी श्रमिकों ने कहा कि वे पैदल ही अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे 'कोरोना से पहले, भूख से ही मर जाएंगे.' प्रवासी और मौसमी श्रमिकों के लिए काम करने वाले एनजीओ आजीविका ब्यूरो के सह-संस्थापक और कार्यकारी निदेशक राजीव खंडेलवाल, स्वीकार करते हैं, ''अगर प्रभावित लोगों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाकर लॉकडाउन की घोषणा होती तो इसके प्रभाव को अपेक्षाकृत कम किया जा सकता था.''

क्या गरीबों पर लॉकडाउन के अनपेक्षित नतीजों को कम करने के लिए सरकार के पास अभी भी वक्त है. कुछ जानें पहले ही जा चुकी हैं, पर क्या जरूरतमंदों के हाथों में कुछ नकद रकम डाली जा सकती है? हमारे असमान समाज में, मध्यवर्ग की बीमारी कोविड-19, जिसका शुरुआती प्रसार विदेश यात्राओं पर गए लोगों से हुआ, की सबसे बड़ी मार गरीबों पर पड़ी है. इसके बावजूद गरीब प्रवासी श्रमिकों को बसों को साफ किए जाने वाले केमिकल से नहलाया जा रहा है. ये गरीब ही हैं जिनके पास घर से काम करके पैसा कमाने का विकल्प नहीं है.

"वित्त मंत्रालय के उपाय तो लॉकडाउन के बाद प्रभावी होंगे. तब तक कोई तत्काल सहायता नहीं पहुंचाई गई तो लाखों लोग भूख से मर जाएंगे."
—ज्यां द्रेज
अर्थशास्त्री

गरीबों के बच्चे ही हैं जिनकी शिक्षा बाधित है. शहरों में अमीरों के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी है. उत्पादकता या खुद में सुधार को लेकर उदासीन रहने वाले वर्गों को अभी भी सोशल मीडिया या स्ट्रीमिंग सेवाओं पर बीत रहे निर्बाध वक्त के दौरान जीभ की संतुष्टि के लिए पिज्जा-आइसक्रीम जैसी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं.

दिल्ली से बाहर जाने वाले राजमार्गों पर चलते कई प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन के अनुभवों से स्वयं और सुविधासंपन्न वर्ग के बीच के अंतर को ज्यादा अच्छे से पहचाना है. मोदी की ओर से पेश किए गए समाधान पर एक ने कहा, ''अमीरों के लिए तो यह आदर्श है, पर हम जैसे लोगों का क्या?'' भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में गरीबों के लिए सोशल डिस्टेंस बनाने की हैसियत में आना भी सपने सरीखा है. अपने साप्ताहिक रेडियो संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि इस पूर्णबंदी की सबसे बड़ी मार गरीबों पर पड़ी है, पर उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था. विशेषज्ञों की राय उनके पक्ष में है, पर इस आश्यकता के नाम पर देश में राजमार्गों पर दिखते संकट के लिए सरकार को माफ नहीं किया जा सकता.

शेख मिराजुल, 34 वर्ष
निर्माण मजदूर, पश्चिम बंगाल

''हमारे पांव जख्मी हो गए थे''

पश्चिम बंगाल में कोलकाता से मुर्शिदाबाद जिले में स्थित अपने गृह नगर रेजिनगर के बीच की 209 किलोमीटर की दूरी में से 40 किलोमीटर शेख़ मिराजुल ने पैदल पूरे किए. राज्य में लॉकडाउन लागू हो जाने के बाद मिराजुल और उनके साथ काम करने वाले 12 अन्य श्रमिकों को दमदम में उनके ठिकाने से निकाल दिया गया. पहले वे 18 किलोमीटर पैदल चलकर सियालदह रेलवे स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि ट्रेनें बंद की जा चुकी हैं. उन्हें एक एंबुलेंस बुक करनी पड़ी जिसने प्रति व्यक्ति दो-दो हजार रुपए लेकर उन्हें 122 किलोमीटर का सफर कराया. मिराजुल ने कहा,''हम 24 मार्च को रात 10.30 बजे नादिया पहुंचे. एंबुलेंस ने हमें हाइवे पर ही उतार दिया. घना अंधेरा था. न तो सड़क पर कोई वाहन था और न ही हमारे मोबाइल फोन में बैटरी बची थी. हम माचिस जला-जलाकर साइनबोर्ड पढ़ते रहे. जब हम पलासे पहुंचे तो आधी रात से ऊपर हो चुकी थी और तब भी हम घर से 20 किमी दूर थे.'' यात्रा का आखिरी हिस्सा सबसे कष्टदायक था. वे कहते हैं, ''थकान से चूर हमारे पांव जख्मी होकर सूज गए थे. हम किसी तरह शरीर को खींच रहे थे क्योंकि डर था कि हम पकड़कर जेल में डाल दिए जाएंगे.'' पुलिस के तंग करने की आशंका में मिराजुल अपना फोटो भी खिंचाने के लिए तैयार नहीं हुए (उनका परिवार फोटो खिंचाने को तैयार हुआ). वे पूछते हैं, ''आप मेरी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं? या आर्थिक मदद दिला सकती हैं?''—रोमिता दत्ता

MAGAZINE KING

कभी न खत्म होने वाला सफर

प्रेम कुमार, 32 वर्ष
राजमिस्त्री, मध्य प्रदेश

प्रेम कुमार गुड़गांव में निर्माण स्थलों पर राजमिस्त्री का काम करते हैं. वहां से मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले में स्थित उनके गांव तक का सफर उनके लिए बेहद यातनादायक रहा. जिस साइट पर वे काम कर रहे थे, वह 21 मार्च को बंद कर दी गई. शहर में लॉकडाउन था, लिहाजा 32 वर्षीय प्रेम कुमार के पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं था कि वे अपनी पत्नी और चार बेटियों के साथ टीकमगढ़ निकल जाएं. उनकी दो और बेटियां हैं जो गांव में उनके माता-पिता के साथ रहती हैं.

उनके पास 2,000 रुपए बचे थे, थोड़ी उन्हें दिहाड़ी मिली (बाकी उन्हें काम पर लौटने के बाद देने का वादा किया गया है), और थोड़ा पैसा उन्होंने गुड़गांव में अपने मकान मालिक से उधार लिया. प्रेम कुमार अपनी पत्नी, बेटियों और भाई के साथ पैदल ही 26 मार्च को गांव के लिए रवाना हो गए. करीब 20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कुछ पुलिसवालों ने एक ट्रक रुकवाकर उसमें उन्हें बैठा दिया. उससे वे कोसी कलां तक पहुंचे. वहां से एक और ट्रक में सफर करके वे मथुरा पहुंचे. मथुरा से उन्हें एक बस मिल गई जिससे वे मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंच गए. वहां से आखिरकार उन्हें एक और ट्रक मिला जिसने 28 मार्च को उन्हें उनके गांव छोड़ दिया. इस सफर पर प्रेम कुमार ने कुल मिलाकर 5,000 रुपए खर्च कर दिए. वे कहते हैं, "हमें रास्ते में हर तरह के लोग मिले—कुछ ने बेहद छोटे सफर के लिए खूब सारा पैसा ले लिया, तो कई अच्छे लोग मिले जिन्होंने खाना भी दिया और रात में सोने की जगह भी. मैं गुड़गांव तभी लौटूंगा, जब मेरा ठेकेदार मुझसे कहेगा. तब तक मैं गांव में खेती-बाड़ी के धंधे में अपने पिता की मदद करूंगा."

—राहुल नरोन्हा

पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट ने पूर्णबंदी में कुछ ढील की जरूरत को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया था कि दुकानें तब तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रह सकती हैं, जब तक कि दुकानों पर सामाजिक दूरी और स्वच्छता संबंधी दिशा-निर्देशों को बनाए रखा जाता है. अदालत के फैसले के बाद पंजाब के नौकरशाहों ने कुछ कारखानों और भट्ठों को फिर से खोलने की अनुमति दी. पर तीन दिनों में कोविड-19 के कारण तीन मौतों को देखते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 14 अप्रैल तक सख्त कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित कराने का फरमान सुना दिया.

सीमाएं सील कर दी गई हैं. लॉकडाउन की घोषणा के बाद से लगातार दिल को झकझोर देने वाले मंजर सामने आने से केंद्र और राज्य, दोनों ही सरकारों के लिए शर्मिंदगी की स्थिति पैदा हुई है और वे अस्थायी आश्रय तैयार कर रही हैं. भारत के एकमात्र फॉर्मूला-1 रेसिंग ट्रैक, ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को अस्थायी आश्रय और क्वारंटीन केंद्र में बदल दिया गया है. हरियाणा में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य में 70,000 प्रवासी श्रमिकों को ठहराने के लिए 467 शिविर पहले से तैयार हैं और 10,000 लोग पहले ही इन शिविरों में रह रहे हैं. प्रदेश की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने जिला उपायुक्तों को को बेघर मजदूरों के लिए शिविर लगाकर उनके खाने-रहने का प्रबंध करने का निर्देश दिया. पर इसे जारी करने में इतनी देरी हुई कि गुरुग्राम में बनाए गए 23, फरीदाबाद के 20, रेवाड़ी के 24, करनाल के तीन और यमुनानगर में बनाए गए करीब सभी शेल्टर होम खाली हैं. वहीं, बस्तर में एक डॉक्टर ने बताया कि स्कूलों को पहले से अस्थायी क्वारंटीन केंद्रों में बदल दिया गया है और प्रत्येक में 100 बिस्तरों का इंतजाम है. आशंका से भरे वे कहते हैं, "अभी तो उनमें ज्यादा मरीज नहीं हैं, पर शायद जल्द ही, यहां कोई जगह न बचे."

कर-मुक्त दान के लिए पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई. माना जा रहा है कि इस फंड का इस्तेमाल गरीबों के लिए होगा और इसमें कई हजार करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं.

जिस देश की बड़ी आबादी रोज कमाती है तो रोज खा पाती है, उसे बिना किसी पूर्व तैयारी के तीन हफ्तों के लिए पूरी तरह घरों में बंद हो जाने के फरमान सुना देने के फैसले से हुए नुक्सान को कम करने के लिए राज्य और केंद्र, दोनों से बहुत समन्वय के साथ काम करने की जरूरत होगी. विश्व बैंक को अंदेशा है कि कोरोना लाखों लोगों को गरीबी में धकेल देगा. इनमें से अधिकांश भारत में होंगे. कोविड-19 के संक्रमित अधिकतर लोगों को इलाज के बाद बीमारी से उबरने में 17.8 दिनों का समय लगता है, पर इसकी आर्थिक मार से उबरने में कहीं अधिक समय लगेगा. 23 मार्च को दिल्ली से बिहार के अपने गांव के लिए पैदल निकल पड़े 37 वर्षीय कृष्ण सुबह से शाम तक चलते रहे, भोजन के लिए अजनबियों की दया पर आश्रित रहे और जान बचाने के लिए घास खाने को भी तैयार थे. वे कहते हैं, "मैं जानता हूं कि हमसे अपने घरों के भीतर रहने की अपेक्षा की जाती है लेकिन कभी-कभी आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है."

—साथ में, **सोनाली आचार्जी, अनिलेश एस. महाजन, अभिताभ श्रीवास्तव, श्वेता पुंज, संतोष**

मुसीबतों का ढेर
29 मार्च को लॉकडाउन के दौरान जम्मू में मंडी में प्याज के बोरों पर बैठा एक मजदूर

MAGAZINE KING

चन्नी आनंद/एपी

फसल देख आया रोना

लॉकडाउन से मजदूरों और कृषि मशीनरी की आवाजाही एक झटके में रुकने से खेती का काम ठप, खेतों में लहलहाती और पककर तैयार रबी फसल से उपजी आशा भारी निराशा में बदली

अजित कुमार झा

MAGAZINE KING

बमुश्किल पखवाड़े भर पहले ही तो ग्रामीण भारत आशा और उत्साह से भरापूरा दिख रहा था. गेहूं, दलहन, तिलहन, सब्जियां जैसी रबी और अंगूर, अनार, यहां तक कि जल्दी पकने वाले आम जैसे फलों की फसलें देश भर में भारी पैदावार के साथ कटाई, तुड़ाई के लिए खड़ी थीं. माचे में बारिश और उत्तर के कुछ इलाकों में पड़े ओले भी किसानों की उम्मीद नहीं तोड़ पाए थे. बिहार में मोतिहारी से करीब 33 किमी दूर बडहरवा फतेह मोहम्मद के मिराजुल हक के खेतों में मसूर की फलियां पककर चटकने को बेताब थीं और मंदी के इस दौर में आने वाले वक्त के लिए उम्मीद की किरणों सरीखी थीं. हक ही क्यों पूरे देश के खेतों में रबी की पकती हुई फसल कृषि अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए उम्मीद की किरण ले आई थी. लेकिन कोविड-19 नामक महामारी और उसकी रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन (तालाबंदी) ने सारी उम्मीदें धराशायी कर दीं. इस महामारी से बचाव के उपायों के कारण ग्रामीण भारत की आशा और उत्साह निराशा के गर्त में जा फंसी.

तीन हफ्ते तक सरकार के थोपे लॉकडाउन से खेतिहर मजदूरों, ठेके पर आने वाले प्रवासी मजदूरों और हार्वेस्टर, थ्रेशर, ट्रैक्टर, ट्रकों और दूसरे उपकरणों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है. लिहाजा, देश के गांवों में यह आशंका घर कर गई है कि ग्रामीण संकट फिर ठाठें मारने लगेगा. लॉकडाउन अगर 14 अप्रैल के बाद भी जारी रहा तो ज्यादातर राज्यों में लगभग पूरी रबी फसल बर्बाद हो जाएगी.

मई-जून में शुरू होने वाली खरीफ फसलों की खेती का काम सौ फीसद खेतिहर मजदूरों के बल पर ही होता है इसलिए लॉकडाउन से उसमें भी रोड़ा अटका तो देश की समूची कृषि व्यवस्था ही भयावह त्रासदी की शिकार हो उठेगी. हालांकि, सरकार ने सामाजिक दूरी बरतते हुए खेतों में कटाई-मंड़ाई के काम में मजदूरों को लगाने की छूट दी है, पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 31 मार्च को एक मशविरा जारी किया, जिसमें कहा गया कि कटाई और मंड़ाई के काम में मशीनों और उपकरणों का ही अधिक इस्तेमाल करें और मुमकिन हो तो इस काम में परिचित लोगों को ही लगाएं. यह सलाह एहतियात के लिए थी पर अंदेशे बरकरार रहे.

नाजुक फसल का नुक्सान ज्यादा

जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियों का नुक्सान सबसे ज्यादा हो रहा है. लॉकडाउन से इन उपजों का बाजार तो पूरी तरह चौपट हो गया है. कहीं कोई खरीदार ही नहीं है. महाराष्ट्र या कर्नाटक के चिकबल्लबपुर में अंगूर उगाने वाले किसान हों, जिनमें तकरीबन 80 फीसद तो अंगूर का निर्यात ही करते हैं, या फिर कोंकण के आम (दुनिया भर में मशहूर अलफांसो) उगाने वाले, पूर्णिया के मछलीपालक हों या नासिक के टमाटर और खीरे की फल उगाने वाले किसान, सब जगह एक ही कहानी है, उपज के सड़ने और अपनी दुर्दशा की व्यथा.

महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेमौसम बारिश और देर से आई सर्दी की मार पहले ही पड़ चुकी है. और अब आ गया लॉकडाउन. फरवरी और मार्च इन दो राज्यों के ज्यादातर किसानों के लिए अंगूर, अनार और ज्वार की फसल निकालने का समय होता है. अंगूर और अनार की फसल का नुक्सान 40 फीसद तक आंका जा रहा है. हर किसान की पीड़ा बेहिसाब है.

नासिक के सिन्नार में अंगूर किसान मनोज थेटे ने आखिरकार अपनी पूरी पकी फसल पर ही मिट्टी फेंक दी क्योंकि न मजदूर हैं, न ढुलाई का साधन और न बाजार. थेटे को सात एकड़ में अंगूर की फसल लगाने के लिए 3.5 लाख रु. का कर्ज उठाना पड़ा था. उनका यह सारा पैसा मिट्टी में मिल गया. थेटे कहते हैं, ''अंगूर निकालने के लिए मजदूरों को तलाशना बेहद मुश्किल है. मैं ट्रकों में भरकर कुछ क्विंटल उत्तर प्रदेश ले गया लेकिन वे ट्रकों में ही सड़ रहे हैं.''

नासिक जिले के डिंडोरी के किसान सतीश उगाले अपने खेत से 100 क्रेट शिमला मिर्च लेकर 30 मार्च को नासिक शहर में कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) पहुंचे. उन्हें उम्मीद थी कि एक क्रेट (एक क्रेट में 20 किलो) की कीमत कम से कम 100 रु. तो मिलेगी ही. लेकिन व्यापारी ने प्रति क्रेट 15 रु. का दाम लगाया. इससे तो ढुलाई का खर्च भी पूरा न मिलता देख, उगाले ने वहां इलाके के गरीब लोगों में शिमला मिर्च मुफ्त में बांट दिया. उगाले कहते हैं, ''लालची व्यापारी के बदले गरीबों को खिला देना बेहतर है.''

कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर के किसान अगस्टिन वर्के ने अपने बागान के सारे अंगूर कंपोस्ट के गड्ढे में डाल दिए और ट्विटर पर अपनी व्यथा लिखी. नासिक के इगतपुरी के संजेगांव के किसान राजाराम गोवर्द्धने

''किसी को तो खाने दो''

चेतन भोर, *27 वर्ष*
किसान, सांजेगांव, नासिक, महाराष्ट्र

सांजेगांव में हर सुबह बहुत से किसान ताजा टमाटर और खीरे के भरे हुए टोकरे अपनी गायों और भैंसों के आगे खाली कर देते हैं. यहां रबी की फसल अच्छी हुई है लेकिन उन्हें खरीदने वाले लोग बहुत कम हैं, इसलिए इन किसानों को लगता है कि इन्हें फेंकने से अच्छा यही है कि अपने मवेशियों को ही खिला दिया जाए. देश में तालाबंदी के बाद गांव के ज्यादातर किसान घोटी या नासिक की मंडियों में नहीं पहुंच पा रहे हैं. मुंबई के कुछ व्यापारी टेंपो लेकर यहां आए थे और सब्जियां ले गए थे लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया था. एक किसान चेतन भोर कहते हैं, ''उन्होंने हमसे कहा कि अगर माल बिक गया तो वे भुगतान कर देंगे. हमें नहीं पता कि हमें पैसा मिलेगा या नहीं लेकिन चलो कहीं कोई तो इन्हें खाएगा.''

छोटे किसान दो महीने के इस फसल के सीजन (फरवरी से अप्रैल) में हर दूसरे दिन करीब 30 टोकरा सब्जियां पैदा करते हैं. हर टोकरे में 20 किलो टमाटर, लौकी, कद्दू या खीरा आता है. इस समय उनके खेतों में सारे टमाटर पक चुके हैं लेकिन करीब 200 किसान परिवारों के पास इन्हें बेचने के लिए कोई बाजार नहीं है. भोर कहते हैं, ''हमें उम्मीद है कि कम से कम केचप और सॉस बनाने वाले उत्पादक यहां आएंगे और हमारे टमाटर और खीरे ले जाएंगे. इस तरह ये सब्जियां कहीं तो काम आएंगी.'' और अब इन किसानों के मन में गर्मी की फसल को लेकर भी संदेह है. इन दिनों एक आम किसान 3 लाख रु. तक कमा लिया करता था लेकिन कोई आमदनी न होने से हमारे पास बीज खरीदने का भी पैसा नहीं रह गया है.'' किसान उम्मीद कर रहे हैं कि यह मौजूदा लॉकडाउन खत्म हो तो एक बार फिर सब्जियां निकलनी शुरू हो जाएं.

–अदिति पै

महाराष्ट्र में फलों की 40% पैदावार पर लॉकडाउन का साया

अंगूर

खेती का रकबा
3,00,000
हेक्टेयर

कहां जाते हैं अंगूर
नीदरलैंड्स, यूके, रूस, जर्मनी

निर्यात में नासिक का हिस्सा
80%

निर्यात
1,97,000
मीट्रिक टन

लॉकडाउन से घाटा

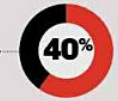

स्रोतः एपीईडीए और रवींद्र बोराडे, अध्यक्ष, नासिक संभाग, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बगैतदार संघ

अनार

खेती का रकबा
1,64,000
हेक्टेयर

लॉकडाउन से घाटा

पैदावार के अहम इलाके
सोलापुर, नासिक, सांगली, सतारा, अहमदनगर और पुणे

प्रमुख उत्पादक इलाके

आम

लॉक रहा सब तो आम भी होगा डाउन

खेती का रकबा
1,57,000
हेक्टेयर

पैदावार के प्रमुख इलाके
रत्नागिरि और देवगढ़

कुल पैदावार
(2016-17)
5,15,000

कुल टर्नओवर
2,500-3,000
करोड़ रुपए

स्रोतः नेशनल मैंगो डेटाबेस, डॉ. गणेश हिंगमिरे

आजकल अपनी मवेशियों को टमाटर और ताजा खीरा खिला रहे हैं (देखें, केस स्टडी: टमाटर और गायें). उधर, बिहार में पूर्णिया के श्रीनगर में मछलीपालक और मखाना उत्पादक किसान चिन्मयानंद सिंह के तालाबों की मछलियां उनकी आंखों के सामने मर रही हैं और उनके मखाने के खेतों (मखाने उथले पोखरों में उगाए जाते हैं) को शैवालों ने जकड़ लिया है. पोखरों से शैवाल निकालना एक तरह से निराई का बेहद झंझट भरा काम है. मछली मारने और मखाने के पोखरों में से शैवाल निकालने के लिए चिन्मयानंद को मछुआरों की जरूरत है. वे कहते हैं, ''इस इलाके में सिर्फ महलदार ही यह काम कर सकते हैं. पर इसमें सामाजिक दूरी बनाए रखना मुमकिन नहीं होगा. लिहाजा, मैं अपनी आंखों के सामने पछिया से सूखते पोखरे देख रहा हूं.'' असल में, पछिया की वजह से इन दिनों मछली और मखाना के पोखरों में नियमित रूप से पानी डालना होता है, पर इसके लिए भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं. ऐसी ही दिक्कत पड़ोस के चनका गांव के किसान और लेखक गिरींद्र नाथ झा को भी दरपेश है. इस पछिया में उनके मक्के के खेतों के साथ आम और लीची के बाग को भी पानी की जरूरत है. झा कहते हैं, ''आम और लीची के पेड़ों में अभी फल लगने का समय है. अभी उनको सिंचाई मिलेगी तो फल अच्छे लगेंगे. यह काम भी नहीं हो पा रहा है. अगर किसी तरह फल लग गए तो फिर बाजार की स्थिति डांवाडोल ही है.''

महाराष्ट्र में अलफांसो किस्म के आम के बाजार में अमूमन सालाना 3,500 करोड़ रु. का कारोबार होता है. सबसे उम्दा किस्म कोंकण के देवगण तालुका से अक्षय तृतीया तक आती है, जो अप्रैल के आखिर में पड़ती है. एक इकलौते तालुका के किसान करीब 300 करोड़ रु. के आम का निर्यात कर लेते हैं. अगर लॉकडाउन में ढील नहीं दी गई तो आम की फसल का नुक्सान बेहतहा होगा. इसके बड़े बाजार यूरोप और अमेरिका हैं. ये दोनों महामारी के केंद्र बने हुए हैं इसलिए वहां फल की मांग की संभावना कम है. इसी तरह राज्य के ग्रामीण इलाकों में कुमकुम के महिला कुटीर और छोटे उद्योग बड़े पैमाने पर हैं. अब यह उद्योग भी खट्टा हो सकता है.

तमिलनाडु के नीलगिरि चाय बागानों के चाय उगाने वाले भी दुश्चिंता से घिरे हैं. मार्च से मई के महीनों में हजारों ऐसे किसान चाय की हरी पत्तियां तोड़कर इलाके की चाय फैक्टरियों में आपूर्ति करते हैं. अब उन्हें चिंता है कि लॉकडाउन से पता नहीं क्या होगा. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के चाय बागानों के मालिकों की यही कहानी है (देखें, केस स्टडी: नक्सलबाड़ी चाय बागान).

इसी तरह फूल उगाने वालों की भी फसल खूब फली है लेकिन आयोजनों और धार्मिक उत्सवों के रद्द होने से कोई खरीदार नहीं है. चेन्नै में फल-फूल-सब्जी की एशिया में सबसे बड़ी मंडियों में एक कोयंबेडु थोक बाजार तो हमेशा ही गुलजार रहा करता था लेकिन आजकल सूना-सा है क्योंकि कारोबार आधा से भी कम हो गया है. ऐसा तब है जबकि जिलों के आर-पार जरूरी जिंसों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है. मार्च के आखिरी दिनों में तमिलनाडु ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल से लगती अपनी सीमाओं पर महीने के अंत तक जरूरी जिंसों के अलावा हर तरह के यातायात पर रोक लगा दी. सबसे प्रभावित कृषि क्षेत्र बेंगलूरू से

ग्राफिक्सः तन्मय चक्रवर्ती

सोनिया जब्बार

मालकिन , नक्सलबाड़ी टी स्टेट, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

''हमें बहुत भारी झटका लगा है''

चाय एक निरंतर प्रोसेस होने वाला उद्योग है. हमें हर रोज फसल काटनी होती है और फसल की पहली कटाई अभी चल ही रही थी. इस साल वास्तव में बहुत अच्छी फसल हुई थी. और फिर अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के हमें सारा काम रोक देना पड़ा. जिस तरह से यह फैसला लिया गया है वह बिल्कुल अविवेकपूर्ण है. उन्हें हर चाय बागान एक इकाई के रूप में देखना चाहिए था और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करना चाहिए था. यहां काम तो बंद कर दिया गया है लेकिन मजदूरों को बाजार जाने की इजाजत है, बच्चे भी खेल रहे हैं. क्या चाय के उत्पादन से ही कोविड-19 फैलेगा. बाकी सब काम पहले की तरह चलता रहे तो ठीक है क्या? हम चाय बागानों और फैक्टरियों में पहले से ही सारी सावधानियां बरत रहे थे. और जहां वजन किया जाता है, वहां आपस में दूरी बनाए रखने के नियम का कड़ाई से पालन किया जा रहा था. चाय की पत्तियां तोड़ने वाले हर मजदूर का रिकॉर्ड रखने के लिए चेहरे से पहचान होने वाले सिस्टम का उपयोग किया जा रहा था. हमें—अनौपचारिक ढंग से—बता दिया गया था कि लॉकडाउन के दौरान हमें अपने श्रमिकों (चाय बागान में करीब 600 कर्मचारी हैं) को पैसा देना होगा. अब मुझे उन्हें पैसा देने के लिए बैंक से कर्ज लेना होगा. सरकार को कहना चाहिए था कि अपने कर्मचारियों को पैसा दो और आपको बैंकों को कोई ब्याज नहीं देना होगा. लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है. हमें भारी नुक्सान हुआ है. अप्रैल के मध्य में जब दोबारा काम शुरू होगा तो हमें झाड़ियों को काटना होगा. इसका मतलब है कि पूरी भरपाई करने में 3-4 हफ्ते लग जाएंगे. अप्रैल सबसे सूखा महीना होता है आप झाड़ियों पर छुरियां नहीं चला सकते हैं. इसलिए इससे भी ज्यादा देरी होगी. हम आधा मार्च गंवा चुके हैं और शायद पूरा अप्रैल भी निकल जाए. इस तरह दूसरी फसल भी बर्बाद हो सकती है. यह चाय उद्योग या भारतीय चाय के निर्यात के लिए अच्छा नहीं है.''

—काई फ्रीजे से बातचीत के आधार पर

लगते तकरीबन 70 किमी के दायरे के इलाके हैं. मुंबई में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (आइजीआइडीआर) में विकास अर्थशास्त्री सुधा नारायणन कहती हैं, ''इस शहर में तमिलनाडु के सीमावर्ती इलाकों की तमाम पैदावार खप जाती है. बागवानी के ज्यादातर किसान तो बिक्री के लिए बेंगलूरू पर ही आश्रित हैं.'' तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन के छह दिन बाद कृषि क्षेत्र में पाबंदियों में ढील दे दी है.

उत्तरी विक्षोभ

यही व्यथा-कथा और आशंका तमाम उत्तरी राज्यों के देहात की भी है. चाहे आप समृद्ध पंजाब और हरियाणा से गुजरें या बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीमारू राज्यों से, सब जगह एक जैसी दुश्चिंताएं फैली हुई हैं. पूर्वी भारत के मजदूर मुहैया कराने वाले राज्यों के कृषि क्षेत्र का भाग्य एक प्रवासी श्रमिकों की पेचीदा व्यवस्था के तहत मजदूरों की आमद पाने वाले पश्चिमी भारत से जुड़ा हुआ है. मसलन, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दूसरे राज्यों में रबी की कटाई-मंड़ाई मजदूरों की भारी कमी से बुरी तरह प्रभावित है जबकि मजदूर मुहैया करने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्य भूमिहीन गरीबों के पास रोजगार न होने और गांव में उनके परिवारों तक पैसा न पहुंचने से दिक्कत में हैं.

बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड जैसे मजदूर मुहैया कराने वाले राज्य दोहरी मार झेल रहे हैं. रबी के मौसम में खासकर कटाई वगैरह के काम के लिए भारी तादाद में सफर करने वाले अस्थायी प्रवासी मजदूर अपने घरों में लाचार बैठे हैं

"जिला प्रशासन से कोई साफ-साफ निर्देश नहीं है. लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों को पीटती पुलिस के वीडियो आते रहते हैं. इसलिए धूप निकलने के पहले ही काबुली चने की फसल काटने के अलावा कोई चारा नहीं है.''

-मलकीत सिंह

काबुली चना किसान, चमकौर साहिब, रोपड़

(देखें, बिहार के मधुबनी जिले के निर्मली की केस स्टडी), दिल्ली और दूसरे शहरों से लाखों लोगों पलायन जारी है. अपने थोड़े-मोड़े सामान के साथ सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल चुके लोगों के नजारे आने वाले दिनों में और बड़ी तबाही के दृश्य दिखा सकते हैं, बिना रोजगार, बिना भोजन के भूखे-प्यासे लोगों का हुजूम और सामुदायिक संक्रमण फैलने के खतरे भी.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और प्रवासी मजदूरों के मामलों के विशेषज्ञ प्रवीण झा कहते हैं, "अगर लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद भी जारी रहता है और सरकार अब तक ऐलान किए गए राहत पैकेजों से आगे जाकर कुछ गंभीर कदम नहीं उठाती है तो आने वाले महीनों में बिहार और उत्तर प्रदेश में महामारी के कारण मौतों के अलावा भुखमरी से मौतें भी बढ़ सकती हैं जिससे अकाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं."

वे राज्य में लौटने वाले हुजूम के भयावह असर के प्रति चेताते हैं: "बिहार की तकरीबन 12.3 करोड़ आबादी (2020) में से ही 50 लाख से 1 करोड़ लोग प्रवासी मजदूरी के लिए निकलते हैं." किसान नेता बिनोद आनंद के हिसाब से संख्या काफी ज्यादा है. उनके मुताबिक, करीब 2 करोड़ या राज्य की आबादी का छठवां हिस्सा प्रवासी मजदूरी करता है (इसमें अस्थायी प्रवास और स्थायी प्रवास दोनों की संख्या है).

पंजाब का दर्द

पंजाब हर साल 1.35 करोड़ टन गेहूं और 1.8 करोड़ टन धान पैदा करता है. दोनों ही फसलें और राज्य में तकरीबन 80 फीसद कृषि कारोबार बिहारी मजदूरों पर आश्रित है. इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में कटाई-मंड़ाई-छंटाई के लिए बड़ी मात्रा में कृषि उपकरण मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों में फंसे हुए हैं क्योंकि मध्य भारत के राज्यों में रबी की कटाई फरवरी-मार्च में ही शुरू हो जाती है.

लॉकडाउन से दूसरे तरह की समस्याएं भी पैदा हो रही हैं. पंजाब के जलालाबाद इलाके के किसान 45 वर्षीय दिलबाग सिंह ने 9 एकड़ में सरसों और 16 एकड़ में गेहूं बोया है. पंजाब में 24 अप्रैल तक पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है. इसलिए दिलबाग और उनके भाई जसकरन कुछ स्थानीय मजदूरों के साथ हर रोज तड़के ही सरसों की कटाई करते हैं,

विशेषज्ञों की राय

राहत की राह

संक्रमण से निपटने के लिए एपीएमसी के जरिए आपूर्ति की कड़ी तो पुनर्जीवित करें, डिजिटल ट्रेड और मशीनों का इस्तेमाल करें.

ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-एनएएम) से लॉकडाउन में भी डिजिटल ट्रेड किया जा सकता है. लेकिन देशभर में मात्र 585 ई-एनएएम हैं. कर्नाटक एक मॉडल राज्य है. यहां 163 राष्ट्रीय ई-मार्केट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरईएमएस) हैं. लॉकडाउन के दौरान देश भर में 2,700 कृषि उपज बाजार समितियां (एपीएमसी) बंद हैं. 27 मार्च को सरकार ने नया आदेश जारी किया कि सभी मंडियां अनिवार्य रूप से खुली रहेंगी. आपूर्ति की कड़ी को पुनर्जीवित करने के लिए एपीएमसी बहुत महत्वपूर्ण हैं.

सुधा नारायणन, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (आइजीआइडीआर)

कृषि खरीद लॉकडाउन की सावधानियों का पालन करते हुए की जा सकती है. लेकिन सख्ती के साथ सामाजिक दूरी, सभी वाहनों और गोदामों आदि का सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है. डिजिटल भुगतान कार्यक्रमों जैसे पीएम-किसान और डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) किसानों और मजदूरों की मदद के लिए बहुत बढ़िया विकल्प हैं.

अशोक दलवई, सीईओ, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी (एनआरएए)

व्यवस्था करें कि लोगों का पलायन दोबारा न होने पाए. उन्हें मेडिकल बीमा या पैकेज देने के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपना काम करने का ट्रेनिंग दें.

प्रोफेसर प्रवीण झा, श्रमिक प्रवासन विशेषज्ञ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

मशीनीकरण के लिए पंजाब मॉडल का अनुकरण करें क्योंकि यह सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करता है. हार्वेस्टर, थ्रेसर और शेलर आदि का इस्तेमाल करते हुए कृषि के क्षेत्र में मशीनीकरण पर जोर दें. अंतरराज्यीय गतिविधियों की जगह जिलों के बीच कृषि के व्यापार को प्रोत्साहित करें क्योंकि राज्यों की सीमाएं सील कर दी गई हैं.

प्रो. सुखपाल सिंह, आइआइएम अहमदाबाद

केंद्र ने किसान-उत्पादक संगठन (एफपीओ) को काम रोकने को कहा है. ऐसे अस्पष्ट निर्देशों के कारण आपूर्ति की कड़ी बाधित हो गई है. इन्हें फिर से जिंदा करें और एफपीओ की मदद लें क्योंकि वे किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

बिनोद आनंद, (सीएनआरआइ)

मशीनीकरण की भी एक सीमा है. पंजाब तो अति-मशीनीकृत होकर मशीनों का कबाड़खाना बन जाएगा. सूबे में अभी 4.5 लाख ट्रैक्टर हैं, जरूरत 1 लाख की है. यानी, 3.5 लाख अधिक है, वह किसानों के लिए बोझ है. साथ में, हम पराली जलाने के लिए छह मशीनों का सेट किसानों को दे रहे हैं, जो एक महीने काम करेंगे और 11 महीने पड़े रहेंगे. जरूरत से अधिक मशीनीकरण से खेती का नुक्सान ही होगा. इससे बेहतर होगा कि करोड़ों बेरोजगारों को सावधानी से लाकर सैनिटाइज करके काम करवाया जाए, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा.

देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ

MAGAZINE KING

जय प्रसाद साह, 61 वर्ष
लेबर ठेकेदार, निर्मली, मधुबनी, बिहार

''पलायन ही उनकी एकमात्र उम्मीद है''

इन दिनों जय प्रसाद साह काफी व्यस्त हैं. वे अपने प्रवासी मजदूरों को कर्ज और एडवांस पैसा बांटने में लगे हुए हैं. साह, हर साल पंजाब के लुधियाना में हजारों मजदूरों को काम के लिए भेजते हैं, खासकर गोयल राइस मिल में काम करने के लिए. वे वहां लेबर सुपरवाइजर के तौर पर 30 साल काम कर चुके थे, इसलिए जानते हैं कि मिल में किस तरह की योग्यता की जरूरत होती है. साह कहते हैं, ''यह तालाबंदी पिछले एक दशक में उत्तर बिहार के प्रवासी खेतिहर किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. मैं उनको एडवांस पैसा और कर्ज दे रहा हूं वरना वे बर्बाद हो जाएंगे.''

ये मजदूर आमतौर पर मार्च-अप्रैल और अक्तूबर-नवंबर में पंजाब जाते हैं. वे खरीफ की फसल के दौरान गोयल चावल मिल के लिए और रबी की फसल जैसे गेहूं, दाल और तिलहन की उपज के समय वहां जाते हैं. साह कहते हैं, ''कुशल मजदूर लुधियाना में एक दिन में 1,000 रु. तक कमा लेता है.'' कोसी (बिहार की पीड़ा कही जाने वाली नदी) के किनारे पर स्थित निर्मली एक छोटा-सा शहर है. उत्तर बिहार में लगभग हर साल बाढ़ लाने वाली कोसी नदी तबाही मचाने वाली एक दूसरी नदी कमला के साथ सटकर बहती है जिससे यहां के मजदूर बहुत बड़ी संख्या में पलायन करने पर मजबूर हैं. लेकिन दिल्ली से गुवाहाटी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के बनने के बाद से निर्मली के लोगों की किस्मत बदलने लगी. फिर भी यहां के लोगों की तकलीफें अभी कम नहीं हुई हैं. साह कहते हैं, ''इन लोगों के लिए काम के लिए पलायन एकमात्र विकल्प है क्योंकि बिहार में भी फसल की कटाई अब मशीनों से की जाने लगी है.''

–अजित के. झा

ताकि कोई दिक्कत न आए. रोपड़ जिले के चमकौर साहिब इलाके के किसान मलकीत सिंह कहते हैं, ''जिला प्रशासन से कोई साफ-साफ निर्देश नहीं है. लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों को पीटती पुलिस के वीडियो आते रहते हैं. इसलिए धूप निकलने के पहले ही काबुली चने की फसल काटने के अलावा कोई चारा नहीं है.''

बकौल दिलबाग, गेहूं की बुआई करने वाले खुशकिस्मत हैं क्योंकि मार्च में बारिश और देर तक सर्दी खिंचने से कटाई करीब पखवाड़े भर के लिए टल गई है. गेहूं, सरसों, काबुली चने जैसे रबी फसलों की कटाई उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में अमूमन 1 अप्रैल के आसपास होती है. लेकिन इस बार, पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव सिराज हुसैन के मुताबिक, ''कटाई देर से होनी चाहिए क्योंकि फसल 15 अप्रैल के पहले ही तैयार हो पाएगी.'' अब किसानों की उम्मीद यही है कि कटाई देर से हो और अप्रैल के अंत तक लॉकडाउन में ढील मिल जाए. वरना मजदूरों की कमी के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा में रबी की फसल तो बर्बाद हो जानी है.

केंद्रीय कृषि मंत्रालय का अनुमान था कि इस साल गेहूं की पैदावार करीब 10.9 करोड़ टन होगी, जो पिछले साल के मुकाबले 6 फीसद ज्यादा है. नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद कहते हैं, ''हम नजर रख रहे हैं. इस साल कटाई देर तक चले तो कोई दिक्कत नहीं है. पिछले साल हमने देखा था कि कटाई 6-8 हफ्ते तक खिंच गई. इस बार एक पखवाड़े ज्यादा खिंच सकती है.'' केंद्र और राज्यों की खरीद कुछ देर से होने से भी थोड़ी दिक्कत घट सकती है.

पंजाब की दूसरी फौरी समस्या यह है कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण के सभी 39 मामले गांवों से ही आए हैं. राज्य में दोआबा क्षेत्र के 30 से ज्यादा गांवों को पहले ही क्वारंटीन किया जा चुका है, जहां ज्यादातर प्रवासी मजदूर परंपरा से पहुंचते हैं. इसके अलावा पंजाब के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में (लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब, रोपड़ वगैरह जिले) भी मजदूर पहुंचते हैं.

आगे क्या?

वित्त मंत्रालय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मुहैया कराने की व्यवस्था में सुधार की योजना बना रहा है. उसने राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए तीन महीने की उधारी पर अनाज उठाने की इजाजत दे दी है और 7.50 करोड़ लाभार्थियों को तीन महीने तक का अतिरिक्त अनाज मुफ्त में उठाने की छूट दे दी है.

महामारी की आशंका बढ़ने के पहले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) अपना अनाज भंडार 12-15 फीसद छूट देकर खाली कर रहा था. और अब पीडीएस के मद में आपूर्ति से भंडार कुछ और खाली हो जाएगा. वित्त मंत्रालय को इससे इस साल कुछ अधिक

विपिन आहूजा

संजीव कुमार गोयल, 44 वर्ष
चावल मिल के मालिक, लुधियाना, पंजाब

''अगर बिहारी मजदूर न होंगे तो रबी की फसल बर्बाद हो जाएगी''

तालाबंदी की घोषणा होने के बाद पिछले दस दिन से संजीव गोयल अपने राइस मिल में काम करने वाले बिहारी मजदूरों के लिए खाना, दवाइयां और दूसरे जरूरी सामान बांटने में लगे हुए हैं. गोयल लुधियाना से करीब 20 किमी दूर अहमदगढ़ मंडी के पास रहते हैं. हालांकि पंजाब में फसल की कटाई कई वर्षों से पूरी तरह से मशीनों के जरिए हो रही है लेकिन खरीद की गतिविधियां अब भी पूरी तरह मजदूरों पर ही निर्भर है. गोयल चिंतित होकर कहते हैं, ''अगर बिहार से मजदूर नहीं आएंगे–अप्रैल के मध्य तक–तो पंजाब में रबी की फसल बर्बाद हो जाएगी. फसल की कटाई मुख्य रूप से मशीनों की जाती है लेकिन भारतीय खाद्य निगम और व्यापारियों की ओर से अगर खरीद नहीं हो पाएगी तो इस फसल का कोई फायदा नहीं है. कटी हुई फसल अपने-आप ही बर्बाद हो जाएगी.''

पंजाब में साल भर में 1.35 करोड़ टन गेहूं और 1.8 करोड़ टन धान का उत्पादन होता है. पंजाब में फसल और पूरा कृषि क्षेत्र 80 प्रतिशत तक बिहारी मजदूरों पर निर्भर है (बाकी का 20 प्रतिशत उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मजदूरों पर निर्भर है). गोयल के मुख्य लेबर ठेकेदार जय प्रसाद साह हैं जो बिहार में मधुबनी जिले के रहने वाले हैं. साह हर साल उनके चावल मिल के लिए 500-600 मजदूर भेजते हैं. गोयल कहते हैं, ''साह जी मेरे भाई की तरह हैं. जब मैं 13 साल का था तब से मैं उनके साथ काम कर चुका हूं.'' पर बिहार में बैठे साह और पंजाब में इंतजार कर रहे गोयल, दोनों तालाबंदी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं.

–अजित के. झा

गेहूं खरीदने के मौके की तरह देख रहा है. एफसीआइ की गेहूं खरीद तीन राज्यों पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से होती है. ये तीनों राज्य किसानों को महामारी से जूझने के लिए प्रति टन 100 रु. को बोनस दे रहे हैं.

लेकिन ये छोटे-मोटे उपाय ही हैं, संकट से जूझने की कोई समग्र नीति अभी नहीं आ पाई है. कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा कहते हैं,''आप मशीन भी लगाएंगे तो उसके पीछे आदमी तो चाहिए ही. मजदूरों को खेतों तक लाने का इंतजाम तो करना ही होगा. यही समय है कि सरकार मनरेगा केमजदूरों को खेती में लगाए. उनकी मनरेगा मजदूरी मार्च में 212 रु. थी ही, इस कठिन समय में सरकार 50 रु. मजदूरी और बढ़ाकर उनको बुलाए,'' नारायणन कहती हैं, ''पिछले हफ्ते तक लॉकडाउन के नतीजे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए असमंजस, अनिश्चिता और दुश्चिंता के रूप में ही आए हैं, जो आगे के हफ्तों की परेशानियां ही बढ़ाएंगे.'' आज, वे स्वीकार करती हैं कि सबसे बड़ी समस्या उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में प्रवासी मजदूरों की कमी है.

कई राज्यों में एपीएमसी मंडियों की बंदी से किसान जल्दी खराब होने वाली फसलों को लेकर एकदम लाचार हो गए हैं, उनका कोई खरीदार नहीं है, न व्यापारी, न उपभोक्ता. अपनी पैदावार को अमूमन एपीएमसी की स्थापित आपूर्ति श्रृंखला के जरिए बिक्री करते रहे किसान अब मंडियों के बदले अपने गांव से ही बेचने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन यह आसान नहीं है क्योंकि पूरा ग्रामीण बाजार ही ठप पड़ा है. ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों के साथ लॉकडाउन के उल्लंघन के नाम पर पुलिसिया ज्यादती की खबरें माल ढुलाई के समूचे नेटवर्क को ही तोड़ रही हैं. नारायणन कहती हैं कि ग्रामीण बाजार के ठप होने से कई किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) ऑर्डर रद्द कर रहे हैं और अपनी गतिविधियां मुल्तवी कर रहे हैं.

लॉकडाउन से बंपर रबी फसल अब निराशा-हताशा का कारण बनती जा रही है. उम्मीद की किरण बस कटाई और अनाज खरीद में देरी में ही दिख रही है.

—साथ में **मंजीत ठाकुर, अनिलेश एस. महाजन, किरण डी. तारे** और **अदिति पै**

MAGAZINE KING

गरीबों की व्यथा कथा

राष्ट्रव्यापी बंद ने शहरी गरीबों को बेरोजगार करने के साथ आर्थिक विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है. उनके जीवन को कैसे पटरी पर लाया जा सकता है?

कौशिक डेका

फोटोः बंदीप सिंह

दक्षिण दिल्ली की एक मलिन बस्ती में 10×10 फुट के कमरे में रहने वाली 40 साल की अल्पना रानी से जब यह पूछा गया कि क्या नए कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए वे, उनके पति और उनके दो वयस्क पुत्र सामाजिक दूरी तथा लगातार हाथ धोते रहने के सुझावों का पालन कर रहे हैं तो वे बुरी तरह बिफर गईं. एक खुले सीवर के किनारे बसी झुग्गी में रहने वाली रानी कहती हैं, ''अगर हमें बर्तन धोने के

लिए पर्याप्त पानी मिल जाए तो हम उसे ही बड़ी कृपा मानते हैं. बार-बार साबुन से हाथ धोने का तो सवाल ही नहीं उठता.'' यहां की झुग्गियां ऐसी लगती हैं जैसे एक-दूसरे से गुत्थमगुत्था हों और इनमें ज्यादातर बिहार के कटिहार के प्रवासी रहते हैं. दोपहर बाद पुरुष और महिलाएं थोड़ी सांस लेने के लिए संकरे कमरों से निकलकर छतों पर पहुंचते हैं लेकिन छतों के बीच भी दूरी बमुश्किल 3 फुट ही होगी. परिवार के लोग बर्तन, बाल्टी और तौलिए आदि एक दूसरे से साझा करते हैं. वे कहते हैं कि न तो नगर निगम के लोग और न ही कोई स्वैच्छिक संगठन कभी उन्हें साबुन, सैनिटाइजर और मास्क देने या फिर उनके क्षेत्र को कीटाणुरहित करने आया.

रानी कहती हैं, ''मैंने इस बीमारी के बारे में सुना है, लेकिन नहीं पता कि अगर यह बीमारी मुझे लग गई तो फिर क्या करना होगा.'' स्वच्छता तो फिलहाल उनकी चिंताओं में कहीं है ही नहीं. चूंकि 25 मार्च से देशव्यापी बंद शुरू हो गया है इसलिए रानी के पति सहित दैनिक मजदूरी, ऑटो-रिक्शा चालकों और स्थानीय दुकानों पर डिलिवरी ब्वॉय के रूप में काम करने वाले मलिन बस्ती के अधिकांश पुरुषों के पास कोई काम-धंधा नहीं है. आसपास की कॉलोनियों में खाना बनाने या फिर साफ-सफाई का काम करने वाली कुछ महिलाओं का काम चल रहा है लेकिन उन्हें नहीं पता कि अगर सब कुछ सामान्य नहीं हुआ तो इस मामूली आमदनी से उनकी जिंदगी कब तक चलेगी.

पूरे देश के शहरों और महानगरों में रहने वाले रानी जैसे हजारों गरीब परिवार खुद को कोविड-19 के कारण तीन सप्ताह की बंदी को अपने लिए मुसीबत का समय मानते हैं क्योंकि इससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले रातोरात बेकर हो गए हैं. इन गरीबों के पास कोई बचत नहीं थी और अब वे पेट भरने और अनिश्चित भविष्य की चिंताओं में डूबे हैं. 2011 की जनगणना का अनुमान है कि देश की शहरी आबादी 37.71 करोड़ है और इसकी लगभग 14 प्रतिशत आबादी या 5.2 करोड़ जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताती है. यही वह वर्ग है जिसे मौजूदा प्रतिबंधों के मद्देनजर सरकारी मदद की सबसे अधिक आवश्यकता है—मुख्य रूप से हाथ में नकदी और भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रूप में.

नरेंद्र मोदी सरकार ने 26 मार्च को, लॉकडाउन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के साथ उनकी इन चिंताओं को दूर करने की कोशिश की. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने इन उपायों को पर्याप्त नहीं पाया और कहा कि निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी (देखें, क्या करने की जरूरत है). उनका कहना है कि बहुत कुछ इस सरकारी मदद के समयबद्ध वितरण पर भी निर्भर करता है. इस बात पर भी संदेह जताया गया है कि क्या पूरा पैसा बिना किसी चोरी के लाभार्थियों तक पहुंच सकेगा. नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो ने कहा है कि गरीबों के बैंक खातों में सीधे लाभ हस्तांतरित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद के साथ सरकार को 'जेएएम' (जन धन खातों, आधार, मोबाइल कनेक्टिविटी) के उस बुनियादी ढांचे का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे वह बढ़ावा दे रही है.

आइए समझें कि केंद्र सरकार के राहत पैकेज से शहरी गरीबों को क्या वास्तव में लाभ हो रहा है और हो रहा है तो कितना? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 20 करोड़ से अधिक महिला खाताधारकों को अगले तीन महीनों तक 500 रुपए अनुग्रह राशि दी जाएगी, लेकिन ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस तरह के स्थानांतरण से केवल शहरी गरीबों के एक वर्ग को ही कवर किया जा सकता है. प्रॉक्टर ऐंड गैंबल इंडिया के पूर्व सीईओ और लेखक गुरुचरण दास पूछते हैं, ''सड़क के किनारे पकौड़ा बेचने वालों या उनके चार या पांच कर्मचारियों का क्या होगा जिनके पास जन धन खाते नहीं हैं?'' दिल्ली के रजोकरी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले एक 29 वर्षीय माली आसाराम की कमाई इस बंद के कारण खत्म हो गई और उन्हें अपनी पहले की थोड़ी-बहुत बचत को जीवनयापन के लिए निकालना पड़ा (देखें, ''हमने सब भगवान पर छोड़ दिया है''). आसाराम के छह सदस्यीय परिवार में से किसी का भी जन धन खाता नहीं है और वे कभी भी किसी सरकारी कल्याण कार्यक्रम के लाभार्थी नहीं रहे हैं.

लोग 500 रु. की इस सहायता को बहुत कम बताते हैं. पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि सरकार को जन धन खातों में एक बार में 6,000 रुपए ट्रांसफर करने चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि बेघरों के लिए बैंक खाते खोले जाएं और उनमें से प्रत्येक में 3,000 रुपए डाले जाएं. भारत सरकार के लिए पेश की अपनी कार्ययोजना में, बनर्जी और डफ्लो ने 'अधिक साहसी' सामाजिक हस्तांतरण योजनाओं का सुझाव दिया है. सरकारी सहायता को 'ऊंट के मुंह में जीरा' बताते हुए उन्होंने लिखा है, ''इसके बिना, मांग संकट आर्थिक हिमस्खलन में बदल जाएगा और लोगों के पास आदेशों की अवहेलना के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा.''

खाद्यान्नों की मुफ्त आपूर्ति के लिए राहत पैकेज के प्रावधान के तहत लगभग 8 करोड़ गरीब लोगों को अगले तीन महीनों तक हर महीने पांच किलो गेहूं या

चावल और एक किलो पसंदीदा दाल दिए जाने की घोषणा हुई है. हालांकि, एक खाद्य अनाज-अधिशेष के बावजूद, भारत लचर वितरण प्रणाली से ग्रस्त है और लगातार आने वाली सरकारें इस मॉडल को दुरुस्त करने में विफल रही हैं. लॉकडाउन के कारण माल की आवाजाही भी बुरी तरह बाधित हुई है जिससे 38 वर्षीय कमाल खान जैसे लाखों लोगों की सरकार से खाद्य पदार्थों की किसी भी तरह की मदद उम्मीद धूमिल हो रही है. लॉकडाउन की घोषणा के एक सप्ताह बाद सिकंदराबाद के इस बढ़ई को सात जनों के अपने परिवार के लिए तेलंगाना सरकार की ओर से घोषित 12 किलो चावल और 500 रुपए की नकद सहायता सहायता का अब भी इंतजार है (देखें, 'जल्द हमें भूखा रहना पड़ेगा'). खान कहते हैं, ''बिना किसी काम के तीन सप्ताह का वक्त काटना मुश्किल हो जाएगा. मैं परिवार को जैसलमेर के पास अपने पैतृक गांव लेकर जाना चाहता हूं क्योंकि वहां हमें भोजन तो मिल जाएगा और मुझे हर महीने 8,000 रुपए मकान का किराया भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास फिलहाल आमदनी का कोई जरिया नहीं है.''

महाराष्ट्र के ठाणे में 35 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर अनिल शेल्के को डर है कि पांच सदस्यों का उनका परिवार खाद्यान्न मदद की पात्रता खो सकता है क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है (देखें, 'सामाजिक अलगाव हमारे लिए असंभव है'). जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सेंटर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर ऐंड लेबर स्टडीज के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर संतोष कुमार मेहरोत्रा कहते हैं, ''यहां तक कि सबसे अच्छे समय में, पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) बड़ी अक्षमताओं से ग्रस्त है. इस नए संकट में अतिरिक्त दबाव के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि डिलिवरी कितनी कुशलता से हो सकती है.''

चिदंबरम ने केंद्र सरकार से आह्वान किया है कि प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए घरों तक सामान पहुंचाने का कोई वैकल्पिक रास्ता खोजते हुए अगले 21 दिनों के लिए खाद्यान्न की मात्रा को बढ़ाकर 10 किलो गेहूं या चावल कर दिया जाए.

24 मार्च को पूर्णबंदी की घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, पीडीएस और फलों, सब्जियों, किराने का सामान, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली की आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई थी. लेकिन विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी झलक रही थी क्योंकि दैनिक खाद्य पदार्थों को ले जाने वाले ट्रकों को राज्य की सीमाओं को पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही और बंद को लागू करने के तरीके पर अनिश्चय की स्थिति में दिखती पुलिस ने कई स्थानों पर सब्जी और फलों की दुकानें भी बंद

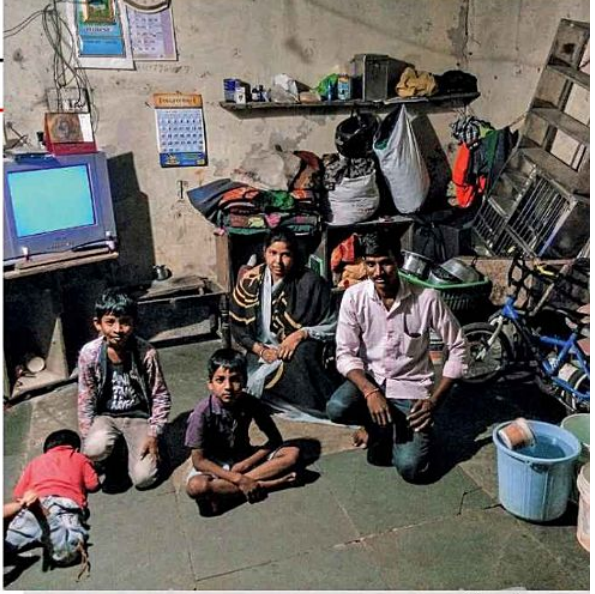

किरण तारे

"सामाजिक अलगाव हमारे लिए असंभव है"

अनिल शेल्के, 35 वर्ष
दिहाड़ी मजदूर, ठाणे

अनिल शेल्के पत्नी और तीन बच्चों सहित पांच लोगों के परिवार के अकेले कमाऊ सदस्य हैं. उन्होंने लॉकडाउन के दौरान गुजर-बसर के लिए पर्याप्त राशन जमा करके नहीं रखा. वे कहते हैं, ''अब मुझे चिंता होती है.'' उन्हें यह भी नहीं पता है कि महाराष्ट्र सरकार की योजना में दिया जा रहा तीन महीने का राशन उन्हें कैसे मिलेगा. मुसीबत यह कि शेल्के के पास राशन कार्ड भी नहीं है. वे कहते हैं, ''मेरे मकान मालिक ने अभी तक किराया (2,500 रुपए) नहीं मांगा है, इसलिए वह रकम मैं खाने पर खर्च कर सकता हूं, लेकिन लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो मैं गहरी मुश्किल में पड़ जाऊंगा.'' कोरोना वायरस की महामारी के दौर में शेल्के सामाजिक दूरी बनाने की अहमियत समझते हैं, पर जब अगल-बगल 26 मकान और उनके बीच एक साझा टॉयलेट हो तो इस कोशिश का कोई मतलब नहीं रह जाता. वे कहते हैं, ''सामाजिक अलगाव हमारे लिए असंभव है.''

–किरण डी. तारे

करा दी हैं. सबसे ज्यादा प्रभावित शहरी गरीब हुए हैं क्योंकि वे अपनी जरूरत का सामान दैनिक आधार पर खरीदते हैं. मेहरोत्रा कहते हैं कि अचानक नौकरी छूटने और आपूर्ति बाधित होने से प्रवासी कामगारों में दहशत फैल गई. उन्हें डर सताने लगा कि कोविड-19 से वे मरें न मरें लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे. वे कहते हैं, ''अपने गांवों में, उन्हें कुछ भोजन या मनरेगा के तहत काम मिलने की उम्मीद रहती है. उन्हें लगता है कि और कुछ न सही पर रबी फसल की कटाई से तो उन्हें जीवन बचाने भर की कमाई हो ही जाएगी. शहरों ने उन्हें ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जिससे वे वहीं बने रहते. ''

लेकिन दिल्ली में रहने वाले रमेश मीणा के लिए तो गांव जाने वाला कोई विकल्प भी नहीं है. पर्दे और गद्दे बनाने वाले 60 वर्षीय मीणा शहर के खानपुर की तंग गंदी गलियों में दो कमरे के घर में पत्नी के साथ रहते हैं. मीणा के पास एक सप्ताह से कोई काम नहीं है और बंदी की शेष अवधि के दौरान भी उन्हें किसी भी आय की उम्मीद नहीं है. हालांकि, अपनी बचत से वे एक या दो महीने तक किसी तरह परिवार चला सकते हैं, लेकिन उससे आगे अगर उनके पास कोई काम नहीं रहा तो तो परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों के आगे हाथ फैलाना पड़ सकता है. केंद्र के पैकेज में 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब विकलांगों के लिए 1,000 रुपए के पूर्व भुगतान का उल्लेख है, लेकिन मीणा को यह जानकारी नहीं कि यह सहायता पाने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है. वे मजाक करते हैं, ''लॉकडाउन से दिल्ली की हवा बहुत स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त हुई है. लेकिन इसका आनंद लेने में सक्षम होने के लिए, मुझे जीवित रहना होगा और उसके लिए भोजन की आवश्यकता है.''

शहरी गरीबों का एक बड़ा हिस्सा प्रवासी श्रमिकों का है जो शहरों में कई क्षेत्रों और सेवाओं को चलाते हैं. 2011 की जनगणना ने अनुमान लगाया था कि देश में करीब 13.9 करोड़ आंतरिक प्रवासी (राज्य के भीतर और राज्य से बाहर प्रवास) हैं, 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि 90 लाख लोग प्रति वर्ष एक राज्य से दूसरे राज्य में काम या शिक्षा के लिए पलायन करते हैं. केंद्रीय श्रम मंत्रालय प्रवासी श्रमिकों का डेटा नहीं रखता. हालांकि, अतीत में आर्थिक सर्वेक्षणों ने उन्हें कुल कार्यबल

MAGAZINE KING

क्या करने की जरूरत है

केंद्र का 1.7 लाख करोड़ रु. का राहत पैकेज अच्छी शुरुआत है पर चौतरफा मुसीबतों के खात्मे के लिए काफी नहीं

- केंद्र और राज्य सरकारों को गहरे तालमेल के साथ काम करना ही होगा ताकि प्रशासनिक अड़चनों के बगैर लाभ समय पर पहुंचाए जा सकें. प्रभावी कामकाज के लिए पीडीएस प्रणाली को आसान और कारगर बनाना चाहिए
- स्थानीय प्रशासनों को गैर-पंजीकृत कामगारों की तेजी से पहचान करना और उन्हें वित्तीय सहायता देने का तरीका निकालना चाहिए
- केंद्र को जेएएम (जन धन, आधार, मोबाइल) ढांचे का फायदा उठाते हुए दोहराव के बगैर यथासंभव ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सभी नकद लाभ का अंतरण करना चाहिए
- केंद्र सरकार को छोटे कारोबारों को मटियामेट होने और जबरदस्त बेरोजगारी पैदा होने से बचाने के लिए आर्थिक पैकेज लेकर आना चाहिए
- झुग्गी बस्तियों और दूसरे भीड़-भाड़ भरे शहरी मोहल्लों में जहां सामाजिक दूरी बनाना लगभग नामुमकिन है, जबरदस्त जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए. यहां पानी की नियमित सप्लाई और साफ-सफाई रखने के लिए जरूरी की चीजों का मिलना पक्का करना चाहिए

राजवंत रावत

आसाराम, 29 वर्ष
माली, रजोकरी पहाड़ी, दिल्ली

''हम तो भगवान भरोसे हैं''

आसाराम एक दशक पहले उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से दिल्ली आए थे. उनके परिवार में पत्नी, दो बेटे और दो बेटियां हैं. लॉकडाउन से पहले पूरा परिवार उनकी करीब 12,000 रुपए की मासिक आमदनी पर गुजर-बसर करता था. अब जब काम-धंधा बंद है, अपनी बचत के सहारे आसाराम 15 दिन से ज्यादा गुजारा नहीं कर सकते. उनके मकान मालिक मांगेराम ने 1,700 रुपए का मासिक किराया माफ कर दिया है और रुपए-पैसे से मदद की पेशकश भी की है. मगर आसाराम जानते हैं कि वे ऐसी मेहरबानियों के भरोसे नहीं रह सकते, खासकर जब उनका न कोई बैंक खाता है और न ही उन्हें किसी सरकारी योजना का फायदा मिल रहा है. वे मास्क जरूर पहनते हैं, पर साफ-सफाई और सामाजिक दूरी रख पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है. वे कहते हैं, ''साबुन और पानी मुफ्त में तो मिलते नहीं, इसलिए मैं हर वक्त अपने हाथ धोता नहीं रह सकता. हम जो भी थोड़ी-बहुत सावधानी बरत सकते हैं, बरतते हैं और बाकी सब भगवान भरोसे छोड़ दिया है.''

—कौशिक डेका

ए. शिवा

कमाल खान, 38 वर्ष
बढ़ई, सिकंदराबाद

''जल्द हमें भूखा रहना पड़ेगा''

कमाल खान को जल्दी ही एहसास हो गया कि लोक संगीत की उनकी पारिवारिक विरासत धन कमाने के काम नहीं आएगी और उन्होंने बढ़ई का काम सीखने का फैसला कर लिया. वे रोज 500 रुपए कमा लेते थे और अंजैया नगर में दो कमरों के मकान में पत्नी, तीन स्कूल जाने वाले बेटों, स्कूल जाने वाले भतीजे और भतीजी के साथ रहते थे. लॉकडाउन में उनकी आजीविका चौपट हो गई. 300 वर्ग फुट के उनके किराये के मकान में सामाजिक दूरी बनाकर रख पाना भी व्यावहारिक नहीं है. तेलंगाना सरकार के घोषित 12 किलो चावल और 500 रु. नकद लॉकडाउन के पहले सप्ताह में तो उन तक पहुंचे नहीं हैं. खान की पेशानी पर बल पड़ गए हैं. वे कहते हैं, ''अगर कोई मदद नहीं आती तो 10वां दिन आते-आते हमें भूखा रहना पड़ेगा.'' —अमरनाथ के. मेनन

का लगभग 20 प्रतिशत माना है. उनमें से ज्यादातर निर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं.

राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट में निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या 5.1 करोड़ होने का अनुमान जताया गया है, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत प्रस्तावित कल्याण कोष में केवल 3.5 करोड़ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लक्षित किया गया है. दिल्ली स्थित आर्किटेक्चरल फर्म एनार कंसल्टेंट्स के पार्टनर दीपांकर मजूमदार कहते हैं, ''हमने अपने निर्माण स्थलों पर ही मजदूरी भुगतान और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है, लेकिन हम एक हद से आगे इस मदद का वादा नहीं कर सकते. हालांकि, अधिकांश मजदूर अभी साइट पर हैं.'' उनका कहना है कि सरकार को लोगों की आवाजाही का अनुमान लगाना चाहिए था, ''हमने यही स्थिति सर्दियों में देखी थी जब प्रदूषण के कारण दिल्ली में दो महीनों के लिए निर्माण कार्य बंद करा दिया गया था.''

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ घंटों के नोटिस में बंद करने की बजाए, पूर्णबंद को बेहतर योजनाबद्ध तरीके से किया जाता तो यह यह प्रभावी हो सकता था. दक्षिण अफ्रीका में ऐसा हुआ है. वहां भी इसी तरह के पूर्णबंद के ऐलान से पहले तीन दिन का नोटिस दिया गया था. तो क्या सरकार हाशिए पर खड़े लोगों के जीवन पर इस पूर्णबंद के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने में पूरी तरह से विफल रही? मेहरोत्रा कहते हैं, ''सरकार स्थितियों का पूर्वानुमान लगाने की बजाए स्थितियां पैदा करके फिर उसे संभालने की कोशिश कर रही है. गरीब इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि सरकार ने न तो उन्हें तैयार होने का समय दिया और न ही पूर्व आश्वासन दिया कि उनकी हर तरह से देखभाल की जाएगी. बिना आजीविका और खाद्य सुरक्षा के कोई अपनी जगह पर बना रहेगा, इसकी उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं है.''

सरकार ने पूर्णबंद के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की थी. इसका अंदाजा गृह मंत्रालय की ओर से छूट वाली आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सूची में लगातार नई चीजें शामिल किए जाने से लगाया जा सकता है. 26 मार्च को, मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि 'पशु आहार और चारा' आपूर्ति भी छूट में शामिल हैं और मंत्रालय ने स्वीकार किया कि कुछ राज्य इसकी अनुमति नहीं दे रहे थे. 27 मार्च को, मंत्रालय ने खेती से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को आवश्यक सेवाओं में रखने की जानकारी दी. 29 मार्च को केंद्र आवश्यक वस्तुओं से आगे निकल गया और 'सभी वस्तुओं' के परिवहन से प्रतिबंध हटा दिया. हालांकि, केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी, स्थिति को 'विशिष्टता' की ओर इशारा करते हैं. अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, ''योजना में खामियां हो सकती हैं लेकिन यह असाधारण स्थिति है. दुनिया अभूतपूर्व संकट से दो-चार है और हर देश अपने जोखिमों और सीमाओं को ध्यान में रखकर प्रतिक्रिया कर रहा है. देखिए, विकसित देश भी इसमें कैसे उलझ गए हैं.''

2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, देश के कुल कार्यबल का लगभग 93 प्रतिशत—अनुमानित 43.7 करोड़ लोग—अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं. इसमें कृषि, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, स्वच्छता और घरेलू श्रमिक शामिल हैं. यद्यपि देश के सकल घरेलू उत्पाद में अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान लगभग आधा है, लेकिन इसके अधिकांश श्रमिक खराब हालात में काम करते हैं और मामूली मजदूरी पाते हैं. शहरी क्षेत्रों के श्रमिकों में हुए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-2018 के अनुसार, पुरुषों ने दैनिक मजदूरी के रूप में 314-335 रु. कमाए, जबकि महिलाओं ने उनसे काफी कम मात्र 186-201 रु. कमाए और वे किसी भी तरह की बचत में असमर्थ रहीं. इससे भी बुरी बात यह है कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेज में घोषित उपाय उन तक नहीं पहुंच सकते हैं.

केंद्र और कई राज्यों ने दुकानों, प्रतिष्ठानों और अन्य वाणिज्यिक इकाइयों से कहा है कि वे तालाबंदी के दौरान अपने श्रमिकों को मजदूरी देना जारी रखें. हालांकि, कब तक संभव होगा यह बहस का विषय है क्योंकि ऐसी ज्यादातर इकाइयां अनौपचारिक प्रकृति की हैं और राज्यों में असंगठित क्षेत्र के ज्यादातर श्रमिक अपंजीकृत हैं. चिदंबरम ने सरकार से अपील की है कि वह सभी पंजीकृत नियोक्ताओं को रोजगार और मजदूरी के अपने वर्तमान स्तर को बनाए रखने के निर्देश दे और उन्हें यह आश्वासन दे कि उनकी तरफ से भुगतान की गई मजदूरी की प्रतिपूर्ति 30 दिनों

के भीतर सरकार कर देगी. इसके अलावा, आमतौर पर छोटी दुकानें और प्रतिष्ठान वेतन और अन्य जरूरी खरीदारी के लिए लगभग एक सप्ताह के खर्च की पूंजी सुरक्षित रखते हैं. यानी तीन सप्ताह की बंदी में उनकी आर्थिक व्यवहार्यता को गंभीर धक्का पहुंचने का डर है. दास कहते हैं, ''यह पैकेज लाखों छोटे व्यवसायों को बचाने में नाकाम रहेगा, जो बंद हो सकते हैं क्योंकि उनके पास माल को अपने पास बनाए रखने की क्षमता नहीं है.'' नोटबंदी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने से मिले सबक का इस्तेमाल करते हुए और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को छोटे व्यवसायों के लिए राहत कार्यक्रम को तैयार करने का आग्रह करते हुए वे कहते हैं, ''भारत एसएमई (छोटे और मझोले उद्यमों) से चलता है. अगर आप उनको सुरक्षित नहीं करते हैं, तो आप भारत की रक्षा नहीं कर सकते. बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का सामना करना होगा.''

कांग्रेस ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह देश के 4.25 करोड़ एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के वेतन और मजदूरी बिल का अगले तीन महीनों का जिम्मा उठाए. एक अनुमान के अनुसार, इस पर 1.5 लाख करोड़ रु. की लागत आएगी. इसने अगले छह महीनों के लिए किसी भी क्षेत्र में छंटनी को रोकने के लिए कानून की भी मांग की है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के अनुसार, तत्काल जरूरत यह सुनिश्चित करने की है कि नकदी सही हाथों और सही समय पर पहुंचे. राजन ने इंडिया टुडे टीवी के साथ बातचीत में कहा, ''भारत के सबसे ज्यादा जोखिम वाले परिवारों—गरीबों और प्रवासियों—के लिए हमें पुलों की जरूरत है. हमें उन तक पैसा पहुंचाने के नए तरीकों की जरूरत है.'' उन्होंने कंपनियों की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया. ''हमें फर्मों को भी जीवित रखने की आवश्यकता है. अगर वे व्यवहार्य हैं तो उन्हें बंद होने से बचाएं. यह निर्णय बहुत सावधानी से करना होगा.''

कई राज्य सरकारों ने भी शहरी गरीबों की सुरक्षा के लिए उपायों की घोषणा की है, लेकिन स्पष्ट रूप से इनको लागू करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है. जैसा कि पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् प्रणब सेन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर बेरोजगारों, गरीब शहरी आबादी और प्रवासी श्रमिकों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है तो 'अन्न के लिए दंगे' छिड़ जाने की पूरी संभावना है. सेन ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा, ''हमने पहले भी अकाल के समय अन्न के लिए हिंसा देखी है. अगर भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया तो हमें फिर से भोजन के लिए दंगे देखने को मिल सकते हैं.''

मेहरोत्रा ने भी इस चेतावनी का समर्थन किया है और प्रस्ताव दिया है कि शहर की सड़कों पर बंचितों को खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों को इसमें तत्काल शामिल किया जाए. वे कहते हैं, ''गरीबों को खिलाने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट्स को एक साथ आना चाहिए. निजी खिलाड़ियों की मदद से, जिला प्रशासन आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध रख सकता है.'' कुछ राज्य पहले से ही सरकारी आश्रयों में गरीबों को मुफ्त भोजन प्रदान कर रहे हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनका प्रशासन 224 रैन बसेरों, 325 स्कूलों और अन्य स्थानों पर लगभग 4,00,000 लोगों को रोजाना दो बार भोजन मुहैया करा रहा है.

हालांकि अधिकारी अनाज के लिए दंगे की आशंकाओं को खारिज करते हैं. वे भारतीय खाद्य निगम, राज्य एजेंसियों और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघों के पास मौजूद गेहूं, चावल और दालों के अतिरिक्त स्टॉक की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, ''चुनौती इस खाद्यान्न को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की है. सरकार सामान की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रही है और आशा है कि स्थिति जल्द ही नियंत्रण में होगी.'' ■

मनीष भंडारी

''सरकार को मुझे वैकल्पिक रोजगार देना चाहिए''

चंदन कुमार, 29 वर्ष
टूरिस्ट गाइड, बोधगया, बिहार

चंदन कुमार, उनका बड़ा भाई सूरज जो सेल्समैन हैं और मैकेनिक पिता कमलेश मिलकर हर महीने 30,000 रुपए कमा लेते थे. लॉकडाउन के चलते तीनों बेरोजगार हो गए. परिवार के पास कुल जमा 12,000 रुपए हैं और थोड़ा-सा राशन. चंदन कुमार कहते हैं, ''मेरे भाई और पिता तो हालात सामान्य होने पर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरा भविष्य अंधेरे से भरा नजर आता है क्योंकि साल के अंत से पहले सैलानियों के बोधगया आने की कोई संभावना नहीं है. सरकार को मुझे वैकल्पिक काम-धंधा देना चाहिए.''

–अमिताभ श्रीवास्तव

आवरण कथा
महामारी से मुकाबला

आवश्यक वस्तु आपूर्ति

ताकि गाड़ी न थमे

देश का 15 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसपोर्ट और आपूर्ति तंत्र अर्थव्यवस्था की जान है, 24 मार्च को अचानक देशव्यापी लॉकडाउन से यह पूरी तरह ठप हो गया, जिससे पहले से ही खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पंगु हो गई. सुधार के लिए सरकार को उठाने होंगे सही दिशा में तेज कदम

एम.जी. अरुण, अनिलेश एस. महाजन और श्वेता पुंज
फोटोः मनीष अग्निहोत्री

अटके पड़े भूटान जा रहे कोयला से लदे ट्रक लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर खड़े

MAGAZINE KING

सामान्य दिनों में हिंदुस्तान का ट्रांसपोर्ट और माल-असबाब ढुलाई तंत्र रोज देश भर में 75 लाख ट्रकों, 7,400 मालगाड़ियों और बीसियों कार्गो विमानों की आवाजाही का गवाह बनता है. साथ ही दूसरे लाखों वाहन न केवल फैक्टरियों तक कच्चा माल पहुंचाते हैं बल्कि किराना दुकानों, सुपरमार्केट और ग्राहकों के दरवाजे तक रोजमर्रा का सामान भी. 24 मार्च की शाम को आधी रात से ही देशव्यापी लॉकडाउन के केंद्र सरकार के ऐलान ने अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई को एकदम ठप कर दिया. सरकार को जल्दी ही समझ आ गया कि यह ऐसा व्यवधान है जिसे देश गवारा नहीं कर सकता. सो, केंद्र ने अगले ही हफ्ते नया आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि अनिवार्य ही नहीं, बल्कि सभी वस्तुओं की ढुलाई लॉकडाउन से मुक्त रहेगी. तब तक इस व्यवस्था के पहियों को चलाने वाले कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कामगारों की मानव श्रृंखला झुंडों में अपने गांव लौटने लगी थी. इससे आगामी हफ्तों में देश भर के बाजारों में चीजों की किल्लत का अंदेशा खड़ा हो गया.

देश के आर्थिक ढांचे के अचानक इस तरह ठप हो जाने से आर्थिक विकास दर के पूर्वानुमान और भी गड़बड़ा गए, जिसके चलते रेटिंग एजेंसियों ने खतरे की घंटियां बजानी शुरू कर दीं. क्रिसिल ने 26 मार्च को वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 5.2 फीसद से घटाकर 3.5 फीसद कर दिया. मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस ने 27 मार्च को मौजूदा वित्त वर्ष में वृद्धि का अनुमान आधे से भी कम करके 2.5 फीसद कर दिया. विशेषज्ञों की मानें तो यह तकलीफ अगली कई तिमाहियों तक उठानी पड़ेगी.

मार्च के आखिर में लॉकडाउन का पहला हफ्ता खत्म होने पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कुछ शीर्ष उद्योगपतियों के साथ फोन पर जमीनी हालात को समझने की कोशिश की. इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी उदय कोटक और टेक महिंद्रा के सीईओ और एमडी सी.पी. गुरनानी सरीखे बड़े उद्योगपति शामिल थे. सूत्रों के मुताबिक, उनके बीच बातचीत का एक बड़ा मुद्दा यह था कि सामान की ढुलाई फिर से पटरी पर कैसे लाएं. कारोबारी अगुआओं ने मंत्रियों को बताया कि जरूरी सामान की ढुलाई में भी कैसे दिक्कतें आ रही हैं, ट्रक ड्राइवर अफसरों और लालफीताशाही के हाथों प्रताड़ित हो रहे हैं और तमाम किस्म का माल देशभर के राजमार्गों पर अटक गया है.

हालांकि लॉकडाउन का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

कहा था कि सरकार ने जरूरी चीजों की आपूर्ति सुचारु रखने की व्यवस्था की'' थी. लेकिन 'जरूरी वस्तुओं' को लेकर कानूनी अस्पष्टता के नतीजतन ढुलाई ठप पड़ गई. गतिरोध तोड़ने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 30 मार्च को देश भर में 'जरूरी और गैर-जरूरी' का फर्क किए बगैर सभी सामान की ढुलाई की इजाजत दे दी. अधिसूचना में न केवल आर्थिक आपूर्ति शृंखला की जटिलताओं और प्रशासनिक प्रक्रिया की उलझनों को सामने रखा गया, बल्कि 'हैंड वाश, साबुन, डिसइंफेक्टैंट (और) बॉडी वाश' जैसी तमाम चीजों के बाकायदा नाम बताए गए, जिन्हें जरूरी माना जाता है.

नाम न छापने की शर्त पर एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी के अधिकारी कहते हैं, ''पूरी सप्लाई चेन ठप है. गृह मंत्रालय की सफाई के बाद चीजें थोड़ी दुरुस्त होने की उम्मीद थी पर इस चेन को आप बटन दबाकर तो शुरू कर नहीं सकते.''

सड़कों से उतरा ट्रांसपोर्ट

बुनियादी परेशानी तो कोरोना वायरस की महामारी है, पर बड़ी दिक्कत ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के आकार और जटिलता को लेकर है. महज एक बड़ी घटना ऐसे नतीजे ला सकती है जिसकी गूंज हफ्तों तक सुनाई दे. मसलन, वाहनों की आवाजाही ठप पड़ जाना. भारतीय ट्रांसपोर्टरों की शीर्ष संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस टोल कमिटी के मुताबिक, लॉकडाउन की अचानक घोषणा के फौरन बाद 75 लाख ट्रकों में से 15 लाख ट्रक, साथ ही 30 लाख ड्राइवर-क्लीनर राजमार्गों और सड़कों पर अटक गए. उम्मीद है कि गृह मंत्रालय की 30 मार्च की अधिसूचना से जल्दी ही ये रुकावटें दूर होंगी.

भारतीय ट्रांसपोर्ट सेक्टर बुनियादी तौर पर ट्रक आधारित है. केयर रेटिंग्स की नवंबर, 2019 की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत का 60 फीसद लॉजिस्टिक्स यातायात सड़कों से और 30 फीसद रेल से होता है. आखिरी रेलवे स्टेशन से गोदामों और बाजारों तक की दूरी पार करने के लिए भी ट्रकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है. भारत में करीब 60 लाख किमी सड़कों का जाल है. इसमें 1,14,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग और 1,75,000 किमी राज्य राजमार्ग हैं. ज्यादातर सामान की ढुलाई सड़कों के रास्ते होती है, इस हकीकत की तस्दीक राष्ट्रीय जीवीए (सकल मूल्य संवर्धित, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मापने का पैमाना) में इस क्षेत्र के योगदान से भी होती है. 2016-17 में ट्रांसपोर्ट क्षेत्र ने देश के जीवीए में 4.85 फीसद का योगदान दिया, जिसमें सड़क यातायात का 3.12 फीसद, रेलवे का 0.77

जाने को तैयार, छोड़ने को नहीं

हरीश चंद्र यादव, 55 वर्ष
ड्राइवर, श्रेया लॉजिस्टिक, मुंबई

राष्ट्रीय लॉकडाउन उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले ट्रक ड्राइवर यादव (सफेद शर्ट में) के लिए दुःस्वप्न की तरह आया है. उनका ट्रक लॉकडाउन की घोषणा वाले दिन यानी 24 मार्च से ही खड़ा है. उनके मालिक ललित कुमार पाठक के पास 25 ट्रेलर ट्रकों का एक बेड़ा है, लेकिन वे सभी अब नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के पास, जसाई में कंपनी के गैराज में खड़े हैं. कोई भी नहीं जानता कि टेक्सटाइल, रबर और स्टील कंपनियों में, जिनके साथ उसकी कंपनी वडोदरा, वापी और सिलवासा शहर में काम कर रही है, वहां व्यावसायिक गतिविधियां कब पटरी पर लौटेंगी. पाठक का कुछ कामकाज कृषि उत्पाद से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इनसे लदे ट्रकों को भी अक्सर चेकपोस्टों पर रोका जा रहा था, जिससे गतिविधि को रोकने का निर्णय लिया गया. पाठक कहते हैं, ''हमारे ज्यादातर कर्मचारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. वे घर जा नहीं सकते, इसलिए मुझे उनके भरन-पोषण की व्यवस्था करनी होगी, जिसका खर्च प्रति दिन करीब छह हजार रुपए है.''

–एम.जी. अरुण

200
अरब डॉलर
का आकार है देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र का. यह आंकड़ा इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का

15
लाख
ट्रक सड़कों पर फंसे. यह आंकड़े ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट क्रांग्रेस टोल कमेटी के मुताबिक

3.5
फीसद
रह सकती है वित्त वर्ष 2020-21 में देश की आर्थिक विकास दर. क्रिसिल ने पिछले अनुमान 5.2 फीसद से घटाया

और हवाई यातायात का 0.16 फीसद था.

यातायात ठप हो जाने के संकेत देश भर की कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) के बाजारों में देखे जा सकते हैं. ताजा कृषि उपज का लेनदेन करने वाले ये बाजार आम तौर पर चहल-पहल से भरे रहते हैं. मगर लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में वे उजाड़ और सुनसान पड़े थे. देश की 2,400 से ज्यादा मंडी समितियों में से 300 से ज्यादा महाराष्ट्र में हैं. करीब 5,00,000 ट्रक रोज देश भर के इन बाजारों से सब्जियों और फलों की ढुलाई करते हैं. आवाजाही थोड़ा खुलने के बावजूद आवक सामान्य से कम है. महाराष्ट्र में नवी मुंबई की वाशी मंडी में रोज 400-500 ट्रक महाराष्ट्र के तमाम इलाकों से कृषि उपज लेकर आते हैं. 1 अप्रैल की सुबह ऐसे केवल 80 ट्रक आए थे.

उधर, भारतीय रेल मालगाड़ियों से भारी तादाद में ढुलाई करती है. अनाजों का भंडार रखने और उसे देश भर में वितरित करने वाले भारतीय खाद्य निगम के अनाजों की ढुलाई रेल से ही होती है. निगम की हर साल 4 करोड़ टन अनाजों की ढुलाई में से करीब 85 फीसद रेल से होती है. कुछेक टन ही अनाज लक्षद्वीप और अंडमान, निकोबार सहित मुख्य भूभाग से दूर के इलाकों में समुद्री जहाजों से पहुंचाए जाते हैं. केरल और त्रिपुरा के अगरतला तक नदियों के रास्ते पानी के जहाज माल ले जाते हैं. रेल और सड़क से ढोई जाने वाली 21 शीर्ष वस्तुओं में फल और सब्जियों की सबसे कम ढुलाई रेल मार्ग से की जाती है.

महामारी के चलते ड्राइवर भी कम मिल पा रहे हैं. एक अग्रणी फूड कंपनी के सीईओ बताते हैं, ''ड्राइवर अब कह देते हैं कि नहीं आ सकते या यूनियनें ज्यादा पैसा मांगती हैं. कंपनियों के लिए इस बढ़ी लागत को उपभोक्ताओं पर डाल पाना असंभव होगा.'' पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के ट्रक यूनियन के एक प्रमुख नेता संजीव दीवान कहते हैं, ''कई ड्राइवर इसलिए काम पर नहीं आ रहे क्योंकि उनके परिवार चिंतित हैं.'' माल की ढुलाई को फिर से पटरी पर लाना इसलिए और भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि कुछ राज्यों ने खुद अपने लॉकडाउन लगा दिए हैं. 30 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के लॉकडाउन को भी अपने राज्य में 14 अप्रैल तक बढ़ा दिया और अपने राज्य की सीमाओं को सील करने का निर्देश भी दे दिया.

उधर, कार्गो उड़ानें बढ़ाने की भी कोशिश होती दिखाई दे रही है—भले ही ऐसा केवल जरूरी चिकित्सा आपूर्तियों के लिए ही किया जा रहा हो. केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय ने 30 मार्च को ऐलान किया कि उसने राज्य सरकारों की चिकित्सा आपूर्तियों की गुजारिशों के साथ तालमेल बिठाते हुए 'देश भर में सप्लाई के काम पूरे करने' के लिए एयर इंडिया और एलायंस एयर के विमानों की सहायता ली. उसने यह भी बताया कि एलायंस एयर की एक उड़ान 29 मार्च को कोलकाता, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और अगरतला के लिए ऐसी आपूर्तियां लेकर नई दिल्ली से कोलकाता गई. इसके अलावा आइसीएमआर (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) की कोविड-19 किट की खेप विमान से नई दिल्ली और चेन्नै सरीखे मेट्रो शहरों में भेजी गई.

व्यावसायिक उड़ान के मामले में तस्वीरें मिली-जुली दिखती हैं. स्पाइसजेट की कार्गो शाखा स्पाइसएक्सप्रेस का कहना है कि हाल के दिनों में ज्यादा जोर चिकित्सा सामान—डायग्नोस्टिक किट, फेस मास्क, सैनिटाइजर और सर्जिकल उपकरण—की ढुलाई पर रहा है और यहां तक कि सरकार की ढुलाई की मांग को पूरा करने के लिए स्पाइसजेट अपने यात्री विमानों को भी कार्गो के हिसाब से ढाल रहा है. कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि शुरुआती लदान और आखिरी डिलिवरी में उन्हें दिक्कतें पेश आईं. उन्होंने यह भी कहा कि महामारी के दौरान सामान की आवाजाही पर लगाए गए नियम-कायदों के अमल में उम्मीद से ज्यादा वक्त लगा है. स्पाइसएक्सप्रेस के पांच समर्पित कार्गो विमानों का बेड़ा है, जो रोज देश भर के चक्कर लगाते हैं और ताजे फलों तथा सब्जियों, शीत शृंखला वाली चिकित्सा आपूर्तियों और दवाइयों की खेप लेकर पश्चिम एशिया और दक्षिणपूर्व एशिया के देशों तक भी उड़ान भरते हैं. कंपनी का कहना है कि भारत से पश्चिम एशिया को मांस, ताजे फलों और सब्जियों की ढुलाई की मांग में बढ़ोतरी हुई है.

कारोबार पर चोट

देश का आर्थिक इंजन माना जाने वाला एफएमसीजी सेक्टर पूरी तरह भले-चंगे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर निर्भर है. उद्योग के प्रवक्ता बताते हैं कि लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में सामान और कामगारों की आवाजाही पर अचानक पाबंदी लगने के बाद कारोबार में भारी रुकावटें पैदा हुईं. देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, लॉकडाउन के

पहियों को पटरी पर लाने के खातिर

लॉजिस्टिक क्षेत्र को शीघ्र पटरी पर वापस लाने के छह नुस्खे

- प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना होगा. खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को खरीद, प्रसंस्करण और वस्तुओं की आपूर्ति के लिए तेजी से मंजूरी देनी होगी
- एक केंद्रीय नियंत्रण एजेंसी की स्थापना की जाए. इसमें अनुमतियों और छूट के साथ-साथ पूरे देश में सुचारु दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शामिल है
- पास जारी करने के लिए एक स्पष्ट तंत्र लागू करना होगा. इसमें आवश्यक दस्तावेजीकरण, प्रक्रियागत दिशानिर्देशों और पास जारी करने की समय सीमा शामिल है. एक समर्पित हेल्पलाइन भी उद्योग को लाभान्वित करेगी
- स्पष्टता पर दिशा-निर्देश जारी करना होगा. वस्तुओं को संभालने के लिए स्पष्ट नियम भी इस समय जरूरी हैं
- हवाई अड्डों से कनेक्टिविटी में सुधार करना होगा. इससे विमान के जरिये बेहतर माल ढुलाई की सुविधा मिलेगी
- इन्वेंट्री का स्तर बढ़ाने की जरूरत है. खुदरा विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने भंडार को प्रभावी और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि वे शिपमेंट आगमन में अप्रत्याशित देरी पर काबू पा सकें

MAGAZINES

ठीक पहले और बाद के दिनों में अपनी 28 में से महज गिनी-चुनी फैक्टरियों का संचालन कर पाई. वायरस का फैलाव रोकने के लिए स्थानीय प्रशासनों ने कड़ी पाबंदियां लगा दीं, जिससे कामगारों की आवाजाही और कभी-कभी फैक्टरियों में काम रुक गया. बाद में कई फैक्टरियां बंद हो गईं. महाराष्ट्र में तो निजी दफ्तरों और फैक्टरियों को बंद करने का हुक्म सुना दिया गया. एफएमसीजी की शानदार कंपनी आइटीसी के प्रवक्ता इसी से मिलती-जुलती कहानी बयान करते हैं. एक प्रवक्ता बताते हैं, ''हमने कुछ राज्यों में सामान की ढुलाई और उसके इंतजाम की इजाजत तो पा ली, पर ट्रकों की कमी चुनौती बनी हुई है.''

आपूर्ति के रास्तों के बंद हो जाने की यह कहानी भारत के हरेक आर्थिक क्षेत्र में दोहराई गई. ट्रकों की अंतर-राज्य और स्थानीय आवाजाही पर देश भर में अचानक और जबरदस्त असर पड़ा, जिससे आपूर्ति की कतारें टूटी गईं—महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन की वजह से फैक्टरियों में कामगारों की और भी कमी हो गई और कारोबारी परिस्थितिकी तंत्र ही बिगड़ गया.

ई-कॉमर्स क्षेत्र में भी यह साफ दिखाई दिया. खुद को क्वारंटीन करने के सरकार के आह्वान के नतीजतन तमाम लोग 24 मार्च के पहले ही घरों में बंद हो गए और हड़बड़ी में अपनी रोजमर्रा की खरीद के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने लगे. संकट तीव्र होने के साथ ही अमेजन और बिग बास्केट सरीखे प्लेटफॉर्मों पर केवल जरूरी वस्तएं ही बेची जाने लगीं. फिर 25 मार्च को ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गए. नियम-कायदों में अस्पष्टता के कारण इस सबसे तेजी से उबर पाना असंभव हो गया—प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि 'अनिवार्य वस्तुओं' के लिए ट्रांसपोर्टरों को पास जारी किए जाएंगे, पर इसके प्रशासनिक नियम-कायदे तत्काल सामने नहीं आए. कंपनियों के लिए इसका मतलब था ऑर्डर पूरे करने में देरी.

नतीजतन ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियों ने 22 से 29 मार्च के बीच कारोबार वाकई और लंबे वक्त तक ठप पड़ते देखा. 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के दौरान, मांग में उछाल की उम्मीद के बावजूद अमेजन, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट ने पाया कि ऑर्डर गोदामों से ग्राहकों तक पहुंचा पाना असंभव है. उद्योग के एक सूत्र कहते हैं, ''जनता कर्फ्यू और देशव्यापी लॉकडाउन के बीच के दिनों में इस कदर अफरा-तफरी थी कि हरेक राज्य (प्रशासन) आवाजाही और ढुलाई पर पाबंदियों को लेकर स्वतंत्र फैसले ले रहा था.'' उसके बाद हालात में कुछ सुधार हुआ है. अमेजन इंडिया के एक सूत्र कहते हैं, ''जरूरी वस्तुओं के बारे में ज्यादा स्पष्टता के चलते हमने इन्हीं वस्तुओं की डिलिवरी करना तय किया है.''

तिस पर भी कई ऑनलाइन विक्रेता ऑर्डर पूरे करने में भारी दिक्कतें बता रहे हैं. ये इतनी व्यापक हैं कि पेटीएम मॉल ने ऑर्डर का माल भेजने में देरी और कैंसिलेशन पर व्यापारियों पर लगने वाले जुर्माने कुछ वक्त के लिए माफ कर दिए. इस प्लेटफॉर्म पर 1,00,000 ऑर्डर सरकारी पाबंदियों की वजह से लटके हुए हैं.

यहां तक कि फिलहाल सबसे अहम क्षेत्र फार्मास्युटिकल भी बचा नहीं है. केंद्र सरकार के फार्मास्युटिकल विभाग ने जहां 26 मार्च को ही निर्देश जारी कर दिए थे कि लॉकडाउन के दौरान दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के 'उत्पादन, पैकिंग और वितरण' के लिए कच्चे माल, पैकिंग सामग्री और मानवबल की बेरोक आवाजाही पक्की की जाए, वहीं विशेषज्ञों ने इसके अमल को लेकर सवाल उठाए हैं.

मेडिकल टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों की नुमाइंगी करने वाली शीर्ष संस्था मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमटीएएल) का कहना है कि राज्य सरकारें और स्थानीय स्तर के प्रशासन इन निर्देशों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं. एमटीएएल के चेयरमैन पवन चौधरी कहते हैं, ''लगता है, उन्हें यही समझ नहीं आया कि 21 दिनों का यह लॉकडाउन अस्पतालों को तैयार करने (और संभावित परिस्थिति के लिए संसाधन जुटाने और जमा करने) के लिए है.'' वे कहते हैं कि बेहद जरूरी कच्चा माल ले जा रहे ट्रक

सौरभ कुमार, 36 वर्ष
ग्रोफर्स एनसीआर के संस्थापक

बड़ी अफरातफरी वाला एक दिन

लॉकडाउन सौरभ के लिए तत्काल हताशा लेकर आया. उनके डिलिवरी एजेंट उनके गोदाम तक नहीं पहुंच सकते थे. उन्होंने बताया, ''पहले दिन बिल्कुल अराजकता की स्थिति थी. कागज पर जरूरी सेवा को अनुमति थी, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासन भ्रम की स्थिति में था. अनुमति हासिल करना बहुत बोझिल काम था—हमें हर उस जिले में आवेदन करना था, जहां हम काम करते हैं और हर जिले के अलग-अलग नियम थे.'' उनके व्यवसाय को अब श्रमिकों की कमी और वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ''उपभोक्ताओं को वस्तुओं की आपूर्ति को तो सुलझा लिया जाएगा, लेकिन निर्माताओं को कच्चा माल मिलना, कर्मचारियों की उपलब्धता और ब्रांडों से माल की आपूर्ति चिंता का विषय है.'' अधिकांश ब्रांडों का कहना है कि उनके पास एक महीने के लिए आपूर्ति श्रृंखला है, लेकिन अगर लॉकडाउन इससे आगे निकलता है, तो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कमी हो सकती है. सौरभ कुमार का कहना है कि एक केंद्रीयकृत नियंत्रण एजेंसी बनाने, मंजूरियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल और देश भर में समान दिशानिर्देशों से अराजकता को रोकने में मदद मिलेगी.

—श्वेता पुंज

संदीप सहदेव

संजीव दीवान, 47 वर्ष
मालिक, चंडीगढ़ इंदौर रोडलाइन्स चंडीगढ़

सामान्य स्थिति से दूर

दीवान की कंपनी शहर में सबसे बड़ी है, जो लगभग 40 ट्रकों का परिचालन करती है. उनका कहना है कि उनके 10,000 से अधिक साथियों के वाहन देश भर के राजमार्गों पर फंसे हुए हैं. और कई ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं हैं. दीवान कहते हैं, ''उनके परिवार के लोग चिंतित हैं.'' लंबी दूरी के ट्रक विभिन्न टोल प्लाजा और पेट्रोल पंपों पर फंसे पड़े हैं. फंसे हुए ड्राइवरों के पास खुद के लिए लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, लेकिन घर से दूर और खाने-पीने की चीजों तक सहज पहुंच न हो पाने से जीवन बेहद कठिन हो गया है. इससे भी बुरी बात यह है कि जब से पंजाब सरकार ने राज्य की सीमाओं को सील किया, तब से गतिविधि लगभग असंभव हो गई है.

–अनिलेश एस. महाजन

शहर और राज्य की सरहदों पर अटके हैं और हालांकि कुछ मैन्युफैक्चरिंग और वेयरहाउसिंग कंपनियों ने अपने कामकाज को लॉकडाउन से छूट देने वाले कागजात जारी किए हैं, लेकिन वे अपने सामान की आवाजाही को लेकर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक संस्थाओं के साथ अंतहीन मुकदमेबाजी में फंस गई हैं.

भारी-भरकम काम

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सीईओ के एक कंसोर्शियम ने 30 मार्च को अपने उद्योग की केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल से बात की. उन्होंने लॉकडाउन के दौरान राज्य प्राधिकारियों के परिवहन से जुड़े केंद्रीय निर्देशों का पालन नहीं करने सरीखे कई मुद्दे उठाए और कहा कि पुलिस को इस मामले में सरकार के निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी जाए. उन्होंने यह भी कहा कि फैक्टरियों को दोबारा खोलने के लिए जरूरी बहुत सारी छूट और अनुमतियां उद्योग पर असहनीय बोझ बन गई हैं.

कई और भी बड़े मुद्दे हैं. मसलन, जैसा कि दिल्ली के खाद्य तेलों के थोक व्यापारी रजनीश गुप्ता बताते हैं, खाद्य तेलों के उत्पादन और सप्लाई की इजाजत है, पर खाली बोतलों और ढक्कनों की नहीं. (इस परेशानी से फार्मास्युटिकल सरीखे उद्योग भी प्रभावित हैं). इस उद्योग के एक सीईओ का अनुमान है कि ''खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के पास औसतन करीब एक हफ्ते का स्टॉक (पैकेजिंग सामग्री का) है.'' मजदूरों-कामगारों का न मिल पाना और समस्या है—कामगार वायरस के डर से काम पर नहीं आ रहे. वे कहते हैं, ''हालांकि हम कामगारों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सामाजिक दूरी और साफ-सफाई के ऊंचे से ऊंचे मानक पक्के कर रहे हैं, फिर भी कई लोग नहीं लौट रहे.''

प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने 29 मार्च को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर को 11 कार्यकारी समूहों के गठन के बारे में जानकारी दी. ये समूह संकट पर सरकार की जवाबी कार्रवाई की देखरेख करेंगे और इनके बीच तालमेल का काम प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पी.के. मिश्र करेंगे. स्वच्छ भारत मिशन में प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके और अमल के अपने हुनर के लिए जाने जाने वाले अय्यर को लॉजिस्टिक पर बने कार्यकारी समूह की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वे कई अहम विभागों के बड़े अफसरों की एक टीम के प्रमुख हैं. इनमें अन्य विभागों के साथ खाद्य खरीद और सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले, सीमा प्रबंधन, सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) और एनडीएमए (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) शामिल हैं. उनका सबसे अहम काम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को वापस पटरी पर लाना है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अय्यर का समूह इस क्षेत्र को क्षमता के 40 फीसद तक भी तेजी से वापस ला पाता है तो यह बड़ी कामयाबी होगी. यह लक्ष्य ही अपने आप में बताता है कि मौजूदा हालत कितनी बुरी और नाजुक है.

अय्यर के समूह को अनगिनत मुद्दों के समाधान खोजने हैं. मसलन, सरकार को चाहिए कि वह तमाम राज्यों में अलग-अलग उद्योगों को जारी किए जाने वाले छूट के कागजात की एक दोटूक व्यवस्था तेजी से बनाए, छापे और अमल में लाए. कुछ राज्य और स्थानीय प्रशासन अपनी ओर से मदद की कोशिश कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वह परिवहन पास की व्यवस्था तेजी से लागू करेगी, जबकि बेंगलूरू पुलिस ने कर्फ्यू पास के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और महाराष्ट्र सरकार ने ट्रांसपोर्टरों के लिए पास और दिशानिर्देश जारी करना शुरू कर दिया है.

कोरोना वायरस की महामारी से दरपेश, राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने के सरकार के फैसले को आम तौर पर बुरा पर जरूरी माना गया है. अलबत्ता इलाज बीमारी से ज्यादा महंगा साबित न हो, इसके लिए जरूरी है कि देश में अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था—जो पूरी तरह अच्छे ढंग से कार्यरत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक क्षेत्र पर निर्भर है—मजबूत और सक्रिय बनी रहे. खाने-पीने की चीजों, दवाइयों और चिकित्सा सामान सहित ऐसी वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति पर मंडराते संकट से युद्ध स्तर पर नहीं निबटा गया, तो लॉकडाउन देश पर असहनीय बोझ डाल देगा. –साथ में, किरण डी. तारे

छोटों को बड़े सहारे की जरूरत

लॉकडाउन में कारोबार पूरी तरह बंद, मगर किराए, बिजली के बिल, कर्मचारियों के वेतन जैसे तय खर्चों से छोटे उद्योग पस्त, बंदी खत्म होने के बाद भी मांग और भुगतान को लेकर अनिश्चितता

शुभम शंखधर

कमर सिद्दीन/मेल टुडे

MAGAZINE KING

आगरा के शहीद नगर में देशराज का जूते बनाने का कारखाना है, जो इन दिनों लॉकडाउन की वजह से बंद है. यहां 12 लोग तय मासिक वेतन पर और 8 दिहाड़ी पर काम करते थे. 38 वर्षीय देशराज बताते हैं, ''लॉकडाउन के बाद कंपनियों ने फोन पर करीब 4,000 जोड़ी जूतों के ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं. धंधा पहले से ही मंदा चल रहा था, ऊपर से यह कोरोना आ गया.'' उनके मन में बड़ी चिंता इस बात की भी है कि पता नहीं बाजार कब खुलेंगे? बाजार खुलने के बाद क्या व्यापार पुरानी रफ्तार से दौड़ सकेगा? पिछले भुगतान कहीं इस बंदी के बाद अटक तो नहीं जाएंगे? ये चिंताएं सिर्फ देशराज की नहीं, बल्कि देश के करोड़ों कुटीर, लघु और मझोले उद्योग मालिकों की हैं, जिन पर इस अप्रत्याशित बंदी की काफी मार पड़ी है. सबसे ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में उत्पादन, ट्रेड और सेवाओं से जुड़ी कुल 6 करोड़ 33 लाख से ज्यादा कुटीर, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) हैं, जो 11.10 करोड़ रोजगार मुहैया कराते हैं और देश की जीडीपी में 28.90 फीसद का योगदान करते हैं.

कपड़ा, चमड़ा, रत्न तथा आभूषण और वाहन उद्योग सघन श्रम वाले क्षेत्र हैं, जो बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया कराते हैं और लाखों छोटे उद्यमियों की शृंखला भी इससे जुड़ी होती है. अर्थव्यवस्था पहले से ही खपत घटने से मंदी की चपेट में थी और अब दुनियाभर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण से इन क्षेत्रों के संकट और बढ़े हो गए हैं.

त्रिपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के कार्यकारी सचिव एस. सक्तिवेल बताते हैं, ''टेक्सटाइल क्षेत्र की समस्याएं दो महीने पहले ही शुरू हो गई थीं.'' कपड़ा उद्योग में इस्तेमाल होने वाली कई ऐसी चीजें हैं जो चीन से आयात होती हैं, और आयात दो महीने से पूरी तरह ठप है. इसके बाद यूरोपीय संघ और अमेरिका में बड़े ब्रांड के स्टोर बंद होने के बाद कंपनियों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए, जिससे बड़ा झटका लगा.'' निटवियर मैन्युफैक्चरिंग के गढ़ त्रिपुर में 9,000 इकाइयां हैं, जिनकी निर्यात में 46 फीसद हिस्सेदारी है. सक्तिवेल कहते हैं, ''हालात जल्द नहीं सुधरे तो कई इकाइयां बंदी की कगार पर पहुंच जाएंगी.''

बुलियन ऐंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल कहते

कहां कितने छोटे उद्योग

देशभर में उत्पादन, सेवा क्षेत्र और व्यापार से जुड़े कुल छह करोड़ से ज्यादा कुटीर, लघु और मझोले उद्योग

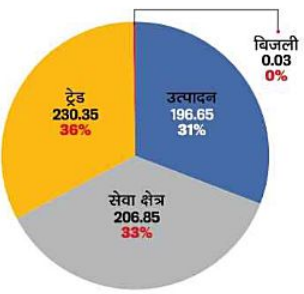

स्रोतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की 2018-19 की सालाना रिपोर्ट

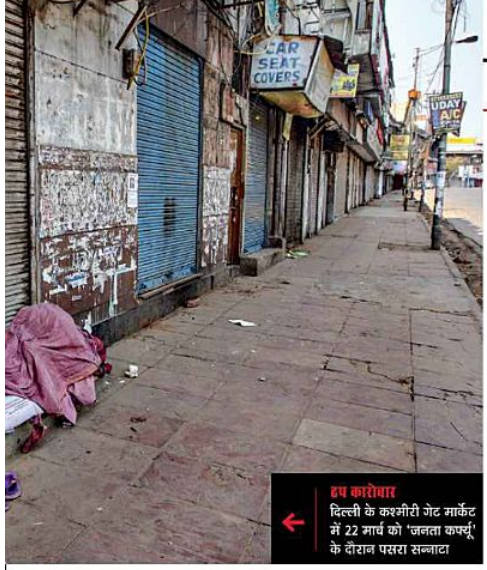

ठप कारोबार
दिल्ली के कश्मीरी गेट मार्केट में 22 मार्च को 'जनता कर्फ्यू' के दौरान पसरा सन्नाटा

हैं. ''कारोबार ठप है और खर्चे वहीं के वहां खड़े हैं. किराया, बिजली का बिल, वेतन और कर्ज की किस्त जस की तस है. अगर व्यापार होगा नहीं तो ये खर्चे व्यापारी को अपनी पूंजी तोड़कर पूरे करने होंगे. इस समय जरूरत यह है कि सरकार इन जरूरी खर्चों को चलाने के लिए छोटे उद्योगों को सहारा दे.'' वे बताते हैं, ''कोरोना संक्रमण का दौर खत्म होने के बाद भी जेम्स ऐंड जूलरी सेक्टर को पुरानी स्थिति में लौटने में एक साल तक लग जाएंगे क्योंकि गहनों की 80 फीसद मांग ग्रामीण क्षेत्र से आती है और गहने लोग सभी जरूरतें पूरी करने के बाद अंत में खरीदते हैं. मौजूदा संकट के बाद पूरे देश में लोगों की क्रय शक्ति तेजी से घटेगी, जिससे मांग और घट जा सकती है.''

तमिलनाडु लेदर टैनर्स एक्सपोर्टर्स ऐंड इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव पी.एम.आर. शम्सुद्दीन कहते हैं, ''व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हैं. ऐसे में कोरोना संक्रमण का दौर खत्म होने के बाद तमाम व्यापारियों को कारोबार शून्य से शुरू करना होगा.'' रिजर्व बैंक के बैंकों के कर्ज की किस्त टालने के फैसले पर वे कहते हैं, ''बंदी के दौरान छोटे उद्योगों को दिए गए कर्ज का ब्याज माफ होना चाहिए.'' उनका यह भी कहना है कि जब कारोबार पूरी तरह बंद हैं तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि छोटे उद्योगों के घाटे को कैसे कम किया जाए.

गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में 3,500 से ज्यादा फैक्ट्रियां है लेकिन फिलहाल जरूरी सामान बनाने वाली 15 इकाइयां ही चालू हैं. यहां बैग और थैले बनाने वाली एक कंपनी उतम फैशन के प्रबंध निदेशक देव त्यागी कहते हैं, ''दिल्ली-एनसीआर से बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन आने वाले दिनों में बड़ी समस्या बनकर उभरेगा.'' बंदी के बाद जब फैक्ट्रियों में काम शुरू होगा तो लेबर की कमी होगी. पहले से छोटे मार्जिन पर काम करने वाले लघु उद्योगों के लिए महंगी लेबर बड़ी समस्या होगी.'' मौजूदा परिस्थिति में छोटे उद्योगों को किस तरह सहारा दिया जा सकता है? वे कहते हैं, ''सरकार का जोर इस पर होना चाहिए कि घरेलू कंपनियां ज्यादा-से-ज्यादा उत्पादन करें. जब आयात पूरी तरह बंद है, तब ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, जो देश में ही विकल्प मुहैया करा सकते हैं.''

छोटे उद्योगों को बड़े सहारे की जरूरत है क्योंकि इनके बिना आर्थिक विकास की रफ्तार पटरी पर नहीं आ सकती है

देशभर के कारोबारियों की समस्याओं और अगली रणनीति के बारे में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं, ''सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में किसी तरह की कटौती से मना किया है, लेकिन कारोबार ठप रहे तो कर्मचारियों को तनख्वाह देना कठिन काम है.'' ऐसे में उनकी मांग है कि जब तक बंदी चलती है तब तक सरकार किसी ऐसे फॉर्मूले पर काम करे जिसमें वेतन का एक हिस्सा सरकार (50 फीसद), एक हिस्सा व्यापारी (25 फीसद) और बाकी कर्मचारी वहन करे. इसके अलावा हमारी मांग यह भी है कि बैंक के कर्ज, ओवरड्रॉफ्ट पर लगने वाले ब्याज और पेनॉल्टी इस अवधि के लिए माफ की जाए.''

बंदी के बाद की स्थिति से निपटने की तैयारी के बारे में खंडेलवाल कहते हैं, ''बंदी खत्म होने से ठीक पहले कैट व्यापारियों के बीच देशव्यापी सर्वे करेगा, ताकि हर तरह के व्यापारी की समस्या समझी जा सके और तय किया जा सके कि कारोबारी, सरकार और ग्राहक हर स्तर पर कैसे कदम जरूरी हैं.'' जाहिर है, हर व्यापारी के लिए बंदी के बाद का माहौल एक जैसा नहीं होगा.

देशव्यापी बंदी का सबसे भारी असर—होटल-रेस्तरां, विमानन, पर्यटन, सिनेमा हॉल जैसे सेवा क्षेत्र पर हुआ है. नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआइ) ने मॉल मालिकों से अपील की है कि बंदी के दौरान उन्हें किराए से राहत दी जाए. एनआरएआइ के अध्यक्ष अनुराग कटियार कहते हैं, ''हमारा बिजनेस मॉडल उच्च तय खर्चों वाला है. लेकिन जब कमाई शून्य है तो हमें अपने कारोबार को ही बचाए के लिए जूझना है.'' रेस्तरां उद्योग का आकार करीब चार लाख करोड़ रु. का है, जिसमें 70 लाख लोगों से ज्यादा लोग काम करते हैं.

वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल ऐंड मीडियम एंटरप्राइजेज (वासमे) के कार्यकारी सचिव संजीव लायक कहते हैं, ''कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन की सबसे बुरी मार छोटे उद्योगों पर पड़ी है.'' ये उद्योग ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करते हैं. इन इकाइयों को अगर तत्काल सहायता नहीं दी गई तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है. वे यह भी कहते हैं, ''भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से हाल में कर्ज के मोर्चे पर कुछ राहत का ऐलान किया गया है, लेकिन ये ऐलान समस्या की विकरालता के मद्देनजर नाकाफी हैं. छोटे उद्योगों को खड़े होने के लिए इससे ज्यादा की जरूरत है.'' इस बाबत वासमे ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए सुझाव दिए गए हैं. इन सुझावों में मुख्य तौर पर ब्याज, कर, बिजली का बिल, सैलरी जैसे तय खर्चों में राहत, केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों में फंसे भुगतानों को जल्द किया जाना, बिना शर्त सस्ती पूंजी मुहैया कराना वगैरह शामिल हैं. अब देखना है कि सरकार इन मामलों में क्या कदम उठाती है. ■

MAGAZINE KING

हेमंत चावला

आपदा के समय इंसाफ

वैश्विक महामारी में बदल चुके कोरोना का असर अदालतों पर ही पड़ना ही था. शीर्ष अदालत ने ऐसे में जरूरी मामलों में सुनवाई के लिए लिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा. अदालतों में स्थिति सामान्य होने में लगेगा लंबा वक्त

मनीष दीक्षित

रा

जधानी दिल्ली में जनता कर्फ्यू से बजी खतरे की घंटी के बाद सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के चैंबर सील हो गए, साकेत जिला न्यायालय भवन के बाहर मुकदमों की अगली तारीख की सूची चिपका दी गई ताकि कोई व्यक्ति अंदर न आ सके. इसके साथ ही 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई का शुभारंभ भी हो गया जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था. ये सब कदम उठाए गए कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए. कोरोना का कोर्ट पर असर यह है कि देश की सभी अदालतें बंद हैं और सिर्फ अत्यंत आवश्यक मामलों की ही सुनवाई निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में हो रही है. पूरे न्यायिक सिस्टम को थाम लेने वाले कोरोना लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिलेगा. फिलहाल, बेहद जरूरी मामले निपटाए जा रहे हैं.

छह महीने पिछड़ जाएगी अदालत

कोरोना वायरस के अदालत पर असर से पहले जजों और मुकदमों की स्थिति स्पष्ट कर लेना जरूरी है. संसद के बजट सत्र में सरकार ने बताया था कि हमारे देश में 10 लाख की आबादी पर 20 जज हैं. विधि आयोग ने 1987 में ही कहा था कि 10 लाख की आबादी पर 50 जज होने चाहिए. 2018-19 के आर्थिक सर्वे में कहा गया कि निचली अदालत का एक जज सालभर में औसतन 746 केस निबटाता है. लंबित तीन

वर्चुअल सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई. जज अपने घर पर और वकील अपने घर. 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट परिसर में

यह भी मिसाल दूर-दूर से सुनवाई

पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई जिसमें जज अदालत कक्ष में और वकील दूर किसी कमरे में बैठकर दलील दे रहे थे. 27 मार्च को दो बेंचों ने अदालत परिसर से बाहर सुनवाई की. न जज कोर्ट में थे न वकील. याची के वकील को ई-मेल पर वीडियो लिंक दिया जाता है जो सिर्फ उसी के लिए एक्टिव होता है.

ईमेल

फौरन सुनवाई की मेंशनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट का अलग से ई-मेल, केस का ब्योरा एक पेज से ज्यादा न हो.

फोन

मेंशनिंग ऑफिसर से तत्काल सुनवाई नामंजूर होने की हालत में सुप्रीम कोर्ट जजों के फोन नंबर दिए जिन पर वकील एक तय समय पर फोन कर अपना पक्ष रख सकते हैं

औपचारिकता हटी

कुछ हाइकोर्ट ने तकनीकी औपचारिकताएं घटाई हैं. बॉम्बे हाइकोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए केस दाखिल करने के वक्त हलफनामा या कोर्ट फीस की अनिवार्यता खत्म कर दी है. सादे कागज पर अर्जी को भी सुना जाएगा.

लंबित मुकदमों का अंबार

सुप्रीम कोर्ट
60 हजार से ज्यादा

हाइकोर्ट 25
पेंडिंग केस 46.43 लाख
(सिविल 19.3 लाख, रिट-13.7 लाख, क्रिमिनल 13.3 लाख)

जजों की संख्या
684
स्वीकृत संख्या 1,079 (भारत सरकार के न्याय विभाग के मुताबिक 1 मार्च, 2020 तक)

निचली अदालतों में पेंडिंग केस 3.21 करोड़

- पेंडिंग क्रिमिनल केस 3.21 करोड़
- एक साल से ज्यादा पुराने केस 2.36 करोड़
- जिला और तहसील अदालतों की संख्या 3,219
- निचली अदालतों में जज कार्यरत 19,160
- मंजूर पद 24,018
- खाली 4,558 (संसद प्रश्नोत्तर)
- कंप्यूटराइज्ड कोर्ट 16,845

स्रोतः संसद प्रश्नोत्तर; नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड; न्याय विभाग-कानून मंत्रालय

MAGZINE KING

करोड़ मुकदमों (देखें ग्राफिक्स) का ढेर पांच साल में निबटाने के लिए 8,152 जजों की जरूरत होगी. नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक, देश में कुल लंबित मामलों में से 74 फीसद से ज्यादा आपराधिक मामले हैं. लॉकडाउन के दौरान कोर्ट भले ही बंद हों पर मुकदमे दाखिल होना बंद नहीं हुआ है. कुछ कोर्टों में ई-फाइलिंग भी हो रही है.

जाने-माने वकील और राज्यसभा सांसद के.टी.एस. तुलसी कहते हैं, ''लॉकडाउन से न्याय की गति पर गहरा असर पड़ेगा. कोर्ट 14 अप्रैल को खुली तो भी हम छह से आठ महीने पीछे हो जाएंगे. हर केस इतना पीछे चला जाएगा. और लॉकडाउन बढ़ा तो हम साल भर पीछे चले जाएंगे. अदालत की एक-एक तारीख का बहुत असर पड़ता है. वायरस के प्रकोप में किसी को यह नहीं मालूम कि अगले हफ्ते क्या होगा. पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं. लॉकडाउन बढ़ा तो बहुत मुश्किल होगी.''

एक तबके का तर्क अलग है. इलाहाबाद हाइकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस.आर. सिंह का मानना है कि लंबित मामले उस तादाद में नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा केस दाखिल ही नहीं हो रहे. ''केस निबटाने के लिए छुट्टियां कम की जा सकती हैं. इलाहाबाद हाइकोर्ट में 210 दिन काम होता है पर इसे बढ़ाया जा सकता है ताकि काम जल्दी निबटे.'' सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की राय में, ''पांच सौ से ज्यादा मामले संविधान पीठ के सामने लंबित हैं. ये निबट जाएं तो हाइकोर्ट और निचली अदालतों के तमाम मामले जल्द निबट जाएंगे.'' अभी जस्टिस सिस्टम में ट्रेन जैसा हाल हो जाएगा: जो लेट हुई, और लेट होती जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के एक और वकील डी.के. गर्ग इसमें अपना पक्ष यूं जोड़ते हैं, ''हर कोर्ट में रोज 4-5 नए केस आते हैं, शुक्रवार को कम से कम 30-40 केस लगते हैं. सुप्रीम कोर्ट 7 मार्च से बंद है. पेंडेंसी देखी जाए तो 3,000-4,000 केस बढ़ेंगे. कोर्ट 14 अप्रैल को खुलने पर अर्जेंट केस चीफ जस्टिस की कोर्ट में लगेंगे. उनका एक घंटा इन्हीं में लगेगा. यानी दो जजों का एक घंटा रोज बर्बाद होगा. फिर गर्मी की छुट्टियां आ जाएंगी, हो सकता है ये टल भी जाएं, तो भी काम का बोझ तो रहेगा. कुल मिलाकर जस्टिस सिस्टम छह महीने पीछे चला गया. बंदी 15 दिन भी बढ़ी तो जो केस 2020 में तय होना है, समझिए कि वह 2021-22 में ही निबटेगा.'' वकीलों की दलील है कि जब इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या अस्पताल काम कर रहे हैं तो कोर्ट क्यों न करे.

उपाध्याय का मानना है कि साल में 185 दिन काम करने वाले सुप्रीम कोर्ट में लॉकडाउन के दौरान भी काम होना चाहिए. पर गर्ग सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा छुट्टियों को जायज ठहराते हैं. ''देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हजारों निचली अदालतों समेत सभी हाइकोर्ट के लिए नजीर होते हैं इसलिए उनमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए. उसमें भारतीय कानूनों की भी व्याख्या होगी और विदेश के कानूनों की भी. कई मामले जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं उनमें क्वालिटी ऑफ जस्टिस दिखना चाहिए. अगर इनमें कोई चूक हुई तो इन फैसलों की व्याख्या करने वाली अदालतें मनमाने ढंग से इनकी व्याख्या कर सकती हैं. न्याय की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को ज्यादा छुट्टियां मिलनी चाहिए.''

कैदी छोड़ना ठीक

कैदियों को छोड़ने वाले अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की 1,339 जेलों में इस वक्त करीब 4.66 लाख कैदी हैं और इनमें खासी तादाद विचाराधीन कैदियों की है. कोर्ट उन कैदियों को जमानत और पैरोल पर रिहा करने का आदेश दे चुकी है जो बेवजह बंद हैं और उनके अपराधों में सात साल से कम सजा

का प्रावधान है.

तुलसी और गर्ग कहते हैं कि पहले भी विचाराधीन कैदियों को जमानत देने का आदेश अदालत दे चुकी है. लेकिन इतनी बड़ी आपदा के दौरान सरकार के लिए भी इतने ज्यादा कैदियों की देखरेख मुश्किल थी. इलाहाबाद हाइकोर्ट ने अग्रिम जमानतों और जमानतों को बढ़ा दिया है. इस मुद्दे पर तुलसी का तर्क है कि हर किसी को जल्द से जल्द न्याय पाने का हक है और उस लिहाज से यह फैसला उचित ही है. गर्ग याद दिलाते हैं कि पहले के आदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था: किसी व्यक्ति को अनंत काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता.

तकनीक का पहली बार इस्तेमाल

सुप्रीम कोर्ट इन दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आवश्यक मुकदमों की सुनवाई कर रहा है. हालांकि इसकी मांग काफी पहले से की जा रही थी. सवाल यह है कि क्या कोरोना लॉकडाउन के बाद भी यह जारी रहेगा? तुलसी कहते हैं, ''सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो कदम उठाया है वह जारी रहना चाहिए. इस तकनीक को पूरी तरह अपनाने का वक्त आ गया है. अगर कोई वकील मद्रास में बैठकर बहस कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है तो ऐसा क्यों न किया जाए? इतनी दूर से एक-एक केस के लिए गरीब आदमी आ ही नहीं सकता. वकील भी बहुत महंगे हैं. तकनीक न्याय की रफ्तार बढ़ाने में मददगार होगी.''

सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता मामले में एक दिलचस्प पहलू जोड़ते हैं: ''देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट न तो बंद है और न ही खुला है. सरकारी आदेश और कोर्टों की व्यवस्था के बीच का जो संकट है उसमें केवल सांकेतिक तौर पर अदालत चल रही है. काम रोकना न पड़े, इसका समाधान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के रूप में आया है. न्यायपालिका को अपने आपको तकनीकी क्रांति से लैस करना पड़ेगा. कछुए की चाल से चल रहे सिस्टम में इससे रफ्तार आएगी. इसे लॉकडाउन के बाद भी जारी रखना चाहिए.''

सुप्रीम कोर्ट के ही वकील ज्ञानंत सिंह लॉकडाउन के अच्छे पहलुओं की ओर इशारा करते हैं: ''न्यायपालिका की सबसे बड़ी समस्या टेक्नोलॉजी को ठीक से न अपना पाने की थी. मजबूरी में ही सही व्हाट्सऐप या अन्य माध्यमों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होने लगी है. इससे पेंडेंसी भी घटेगी. मुल्जिम को जेल से अदालत तक ले जाने में संसाधनों की बर्बादी होती है. रुटीन केसों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनाई गई तो दूसरे शहरों की जेलों में बंद कैदियों को लाकर पेश करने का झंझट खत्म होगी.'' सुप्रीम कोर्ट से पहले पटना हाइकोर्ट ने 18 मार्च को वर्चुअल कोर्ट शुरू कर दी थी. कोरोना लॉकडाउन से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? न्यायिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन दक्ष के प्रोग्राम डायरेक्टर सूर्यप्रकाश बी.एस. कहते हैं, ''इसकी वजह वकीलों और जजों का तकनीक के बारे में न सोचना है. दक्ष की स्टडी कहती है कि न्यायिक प्रशासन के लिए जज के पास टाइम नहीं है.'' वे बताते हैं, निचली अदालतों में कामकाज के लचर रवैये के चलते वादियों को उत्पादकता या वेतन का जो नुक्सान होता है वह देश की जीडीपी का आधा प्रतिशत से ज्यादा होता है. रकम में देखें तो यह 50,000 करोड़ रु. से

लॉकडाउन से न्याय की रफ्तार पर असर पड़ेगा. अदालत 14 अप्रैल को खुली तो भी हम 6-8 महीने पीछे हो जाएंगे. और लॉकडाउन बढ़ा तो हालात सामान्य होने में साल भर से भी ज्यादा लग जाएगा

एक लाख करोड़ रु. के बीच बैठती है. इसलिए निचली अदालतों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी तकनीकी व्यवस्थाएं ज्यादा जरूरी हैं.

वकीलों पर असर

अगर हम सिर्फ दिल्ली की बात करें तो यहां सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट के अलावा आधा दर्जन निचली अदालतें, एनसीएलटी, लेबर कोर्ट, अनेक ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर कोर्ट आदि हैं और लॉकडाउन से इन सभी जगह प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को बहुत नुक्सान उठाना पड़ रहा है. इस पर तुलसी कहते हैं, ''99 फीसद वकील हैंड टु माउथ हैं. वे किराया नहीं दे पा रहे, रोजमर्रा के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे. वकीलों के लिए बार एसोसिएशन और सरकार को जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए, मोटे अनुमान के मुताबिक, देश में करीब 17 लाख वकील हैं और इनमें से एक लाख तो अकेले दिल्ली-एनसीआर में ही हैं.'' वकीलों ने बार काउंसिल और केंद्र और राज्य सरकार से मदद मांगी है.

सुनवाई फिलहाल अहम मामलों की

सवाल उठता है कि लॉकडाउन के दौरान जनता को न्याय मिलेगा कैसे? जिसका केस चल रहा है उसे तो पता है कि 15 दिन में फैसला आना नहीं है. लोग लॉकडाउन में भी गिरफ्तार हो रहे हैं और जमानत पर छूट भी रहे हैं. इस पर स्थिति साफ करते हुए ज्ञानंत सिंह कहते हैं, ''बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे बेहद महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो ही रही है. हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से जुड़े मामले भी फौरन सुने जा रहे हैं क्योंकि इन्हें बाद में नहीं सुना जा सकता. जमानत और हिरासत से जुड़े मामलों की सुनवाई निचली अदालतों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में हो रही है. निचली अदालतों में वही व्यवस्था लागू है जो छुट्टी के दिनों में होती है.''

फिलहाल अर्जेंट मैटर ही सुने जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट और कई हाइकोर्ट ने जो अंतरिम आदेशों की तारीखें बढ़ा दी हैं, इससे उस शख्स को फायदा होगा जिसके पक्ष में वह अंतरिम आदेश था. ज्ञानंत सिंह के मुताबिक, खासकर वित्त से जुड़े मामलों में फायदा हो जाएगा. हालांकि अंतरिम आदेश भी पर्याप्त आधार के बगैर नहीं मिल जाता. जैसे किसी कंपनी की डिमांड आई और कोर्ट से स्टे हो गया तो दूसरी पार्टी को भी नोटिस गया लेकिन उसकी तारीख पर कोर्ट बंद है तो इससे उसे फायदा हो गया जिसे स्टे मिला है. लेकिन ऐसा चुनिंदा मामलों में ही होता है. वकील एक और अंदेशा जताते हैं कि जिन मुकदमों की तारीख लगी थी उन्हें अपने आप आगे बढ़ा दिया गया. इसका फायदा घोटालों के आरोपी सुबूत मिटाने के रूप में उठा सकते हैं. लिहाजा अदालत को इस मामले में सतर्क रहने की जरूरत है.

सवाल उठता है कि अब किसी को अगर अपने मुकदमे की अगली तारीख जाननी है तो वह क्या करे? कैसे इसका पता करे? ज्ञानंत सिंह इसका सीधा-सा उपाय सुझाते हैं, वह यह कि ई-कोर्ट सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर मुकदमे की अगली तारीख जानी जा सकती है. यह बात बिल्कुल सच है कि लंबे समय बाद जब कोर्ट खुलेंगे तो नए मुकदमों का अंबार लग जाएगा. लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जो पाबंदियां लगाई गईं वे भी जरूरी हैं. रिटायर्ड जस्टिस एस.आर. सिंह साफ कहते हैं, ''जिंदगी रहेगी तो अदालतों का भी कोई मकसद है, वरना क्या फायदा. लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं था. यह व्यापक जनहित का मामला है.'' ■

मनीष अग्निहोत्री

मुस्तैद
लखनऊ के गोमतीनगर में सीएम हेल्पलाइन का दफ्तर

MAGAZINE KING

चौबीसों घंटे चौकन्ने

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन कोरोना के खिलाफ जंग में भरोसेमंद 'हथियार' बनकर उभरा. योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे इसकी निगरानी

आशीष मिश्र

कानपुर के ईश्वरीगंज ग्रामपंचायत के युवा प्रधान आकाश वर्मा 27 मार्च की शाम अचानक अचरज में पड़ गए जब उनके मोबाइल पर 1076 नंबर से कॉल आई. कहीं इस कॉल को उठाने से मोबाइल का बैलेंस न कम हो जाए इसलिए पहली बार तो आकाश ने फोन नहीं उठाया. दोबारा कॉल आने पर डरते-डरते आकाश ने फोन उठाया तो पता चला कि यह सीएम हेल्पलाइन की कॉल है. हेल्पलाइन की तरफ से कॉल करने वाली युवती ने आकाश से उनके गांव में दूसरे प्रदेश और विदेश से आने वालों की जानकारी मांगी. आकाश बताते हैं, ''मुझे पता था कि 1076 सीएम हेल्पलाइन नंबर पर केवल फोन करके अपनी समस्या ही बताई जा सकती लेकिन यह नहीं पता था कि इस नंबर से कॉल भी आ सकती है.'' यह एक नई व्यवस्था है. पिछले वर्ष अप्रैल में जनता की शिकायतें सुनने और उनके निराकरण के लिए तैयार किया गया 'इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम' (आइजीआरएस) मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के साथ संबंद्ध होकर अब कोरोना से निबटने के लिए प्रदेश सरकार के पास एक मजबूत 'हथियार' बनकर उभरा है.

लखनऊ में लोकभवन से सात किलोमीटर दूर विभूति खंड में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने मौजूद साइबर टावर बिल्डिंग के पांचवें और छठे तल पर 1,076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का कॉल सेंटर चल रहा है. देश के सबसे बड़े इस सरकारी हेल्पलाइन में कुछ 1,020 ऑपरेटर चौबीस घंटे लोगों की समस्याओं के निबटारे और उनकी निगरानी के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं. इस कॉल सेंटर में तीन शिफ्ट में काम होता है. 500 ऑपरेटर सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक और इतने ही ऑपरेटर दोपहर तीन से रात 11 बजे तक अपनी सेवाएं देते हैं. रात 11 से सुबह सात बजे तक 20 ऑपरेटर मौजूद रहते हैं. कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद जैसे ही प्रवासी लोग यूपी पहुंचने लगे, इनकी निगरानी के लिए सीएम हेल्पलाइन की ही मदद ली गई. मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव आलोक कुमार सीएम हेल्पलाइन के प्रभारी हैं. हेल्पलाइन में आने वाली सभी प्रकार की सूचनाओं पर वे अपने दफ्तर के कंप्यूटर के

जरिए नजर रखे हुए हैं. आलोक कुमार बताते हैं, ''सीएम हेल्पलाइन के जरिए हमने प्रदेश की सभी 60,000 ग्राम पंचायतों के प्रधान और सभी सभासदों को फोन करके उनसे उनके इलाके में आई प्रवासी जनसंख्या के बारे में जानकारी जुटाई है. इसके अलावा उन लोगों के बारे में भी जानकारी ली है जिन्हें कोरोना से मिलते-जुलते लक्षण प्रकट हुए हैं. '' सीएम हेल्पलाइन को 108 एंबुलेंस सेवा और पुलिस की डायल-112 से भी सीधे जोड़ दिया गया है. सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) अभिषेक कौशिक बताते हैं, ''सीएम हेल्पलाइन को अगर किसी मरीज के बारे में सूचना मिलती है तो तुरंत संबंधित जिले के सीएमओ और एंबुलेंस सेवा को एलर्ट कर दिया जाता है. इसके बाद चिकित्सकों का एक दस्ता उक्त मरीज की जांच करने भेजा जाता है.'' हेल्पलाइन के जरिए भी चिकित्सकीय परामर्श देने के लिए साइबर टावर स्थित सीएम हेल्पलाइन के दफ्तर में तीनों शिफ्ट में दो-दो डॉक्टर तैनात किए गए हैं.

पहले राउंड में सीएम हेल्पलाइन के जरिए सभी जिलों के गांवों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले उन लोगों की सूची तैयार कर ली गई है जो सर्दी-खांसी से पीड़ित हैं. दूसरे चरण में सभी प्रधानों और सभासदों को फोन करके प्रवासी लोगों के भरण-पोषण और उनके स्वास्थ्य की निगरानी करने को कहा जा रहा है. आलोक कुमार बताते हैं, ''हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि सीएम हेल्पलाइन पर सूचना मिलने के तीन घंटे के भीतर ही जरूरतमंद के पास सरकारी मदद पहुंच जाए, '' यहां प्राथमिकता के तौर पर उन लोगों को बतौर ऑपरेटर नौकरी दी गई है जो दिव्यांग हैं या फिर महिलाएं. इन सभी ऑपरेटर की रोज मेडिकल जांच के साथ इनके आने-जाने और भोजन का प्रबंध सरकार स्वयं कर रही है. हेल्पलाइन की व्यवस्था देखने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने 2013 बैच के दो आइएएस अफसर सत्येंद्र कुमार और रमेश रंजन को सीएम हेल्पलाइन के दफ्तर में तैनात किया है. मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात विशेष सचिव अविनाश कुमार हेल्पलाइन की गतिविधियों पर नजर रखने में सचिव आलोक कुमार की मदद कर रहे हैं.

कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे से निबटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं. मुख्यमंत्री ने सरकार के 11 अफसरों की निगरानी में कमेटी गठित की है जो कोरोना से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर अपना काम करेंगी (देखें ग्राफिक्स). अपर मुख्य सचिव, गृह और सूचना विभाग अवनीश कुमार अवस्थी हर शाम चार बजे लोकभवन के मीडिया सेल में मौजूद होते हैं और सरकार के कार्यों की जानकारी देते हैं. अवस्थी बताते हैं, ''सरकार के हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है. इन सबकी निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं.'' अधिकारियों के कामकाज की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उन 11 अधिकारियों के साथ नियमित बैठक कर रहे हैं जो अलग-अलग कमेटी के प्रभारी हैं. इसके लिए लखनऊ के 5 कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के दाहिनी ओर बने बड़े हॉल को एक मीटिंग रूम में तब्दील कर दिया गया है. यहां पर अधिकारी 'सोशल डिस्टेंसिंग' का प्रोटोकॉल मानते हुए मुख्यमंत्री के साथ बैठक करते हैं. मुख्यमंत्री आवास के भीतर एक कक्ष में दूसरे जिलों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए टीवी स्क्रीन और कैमरे की व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री अपने कार्यालय के प्रमुख सचिव

कोरोना से निबटने निकली योगी की टीम 11

1 आर.के. तिवारी यूपी के मुख्य सचिव और 1985 बैच के आइएएस अफसर. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समन्वय कमेटी में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन सदस्य हैं. यह भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर समन्वय स्थापित कर रही है

2 आलोक टंडन यूपी के औद्योगिक विकास आयुक्त के पद पर तैनात. 1986 बैच के आइएएस अफसर हैं. इनकी अध्यक्षता में बनी कमेटी में प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, श्रम एवं सेवायोजन सदस्य हैं. इनका कार्य प्रदेश की औद्योगिक व व्यावसायिक इकाइयों में काम करने वाले कार्मिकों (नियमित, दैनिक वेतन, संविदा पर) को बंदी के दौरान पूर्ण वेतन, मानदेय सुनिश्चित कराना है

3 आलोक सिन्हा कृषि उत्पादन आयुक्त. 1986 बैच के आइएएस अफसर. इनकी अध्यक्षता में बनी कमेटी के जिम्मे आवश्यक सामग्री एवं वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए जनपदों से समन्वय स्थापित करना है. होम डिलिवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं यथा दूध, सब्जी एवं राशन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी इनकी कमेटी के ही जिम्मे है

4 अवनीश कुमार अवस्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी अधिकारियों में शुमार वर्ष 1987 बैच के आइएएस अधिकारी अवनीश कुमार यूपी में गृह और सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इनकी अध्यक्षता में बनी एन्फोर्समेंट की कार्रवाई की समीक्षा और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है

5 रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग के पद पर तैनात. 1987 बैच की आइएएस अफसर. इनकी अध्यक्षता में बनी कमेटी प्रदेश स्तर पर एवं सभी जनपदों में कंट्रोल रूम की स्थापना व नियमित रूप से उनके कार्य की समीक्षा करने के साथ यह भी सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी व्यक्ति की जिज्ञासा व अनुरोध सही अधिकारी व विभाग तक अवश्य पहुंच जाए

MAGZINE KING

अमित मोहन प्रसाद प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के पद पर तैनात. 1989 बैच के आइएएस अफसर. इनकी कमेटी का काम अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, दवाइयों एवं मास्क आदि की व्यवस्था, होम क्वारंटीन के अतिरिक्त अस्पतालों में क्वारंटीन की सुविधा विकसित करना, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत करना है

6

संजीव मित्तल अपर मुख्य सचिव वित्त के पद पर तैनात 1987 बैच के आइएएस अफसर. इनकी अध्यक्षता में बनी कमेटी का कार्य कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन तथा भविष्य की रणनीति तैयार करना है. इस कमेटी में सदस्य के तौर कृषि/उद्यान, गन्ना विकास और उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव हैं

7

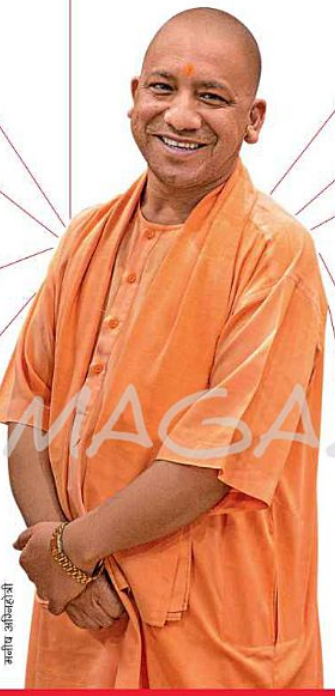

8

देवेश चतुर्वेदी 1989 बैच के आइएएस अधिकारी देवेश चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव कृषि के पद पर तैनात हैं. यह कमेटी किसानों की फसल जैसे गेहूं, आलू, सरसों इत्यादि के प्रभावी खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी. किसानों से जुड़ी योजनाओं के पालन में आने वाली दिक्कतों को दूर करना और पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करना भी इनके जिम्मे है

मनीष अग्निहोत्री

हितेश चंद्र अवस्थी पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी 1985 बैच के आइपीएस अफसर हैं. इनकी कमेटी के जिम्मे जेलों, ट्रेनिंग सेंटर और पीएसी बटालियन में साफ-सफाई सुनिश्चित कराना, पीएसी बटालियन एवं ट्रेनिंग सेंटर में तैनात फोर्स को रिजर्व के रूप में तैयार करना है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फील्ड में तैनात किया जा सके

9

10

एस.पी. गोयल मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात प्रमुख सचिव एस.पी. गोयल 1989 बैच के आइएएस अफसर हैं. मुख्यमंत्री के निर्णयों को तुरंत संबंधित विभागों तक पहुंचाकर उन्हें लागू करवाने और फॉलोअप की जिम्मेदारी इन पर है. लॉकडाउन की स्थिति में बेरोजगार हुए श्रमिकों के लिए भरण-पोषण भत्ता से जुड़े नियम-कानून बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

भुवनेश कुमार 1995 बैच के आइएएस अफसर. प्रमुख सचिव पशुधन के पद पर कार्यरत हैं. इनकी अध्यक्षता में बनी कमेटी का कार्य पशुओं के चारे की व्यवस्था तथा आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराना है. इसके अलावा, आवारा पशुओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का पूरी तरह से पालन कराना भी इनके जिम्मे है

11

एस.पी. गोयल और मुख्य सचिव आर.के. तिवारी के जरिए जिलाधिकारियों के कामकाज पर नजर रखे हुए हैं.

दिल्ली से यूपी की सीमा में दाखिल हो रहे प्रवासी मजदूरों के लिए जरूरी इंतजाम न करने की जानकारी मुख्यमंत्री को 28 मार्च को ही मिल गई थी. एक अधिकारी बताते हैं, ''नोएडा में जब प्रवासी मजदूरों की भीड़ बढ़नी शुरू हुई तो जिलाधिकारी बी.एन. सिंह फौरन हरकत में नहीं आए. उन्होंने समय-समय पर शासन को जरूरी सूचनाएं नहीं पहुंचाई. जब भीड़ बहुत बढ़ गई तो उसके लिए भी नोएडा के पूर्व जिलाधिकारी ने कोई चुस्ती नहीं दिखाई.'' नोएडा में 30 मार्च को समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बी.एन. सिंह को जमकर फटकार लगाई. मुख्यमंत्री के जाते ही उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नोएडा के जिलाधिकारी का पद छोड़ने की इच्छा जता दी. शाम होते ही 2007 बैच के आइएएस अधिकारी सुहास एल.वाइ. को नोएडा का जिलाधिकारी बना दिया गया. 31 मार्च सुहास ने नोएडा के डीएम का चार्ज ग्रहण कर लिया.

लखनऊ में विधानभवन के सामने मौजूद लोकभवन कोरोना से निबटने में लगे अधिकारियों का केंद्र बन चुका है. अपने कार्यालय से सटे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष के जरिए मुख्य सचिव आर.के. तिवारी लगातार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क में हैं. लोकभवन के सी ब्लॉक के पांचवें तल पर अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश कुमार अवस्थी बैठते हैं. इनके कक्ष के ठीक सामने कमांड सेंटर है जहां से प्रदेश की कानून-व्यवस्था से जुड़ी हर छोटी हरकत पर नजर रखी जा रही है.

कोरोना संक्रमण से निबटना सरकार के लिए अभूतपूर्व चुनौती है. इसका सफलता पूर्वक सामना करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगे के लिए एक सक्षम अधिकारियों की टीम भी मिल जाएगी. ■

स्मृति/ सतीश गुजराल: शांत और ओजस्वी
पेज 65

फुरसत

सवाल-जवाब/मनीषा कोइराला: अब नए प्लेटफॉर्म पर नायिका
पेज 66

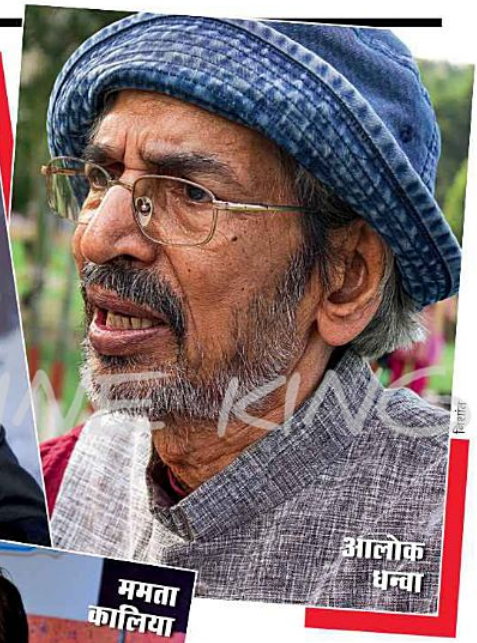

MAGAZINE KING

साहित्य

करो न दिल की बात

वैश्विक महामारी ने साहित्यिकों की संवेदना को भी झकझोरा. उनकी राय में कोरोना के असर ने रचनाओं की जमीन को हमेशा के लिए बदल डाला

हरियाणा और दिल्ली की ओर से सिर पर गठरी और गोद में बच्चे चिपकाए, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर कतारों में चले जा रहे प्रवासी मजदूर कथाकार ममता कालिया को 1946 की याद दिला रहे थे, जो गाजियाबाद में उसी के किनारे एक सोसाइटी में रहती हैं. ''उस वक्त बंटवारा हुआ नहीं था लेकिन चारों तरफ उसकी तैरती चर्चाओं से ही एक माहौल बन गया था. पाकिस्तान की ओर से हिंदुओं को मैंने इसी तरह झुंड में आते देखा था.

कोरोना महामारी ने जिस तरह दुनिया को धीरे-धीरे अपनी कुंडली में लपेटा है, उससे महाशक्तियों के मुंह से भी झाग आने लगा है. कोरोना वायरस मनुष्यों के फेफड़ों में पानी भर रहा है, दूसरी ओर खासकर लेखकों-रचनाकारों की सोच के कैनवास को बुनियादी स्तर पर बदले दे रहा है. ''यह तृतीय विश्वयुद्ध है,'' ''यह चीन का शक्ति परीक्षण है,'''''यह (मजदूरों का बहिर्गमन) कोरोना से ज्यादा सरवाइवल का मुद्दा है'' जैसी टिप्पणियां लेखकीय बिरादरी में सुनी जा सकती हैं. मराठी में दलित चेतना के बड़े लेखक शरण कुमार लिंबाले रहते पुणे में हैं. 22 मार्च को जनता कर्फ्यू से एक दिन पहले ही वे शोलापुर (महाराष्ट्र) में अपने मूल गांव हन्नूर गए थे, तब से वहीं फंसे हैं. फोन पर पीछे से आती मुर्गों की बांग के बीच वे थोड़ा अनमने-से कहते हैं, ''कोई किताब भी नहीं लाया था. खाली हाथ. अपने भीतर के लेखक के बारे में तो क्या ही बताऊं! मैं शून्य मानसिकता में पहुंच गया हूं. कुछ सूझ ही नहीं रहा.''

यह त्रासदी लेखकों को भी साहित्यिक स्मृतियों में उतरने और क्लासिक्स को खंगालने का मौका दे रही है. पटना में एकांत में जी रहे हिंदी के 72 वर्षीय कवि-चिंतक आलोक धन्वा शरत्चंद्र के वृहद उपन्यास *श्रीकांत* का जिक्र करते हैं, जिसमें पिछली सदी के दूसरे दशक में बंगाल में फैले प्लेग का वर्णन है, ''उसमें एक जगह लिखा है कि लोग गांव में एक लाश दफनाकर लौटते और पीछे 3-4 तैयार मिलतीं...पूर्वी उत्तर प्रदेश में खुद मेरे बाबा भी प्लेग से मरे थे. 100-100 गांव एक कतार से साफ हो गए थे, ऐसा बताया गया.'' कालिया इस कड़ी में *श्रीकांत* के अलावा श्रीनरेश मेहता के उपन्यास उत्तर कथा को जोड़ती हैं जिसमें साठ के दशक के हैजे का कारुणिक चित्रण है. उसमें एक मां ससुराल से आई बेटी को दूर से ही ड्योढ़ी पर रोककर वापस भेज देती है. उसकी सोच यह है कि घर में फैला हैजा उसे भी न अपनी जद में ले ले.'' उसी से जोड़कर जरा आज के दृश्यों को देखें, जहां अपने गांव-जवार में वापस पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों को गांव की देहरी पर रोका और शक की नजर से देखा जा रहा है कि कहीं उनमें कोरोना वायरस का संक्रमण तो नहीं है.

क्या इस तरह की भीषण बीमारियों के पेट में भविष्य के लिए उम्मीद की कोई चमक भी होती है? क्या इसमें ऐसा कुछ निहित होता है जो इनसानी उद्यमशीलता को चैलेंज करे? उसे और आगे धकेले? लिंबाले इन जिज्ञासाओं को भीतर समेटकर तर्क को एक नई दिशा देते हैं और अपनी रचनाओं की तरह ही थोड़ा जोखिम उठाते हुए कहते हैं, ''नई-नई बीमारियां आनी ही चाहिए. ये चुनौतियां आएंगी तो मनुष्य उनसे निबटने की तैयारी करेगा. उसकी कल्पना, सोच और उद्यमशीलता को नए पंख लगेंगे. विज्ञान की राह में भी वे नए दरवाजे खोलेंगे.'' लिंबाले के कहे में थोड़ा तंज भी है. वह यह कि पर्यावरण हो या फिर यातायात, मनुष्य अपने आराम और अय्याशी के लिए किसी क हक्श नहीं रहा. यह भी जब शांति रहती है तो पाकिस्तान ही सबसे बड़े दुश्मन के रूप में खड़ा रहता है, कोरोना सरीखा संकट आने पर इनसान और इनसानियत की फिक्र की जाने लगती है. सियासत भी उस बीच काल्पनिक और गढ़े गए दुश्मनों से तौबा किए रहती है.

लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वक्त की जरूरत होने के बावजूद लेखकों की बिरादरी ख्याली तौर पर ही सही, इसमें थोड़ा पोएटिक रियायत लेती है. कोई फिराक (गोरखपुरी) का शेर याद करता है:

यारो बाहम गुंधे हुए हैं कायनात के बिखरे टुकड़े,
इक फूल को जुंबिश दोगे तो इक तारा कांप उठेगा.
कोई गालिब के दर्द से खुद को जोड़ता है
मुश्किलें मुझ पर पड़ीं इतनी कि आसां हो गईं.

धन्वा कहते हैं कि सृष्टि में ज्यादा दिनों के लिए आइसोलेशन संभव नहीं. ''प्रकृति के खिलाफ बैठता है यह सब. मां-बेटी-बहन-भाई-पिता. त्रासदी बड़ी जरूर है और हमें जरूरी एहतियात बरतना ही चाहिए, पर ऐसे रिश्तों के लोग कब तक दूर रह सकते हैं.'' कोरोना की त्रासदी के दौरान आपस में दूरियों का पालन करने के पीछे दूसरी ज्यादा मानवीय वजहें हैं. डर उन्हीं में से एक है. ''लिंबाले बताते हैं कि ''हमारे यहां गांव में लोग खासे डरे हुए हैं. हर किसी को स्वाभाविक तौर पर जान की फिकर है. दुनिया में इसके कहर को देखते हुए मीडिया ने भी लोगों को जागरूक करने में बड़ा रोल निभाया है.''

एक प्रेमकथा के 22 पन्ने लिखकर छोड़ देने वालीं कथाकार ममता कालिया कहती हैं कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई.

लेकिन इस त्रासदी ने मानवीय संवेदनाओं को जिस तरह से झंझोड़ा है, उससे रचनात्मकता की दिशा और उसकी जमीन भी बदलने वाली है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं. कालिया कहती हैं, ''मैंने एक प्रेम कहानी लिखनी शुरू की थी. 22 पन्ने लिख भी लिए थे. लेकिन अब तो उसकी अकाल मृत्यु हो गई. इतने निगेटिव समय में पॉजिटिव कोई कैसे लिखेगा भला? हां संस्मरण वगैरह लिखना आसान है, जिसमें हृदय की भावनाओं वाली बात न आए. कविता की पंक्ति है ना लहर छूने से सलिल को क्लेश होता है. तो अब हंगरी पर एक संस्मरण शायद पूरा हो जाए. देखिए न! विभाजन पर अभी तक भी मार्मिक कहानियां आ रही हैं. हाल के नया ज्ञानोदय के अंकों में ऐसी दो कहानियां छपी हैं. उसी तरह से श्रमिकों का यह जो बहिर्गमन हुआ है, उस पर भी अगले 30-40 साल तक कहानियां आती रहेंगी.''

धन्वा इस त्रासदी को दो तरह से देखते हैं. उनका कहना है कि ''अगर यह सचमुच सृष्टि को खत्म करने आई है, जैसा कि विश्वयुद्ध में होता था, तो यह समझिए कि यह विश्वयुद्ध से भी खतरनाक है. दूसरे, सारे उपक्रम बंद हैं. यह सिलसिला लंबा चला तो डिप्रेशन शुरू हो जाएगा. वह भी हमारी सबसे बड़ी आबादी युवाओं के दिमाग में. क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है. उनके भीतर यह भय बैठेगा कि अब उनका क्या होगा!'' यानी साहित्यिकों के हलके में कोरोना पर बहस लंबी चलेगी. –शिवकेश

सतीश गुजराल 1925-2020

शांत और ओजस्वी

बीती 26 मार्च को 94 वर्ष की उम्र में दिवंगत चित्रकार सतीश गुजराल को याद कर रहे हैं उनके दोस्त कृष्ण खन्ना

सतीश गुजराल के साथ मेरी दोस्ती जैसे अनंतकाल से चली आ रही थी. उनको मैं पचास साल से जानता था? या हजार बरसों से? पता नहीं. पहली बार उनसे मेरी मुलाकात 1960 के दशक की शुरुआत में हुई. प्री डि ला क्रिटीक अवार्ड जीत चुके एस.एच. रजा उनके शो में आए थे और हम सब जानना चाहते थे कि यह स्थापित कलाकार क्या सोचता है. सतीश ने रजा को वहां घुमाने का ब्यौरा दिलचस्प ढंग से बयान किया. 'वे पहली पेंटिंग पर पहुंचे, और...' सतीश ने अपने होंठ उसी तरह सिकोड़े जैसे रजा नापंसदगी में फुसफुसाती आवाज निकालते हुए सिकोड़ते थे—''दूसरी पेंटिंग पर वे थोड़ा पिघले और 'हुं...हुं' की भंगिमा में हल्की-सी गर्दन हिलाई. तीसरी पर आए, 'ऐ गल हुई!' चीख पड़े.'' अब हम बात कर रहे थे!

उनमें हंसने-हंसाने की गजब की क्षमता थी. मैं भी पंजाबी था. उनकी सुनने की कमजोरी से तालमेल बिठाने का धैर्य भी मुझमें था. पंजाबी उनकी पहली भाषा थी और हम हंसी-मजाक करते, एक-दूसरे की बखिया उधेड़ते. वे कहते, ''तू बड़ा बदमाश है!''

हम जब बात करते थे तो उसमें न फुसफुसाहट होती और न आधे-अधूरे स्वर. वे सीधे और बेलाग बोलते—यही उनकी पहचान थी. ब्रश के काम करने के तरीके पर निर्भर अमेरिकी ऐक्शन पेंटरों के उलट सतीश ने बहुत मेहनत और संकल्प के साथ चित्रकला सृजित की. उन्होंने ऐसी शैली विकसित की, जो खुली हुई थी और बड़ी भी.

वे कलाकारों के उस दबदबे वाले गुट से अलग थे जो अंतर्मुखी अनुभूति को पाल-पोस रहा था और उन दिनों के खासकर पेरिस के चलन का पिछलग्गू था. 1952 में पिकासो और तमाम फ्रांसीसी चित्रकारों की बजाए, सतीश ने मेक्सिको जाने और म्यूरलिस्ट डिएगो रिवेरा और डेविड अल्फारो सिक्वेरोज के साथ काम करना तय किया. उनके नजरिए में आसपास के लोग और आजादी की लड़ाई के नायक अहमियत रखते थे.

सतीश की सोच यह भी थी कि पेंटिंग सिर्फ ड्रॉइंग रूम के लिए न हो. पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने भित्तिचित्र बनाए. दिल्ली के बेल्जियम दूतावास में स्थापत्य की परियोजना सरीखे भारी-भरकम प्रोजेक्ट हाथ में लिए. उन्होंने जगहों को जिस तरह तराशा,

दंटीप सिंह

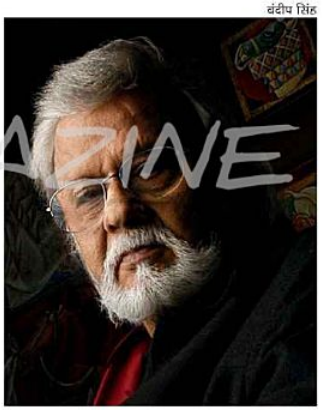

मुझे हैरत होती थी कि एक पेंटर तीसरे और चौथे आयामों के बारे में भला कैसे सोच पाता है! वे कहते थे, ''बड़ा आसान है. तू भी कर सकता है.''

वह देखकर मैं चकित था. मैं हैरान रह जाता था कि एक पेंटर तीसरे और चौथे आयामों के बारे में कैसे सोच पाता है. वे कहते थे, ''बड़ा आसान है. तुम भी कर सकते हो.'' मैं जानता था कि मैं नहीं कर सकता. मगर एक चीज मैंने उनसे जरूर सीखी कि बड़े आकार-प्रकार से, विशाल जगह से और भारी-भरकम विचारों से खौफ न खाएं, इन्हें लंबे वक्त में पूरा करना होता है.

सतीश ने सिरैमिक्स में भी महारत हासिल की. मुझे याद है, एक वक्त जब वे बहुत बीमार थे, मैं उन्हें देखने गया. वे बिस्तर पर लेटे थे, तमाम रंगों और उनकी परतों के बारे में ढेरों किताबें उनके चारों ओर फैली थीं. वे इन्हें पढ़ते और तरीके—मसलन, सही चमक हासिल करने के लिए हीटिंग और टाइमिंग वगैरह—लिख लेते. उन्होंने कुछ शानदार रंग रचे. कुछ मेरे पास हैं, एक टेबल, एक टी सेट आदि. उनकी बेटियां, या उनकी पत्नी किरण मदद करती रही होंगी. वे किरण से बहुत ज्यादा, गहरा प्यार करते थे—और वे ही सब कुछ संभालती थीं. जब वे सत्तर से ऊपर थे और सुनने की क्षमता वापस लाने के लिए उनका ऑपरेशन होना था, उन्होंने मुझसे कहा कि वे बस किरण की आवाज सुनना चाहते थे. खूबसूरत शादी थी उनकी.

उर्दू शायरी का उनका ज्ञान भी असाधारण था. उन्होंने तैरते हुए कुत्तों की मेरी एक तस्वीर देखी और फौरन फैज अहमद फैज की एक कविता कुत्ते का जिक्र किया. यही नहीं, इसे उन्होंने मेरी स्केचबुक में अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में उकेर भी दिया. वे शिष्ट और सजीले थे, पहनावे में भी.

सतीश ने मेक्सिको भित्तिचित्रकारों के साथ काम करते वक्त वह तरीका सीखा जिसका इस्तेमाल वे पेंटिंग को पूरी तरह मजबूत बनाने के लिए करते थे. मेरे पिता ने उनसे एक पेंटिंग खरीदी, जो बरसों मेरे पास रही, पर उसे रत्ती भर नुक्सान नहीं पहुंचा. यह भूरी और कम चौड़ी है और इसमें कृष्ण और अर्जुन को रणभूमि में दिखाया गया है. इसमें आकृतियों का एक पर्दा है जो नीचे से ऊपर तक लटका है—इसके आर-पार झांककर ही आप देख सकते हैं कि असल में क्या चल रहा है. उसमें पेंट और मिश्रित पदार्थों को भीतर से इतनी मजबूती से लगाया गया है कि आप इसे रगड़ें, चाहे जो करें, पर इसे मिटा नहीं सकते. यह पूरी तरह उनके चरित्र, उनकी फितरत की तरह है—अभेद्य.

—सोनल शाह से बातचीत के आधार पर

अब नए प्लेटफॉर्म पर नायिका

अभिनेत्री **मनीषा कोइराला** खुश हैं कि अब उन्हें स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रतिभा आजमाने का मौका मिल रहा और चुनने की आजादी भी

अतुल के.एस./गेट्टी इमेजेज

● *मस्का* में ईरानी कैफे की मालकिन का किरदार करने में सबसे मुश्किल क्या लगा?
गालियां देना. मेरी जिंदगी में ऐसी नौबत कभी नहीं आई कि यह सब करना पड़े. पहली बार मैंने यह सब किया. लेकिन वह किरदार का हिस्सा है और आपको वह सब ठीक से करना होता है.

● सबसे अच्छा बन मस्का कहां खाया?
मुंबई में क्यानी'ज के यहां. रात में दुकान बंद हो ही रही थी कि हम पहुंच गए और फारसी जानने मेरे कोच की गुजारिश पर हमें अंदर जाने दिया गया.

● *मस्का* नेटफ्लिक्स के साथ आपका तीसरा प्रोजेक्ट है. क्या इस प्लेटफॉर्म ने आपको एक नई शुरुआत दी है?
एब्सोल्यूटली. कैंसर के उपचार के दिनों में मैं वर्जीनिया में नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्रीज देखती रहती थी. आंटी ने सब्स्क्राइब कर रखा था. इसका सेट-अप बेहद प्रोफेशनल है. लोगों की शिकायत है कि इसके लिए पहले अच्छी-खासी लिखापढ़ी करनी पड़ती है लेकिन उससे सबकी सुरक्षा पुख्ता हो जाती है. उसमें एक तरह की नई ऊर्जा है. अभी तक इसका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है.

● काम वाला माहौल निश्चित रूप से नब्बे वाले दशक से अलग ही होगा...
उन दिनों तो मैं फिल्म पर फिल्म किए जा रही थी. मशीन की तरह. पर वह रूटीन बन गया था, सो अटपटा नहीं लगता था. कई दफा तो स्क्रिप्ट भी नहीं होती थी. अब मुझे चुनाव की अहमियत समझ आ गई है. अब मुझे पता है कि क्या करना है. खराब फिल्म करने की बजाए बागवानी, योग और ध्यान में समय लगाती हूं.

—सुहानी सिंह

MAGAZINE KING